हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 07 फरवरी, 2019 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

07-02-2019/1100/SS-YK/1

प्रश्न संख्याः 842

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितने भी हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े मेले, चाहे शिमला का समर फैस्टिबल है, चाहे मंडी की शिवरात्रि है, चाहे हमारा कुल्लू का दशहरा है, चाहे चम्बा का मिंजर मेला है, इस तरह के बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें करोड़ों रुपये इकट्ठे किये जाते हैं परन्तु इन पैसों को तरीके से खर्च नहीं किया जा रहा है और इसका वार्षिक कोई ऑडिट भी नहीं हो रहा है। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जो यह पैसा सरकारी तंत्र के द्वारा पब्लिक से इकट्ठा किया जा रहा है, इसका हर साल ऑडिट हो?

दूसरा, इसमें जितने भी कलाकार आते हैं उसमें स्थानीय कलाकारों को मामूली-सा पैसा दिया जाता है जबकि बड़े-बड़े कलाकारों पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है। क्या आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई ऐसा नियम बनायेंगे कि किस हिसाब से कलाकारों को पैसा देना है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी ने प्रश्न पूछा है मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और स्वाभाविक रूप से मेलों का आयोजन करना हमारी संस्कृति के लिए आवश्यक है। उसके साथ-साथ में इन आयोजनों को सरकार भी ठीक प्रकार से व्यवस्थित (मैनेज) करे, यह भी बहुत आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न के हिसाब से इन्होंने एक जानकारी चाही है। हमारे कुछ मेले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हैं। कुछ मेले हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी हैं। उसके साथ-साथ बहुत संख्या ऐसी भी है जो जिला स्तर पर मेले मनाये जाते हैं। जिला स्तर के मेले घोषित हुए हैं।

7.2.2019/1105/केएस/वाईके/1

जो बड़े मेले होते हैं उनमें लोगों से जो आय होती है, वह ठीक प्रकार से खर्च हो, यह सभी की चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम अन्तरराष्ट्रीय मेलों की बात करें तो हमारा कुल्लू का दशहरा ओर रेणुका का मेला, ये दो अन्तरराष्ट्रीय स्तर के मेले हैं। हमारे 6 राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं, 19 स्टेट लैवल के और 56 जिला स्तर के मेले हैं । कोशिश तो यही होती है कि इन मेलों के आयोजन में जो आय होती है, वह ठीक प्रकार से खर्च हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार हमेशा मोनिटर भी करती है । जैसा नेगी जी ने कहा है कि उसमें ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो खर्चा होता है, वह रिकॉर्डिड होता है। उसमें उस प्रकार का मैकेनिज्म ऑलरेडी बना हुआ है। इतना जरूर है कि उसमें गलत तरीके से खर्च न हो, फिजूलखर्ची न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से हमेशा प्रयत्न किए जाते हैं। जहां तक आपने ऑडिट की बात की, लोकल स्तर पर जहां ये मेला होता है, उसके ऑडिट की व्यवस्था पहले से ही है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कलाकारों के बारे में बात की कि जो बड़े कलाकार आते हैं उनको ज्यादा पैसा दिया जाता है और छोटे कलाकारों को कम पैसा दिया जाता है। हमने इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, कुछ कलाकार जो किसी नाम की वजह से बड़े बन गए, वे उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि जो हमारे हिमाचल के स्थानीय कलाकार हैं, जो हमारी लोकल फ़ोक को भी प्रमोट करते हैं और जो यहां की लोकल भाषा में गीत गाए जाते हैं, उस धरोहर को बचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है,उनके लिए सुनिश्चित किया है कि जो बड़े मेले होते हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर तथा जिला स्तर के मेलों में स्थानीय कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा समय और प्राथमिकता मिले। लेकिन उसके बावजूद माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की आवश्यकता भी महसूस होती है कि लोग अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी सुनना चाहते हैं। अगर हमारे देश का

कोई आर्टिस्ट लोगों का मनोरंजन करने के लिए यहां आता है तो स्वभाविक रूप से यह लोगों की भी मांग होती है और मनोरंजन की दृष्टि से भी यह आवश्यक लगता है। हमेशा जो बड़ा मेला होता है उसमें हमारा कार्यक्रम शाम को लगभग 8 बजे से शुरू हो जाता है। शाम को सांस्कृतिक संध्या शुरू हो जाती है उसके बाद दस बजे तक वह कार्यक्रम चलता है और 9 बजे तक स्थानीय कलाकार उसमें हिस्सा लेते हैं। जो बड़े कलाकार आते हैं, वे थोड़े वक्त के लिए आते हैं और थोड़ी देर के लिए परफोर्म करते हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हम लोगों से भी इस बात की जानकारी लेते हैं कि कौन सा कलाकार बुलाना चाहिए और जब मेला कमेटी बैठती है तो उसमें भी इस बात को ले कर चर्चा होती है कि कौन आर्टिस्ट बुलाना चाहिए और वहां पर यह तय किया जाता है कि इस आर्टिस्ट को बुलाया जाए। जब उस आर्टिस्ट के साथ बात होती है तो वह एक नाइट का 25 लाख रुपये मांगता है। एक घण्टे की परफोर्मेंस के 20, 25 और 30 लाख रुपये मांगतजे हैं और कुछ आर्टिस्ट तो 40 लाख रुपये तक की मांग करते हैं। वह हमारे लिए सचमुच चिंता का विषय बनता है लेकिन

7.2.2019/1110/av/ag/1

फिर भी जितना कम किया जा सकता है तो बड़े आर्टिस्ट का खर्चा भी कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस बात की भी आवश्यकता होती है कि बड़े कलाकारों को भी हिमाचल में आकर लोगों का मनोरंजन करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए यानी इसमें संतुलन बनाने की बात है। यह निश्चित है कि हमारे जो अपने हिमाचल के आर्टिस्ट लोकल फोक को प्रमोट करते हैं और अच्छा परफोर्म करते हैं; उनके साथ तो कम्परोमाइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने स्पष्ट कहा है कि सभी मेलों में कलाकारों को प्राथमिकता के आधार पर काम देना चाहिए। हमारे जितने भी इस प्रकार के मेले होते हैं उनके लिए जो पैसा आता है उसके ऑडिट का प्रावधान है और इस बारे में मैं

पहले कह चुका हूं। उसके बाद आपने जो दूसरी बात कही कि बड़े कलाकारों के साथ-साथ हमारे लोकल कलाकारों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए तो हमने उसको भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आपने तीसरी बात यह कही कि हमारे हिमाचल के कलाकारों को कम पैसा दिया जाता है। उनको किसी को 15-20 हजार रुपये दिए जाते हैं और किसी को इससे भी कम राशि दी जाती है। **उसमें भी कलाकार के हिसाब से जो उनको कार्यक्रम में परफोर्म करने के लिए राशि दी जा सकती है, वह हम देने की कोशिश करेंगे।**

अध्यक्ष : कृपया ध्यान रखें, हम दो अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्नकर्ता और बाद में अन्य केवल दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका देंगे ताकि अधिक-से-अधिक प्रश्न निकल सकें।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से काफी संतुष्ट हूं। लेकिन आपने जो ऑडिट की बात कही है तो जिला स्तर पर मेला कमेटी के चेयरमैन जिलाधीश होते हैं और सब-डिविजन लैवल पर एस0डी0एम0 होते हैं। अगर इस बारे में इंटरनल ऑडिट होगा तो उसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी। इसलिए क्या आप कोई अन्य मैकेनिज्म विकसित करेंगे ताकि इस पर कोई चैक हो क्योंकि इनसे करोड़ों रुपये की राशि इकट्ठी हो रही है। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि वी0आई0पीज0 को ऑनर करने के लिए आप लाखों रुपये की राशि खर्च कर रहे हैं क्योंकि आप उत्तर में दर्शा रहे हैं कि शिमला में ढाई-तीन लाख रुपये की राशि केवल वी0आई0पी0 के ऑनर में खर्च की जा रही है। अगर कोई वी0आई0पी0 बुलाया है तो उसको एक मुमैंटो देना काफी होता है। इसके अलावा टोपी-शॉल इत्यादि देना तो फिजूलखर्ची होती है, तो क्या इसके ऊपर भी रोक लगाई जायेगी? मैं उत्तर में यह भी देख रहा हूं कि शिमला फैस्टिवल में एक लोकल आर्टिस्ट जिसकी आपने बहुत तारीफ की है, उसको केवल 5000 रुपये की राशि मिल रही है। बाहर से आने वाला कलाकार एक-डेढ़ घंटे में 12 लाख रुपये की राशि लेकर जा रहा है। क्या आप इसके लिए नियम बनायेंगे और इनको एक

सम्मानजनक राशि दी जायेगी क्योंकि हमारे लोकल कलाकार को दी जाने वाली 5000 रुपये की राशि तो कुछ भी नहीं है।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात से सहमत हूं कि फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए। मगर जैसे इन्होंने ऑनर करते वक्त टोपी-शॉल देने की बात की है तो इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी मेहमान का स्वागत करने की हमारी एक परम्परा रही है और मुझे लगता है कि स्थापित परम्परा को हमें मेंटेन भी करना चाहिए। मगर अन्य चीजों पर जो लेविशली खर्च करने की बात आई है तो हमने उसके लिए कहा है कि कम-से-कम खर्च किया जाये। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे हिमाचल के अच्छे कलाकारों को अभी तक दी जाने वाली राशि बहुत कम है। यह प्रशासन तय करता है कि किस को कितना देना है क्योंकि अमुक कलाकार को भी अपनी पूरी टीम के साथ आना पड़ता है और टीम के साथ परफोर्म करने के लिए आना-जाना-रहना; इन सारी चीजों को लेकर के परेशानी तो होती है। लेकिन फिर भी हम इसके लिए कोई मैकेनिज्म विकसित करने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल के लोकल कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जितना उनका आने-जाने व रहने का खर्चा होता है उनको कम-से-कम उतनी राशि तो मिले। **मेरे कहने का मतलब यह है कि उनका कम-से-कम अपना खर्चा तो निकलना चाहिए, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे**।

07/02/2019/1115/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

आपने जो ऑडिट की बात कही है और आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है, ये करोड़ों रुपया इकट्ठा करने वाले हमारे 2-3 ही मेले हैं। जैसे कुल्लू का दशहरा, मण्डी की शिवरात्रि, चम्बा का मिंज़र, रेणुका का मेला, रामपुर की लवी और किन्नौर का मेला। बाकी जगह तो मेले के संचालन के लिए जो खर्चा निकालना होता है, वह भी पूरा करना कठिन हो जाता है। उसके लिए इधर-उधर से मदद लेकर पूरा करने की कोशिश होती है।

फिर भी आपने जो सुझाव दिए हैं, ये महत्वपूर्ण सुझाव हैं, अच्छे सुझाव हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि इन सुझावों पर अमल करने की स्थिति में आगे बढ़ सके।

श्री विनय कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि कुल्लू का दशहरा और रेणुका का मेला दो अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि भाषा एवं संस्कृति विभाग जो इन मेलों को अनुदान देता है, वर्ष 2017 व 2018 में भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा कितना पैसा रेणुका मेले के लिए और कितना पैसा कुल्लू दशहरे के लिए दिया गया?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए सरकार की ओर से पैसों को देने की बात है, वह स्थाई है और वह 2.00 लाख रूपये दिए जाते हैं। यदि आप रेणुका मेले की बात करें तो वर्ष 2018-19 में वहां पर 84,11,826/- रुपये इकट्ठे हुए और कुल्लू दशहरे में यह राशि ज्यादा इकट्ठी हुई है। वहां पर मु0 6,74,78,711/- राशि इकट्ठा हुई है। अंतर्राट्रीय मेलों के लिए 2.00 लाख रुपये की स्थाई व्यवस्था की गई है और उसके अंतर्गत ये राशि इन मेलों को दी गई है।

श्री सतपाल सिंह रायजादाः माननीय अध्यक्ष महोदय, 'ऊना उत्सव' को पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने 'स्टेट फेयर' घोषित किया था। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ऊना उत्सव बंद कर दिया जाता है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसके बारे में विचार करेंगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है। आप शायद 'सोमभद्रा फ़ेयर' की बात कर रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार this fair has not been organized since 2016. 2016 में तो आपकी पार्टी की सरकार थी। इसके बाद ये मेला आज तक वहां पर आयोजित नहीं हुआ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की

सरकार की बात है, हम तो बहुत धार्मिक आदमी है और अपनी संस्कृति को हमेशा बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद ये मेला बन्द नहीं किया गया।

07-02-2019/1120 /NS/DC /1

प्रश्न संख्याः 1194

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 33 के0वी0 सब-स्टेशन का लगना 24 पंचायतों में से 18 पंचायतों को प्रभावित करता है। हमारी सरकार ने इस संवेदनशील विषय को बड़ी तवज्जो देकर किया था and that is why I have put this question. I am grateful to the Hon'ble Minister for assuring to complete its work till March 2019.

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिल गया। माननीय सदस्य, श्री सुरेश कुमार कश्यप जी आप क्या पूछना चाहते हैं? यह प्रश्न तो इनके विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का कुछ एरिया सोलन डिवीज़न में ही पड़ता है।

अध्यक्षः श्री सुरेश कुमार कश्यप जी आप अपनी सप्लीमैंटरी पूछें।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का कुछ एरिया सोलन डिवीज़न के अंडर आता है। विशेष रूप से ओच्छघाट सब-डिवीज़न और इस सब-डिवीज़न में कोटला-पंजोला पंचायत आती है और वहां पर अगर हम कोई भी कागज़ बिजली से संबंधित देते हैं तो सोलन डिवीज़न वाले इस क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र सोलन डिवीज़न के अंडर आता है। बार-बार आग्रह करने के बाद भी वहां पर लकड़ी के बहुत सारे पुराने खंभे हैं, जो अभी तक बदले नहीं गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या आप इस एरिया को सोलन डिवीज़न से निकाल कर राजगढ़ इलैक्ट्रिकल डिवीज़न में सम्मिलित करेंगे? क्योंकि इसका थोड़ा-सा एरिया सोलन में पड़ता है और इस एरिया की अनदेखी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी इस बारे में आश्वासन चाहता हूं।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं था। फिर भी माननीय सदस्य ने कहा है तो हम इसको एग्ज़ामिन कर लेंगे। जहां तक इन्होंने खंभे बदलने के लिए कहा है तो इन खंभों को बदल देंगे।

प्रश्न संख्याः 1195

श्री अरूण कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, वह अधूरी है। वन विश्राम गृह, मंला वर्ष 1962-63 में बना है। इस विश्राम गृह के निर्माण में पत्थर तथा मिट्टी का प्रयोग किया गया है। इसकी दीवारें अंदर से चिकनी मिट्टी की बनी हुई हैं और बाहर से इसमें पलस्तर कर दिया गया है। अंतिम बार वर्ष 1997-98 में इस विश्राम गृह की मरम्मत की गई थी और इसके बाद आज दिन तक रंग-रोगन के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फोटो खिंच कर इसकी तस्वीर भी साथ लाया हूं। यह विश्राम गृह मेरे विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र विश्राम गृह है, जो वन विभाग से संबंधित है। इस विश्राम गृह की दूरी श्री चामुंडा देवी से 4 किलोमीटर है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी इस विश्राम गृह से फायदा होता है और यह नेशनल हाईवे के बीच में पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस विश्राम गृह का पुनः निर्माण करने के लिए बज़ट का प्रावधान करेंगे?

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि यह विश्राम गृह वर्ष 1962-63 में बना था और यह परंपरागत कांगड़ा स्टाईल मिट्टी और गारे से बना है। अभी तक इस विश्राम गृह में कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। वर्तमान वर्ष 2019-20 के लिए रोड एंड बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया है। माननीय सदस्य ने इसको ठीक करने के लिए कहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसमें तीन कमरे और एक ड्राईंग रूम है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इस विश्राम गृह को सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे और जितना अच्छा बना सकते हैं, इसको बनाने की कोशिश करेंगे तथा धन की कोई कमी आड़े नहीं आएगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आपको बधाई हो।

07.02.2019/1125/RKS/DC-1

<u>प्रश्न संख्याः1196</u>

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, हर टैम्पल ट्रस्ट से महीने में कितना चढ़ावा आता है वह सारी सूचना उपायुक्त महोदय के माध्यम से संबंधित विभागीय सचिव के पास पहुंच जाती है। अब यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और इस सूचना को विभागीय सचिव के कार्यालय से माननीय मुख्य मंत्री के कार्यालय तक पहुंचने में इतना समय लग जाए यह ठीक नहीं है। सरकार द्वारा टैम्पल ट्रस्ट का 15 प्रतिशत और शराब की प्रति बोतल में गौसदनों के लिए पैसा देने की बात कही गई थी। साल खत्म होने को है लेकिन इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। जबकि बजट सत्र में इसका लेखा-जोखा होना चाहिए था। मुझे हैरानी इस बात की है कि कितने गौसदन बने इस प्रश्न का उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। यह प्रश्न दो दिन पहले लगा था और इसकी सूचना भी नहीं दी जा रही है। कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितने गौसदन बने, वह पैसा कहां खर्च किया गया इसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी को नहीं मिल रही है यह बड़ी हैरानी की बात है।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी लेकिन सूचना एकत्रित करने में कई बार वक्त लग जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी सूचना एकत्रित करने में पांच साल का कार्यकाल निकल गया परंतु सूचना एकत्रित नहीं हुई। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं और इसके लिए विभाग को आदेश दिए हैं कि यह सूचना तुरंत एकत्रित की जाए। जो आयोग के गठन की बात है, आयोग का गठन कर दिया गया है और इसका काम शुरू हो गया है। विभाग ने कुछ चीजों की जानकारी प्राप्त कर ली है लेकिन कुछ चीजों की जानकारी अभी तक अपेक्षित है इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी सूचना दी जाए वह ठीक हो और पूर्ण हो। मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहूंगा कि यह पूर्ण सूचना आपको जल्द-से-जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। हम इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है और इस आयोग के गठन के पीछे हमारी मंशा भी यही है कि जिस गाय को हम मां कहते हैं उस फर्ज को भी हमें अदा करें। हमने हिमाचल प्रदेश में तीन जगह

Cow Sanctuary खोल दी है। लेकिन जो मंदिर से 15 प्रतिशत और एक्साइज से एक रुपये प्रति बोतल के हिसाब से पैसा आने की बात कही है, यह एक विस्तृत सूचना है और जैसे ही यह सूचना प्राप्त होगी वैसे ही यह सूचना आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी।

<u>प्रश्न संख्याः 1197</u>

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, जौ मैंन बस सेवा के लिए आग्रह किया है इसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री के बल्ह प्रवास के दौरान की गई थी। सुन्दरनगर-हल्यातर जो बस चलती थी वह पूर्व सरकार के समय बंद कर दी गई थी। प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि निरीक्षण कमेटी द्वारा रोड का निरीक्षण करने के बाद ही पता चलेगा कि वहां पर बस सेवा शुरू की जाएगी या नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि इससे पहले भी उस सड़क पर बस चलती थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बस सेवा को कब शुरू किया जाएगा?

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने उस सड़क पर बस चलाई थी इसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। उस पर ज्वाइंट इंस्पैक्शन कमेटी की क्या रिपोर्ट लगी थी लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ज्वाइंट इंस्पैक्शन कमेटी ने उसको अप्रूव नहीं किया था। ।

07.02.2019/1130/बी0एस0/ए0जी0-1

और मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, निश्चित रूप से वह पूरी होगी। **हम संयुक्त निरिक्षण कमेटी के द्वारा इस सड़क का निरिक्षण करवाएंगे। उसके पश्चात चालक और परिचालक की उपलब्धता के आधार पर हम प्राथमिकता के तौर पर इस बस को चलाएंगे।**

प्रश्न संख्याः 1198

श्री सतपाल सिंह रायजादा (ऊना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या वी. के. वी. एन. वाई. का दायरा बढ़ाया जाएगा ? हम वी. के. वी. एन. वाई. की गाईड लाइन न0 19 के अनुसार वाई-फाई का प्रावधान कर सकते हैं तो क्यों न इसका दायरा बढ़ा कर सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रक्षते हुए सी.सी.टी.वी. कैमराज लगाने का प्रावधान किया जा सकता है? इस संबंध में पहले भी मेरा प्रश्न रहा है। उसमें भी हम जिम के लिए कमरा तो बना सकते है। लेकिन उसके अंदर जिम का सामान देने के लिए विधायक पैसा नहीं दे सकते हैं। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आज के समय में पंचायतों को जब सड़कों व रास्तों के निर्माण तथा अन्य कार्यो के लिए अन्य स्रोतों से भी पंचायतों को बहुत सारा पैसा आता है । जो हमारा विधायक निधि का पैसा है उसे हम सी.सी.टी.वी के लिए भी दे सकें और जो कमरा होगा उसमें यदि जिम के यंत्र नहीं उपलब्ध होंगे तो यह कार्य कैसे आगे बढ़ेगा ?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा है उसमें हमने बड़ी डिटेल में जो परमिसिबल एक्टिविटी हैं और जहां हम इस पैसे को दे सकते हैं उनकी संख्या 20 हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विधायक निधि को खर्च करने का दायरा कभी इससे भी कम था। हम 7-8 स्कीम्ज के लिए ही पैसा दे सकते थे। सुझाव आने के साथ-साथ हम आगे बढ़े हैं। इसके बाद बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। उस दृष्टि से माननीय सदस्य का भी सुझाव आया है इस पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे । जहां तक आपके पश्न का संबंध है उसके अनुसार सामुदायिक भवन के निर्माण तथा वाई-फाई लगाने के लिए केवल नॉन रैकरिंग खर्चे का प्रावधान है। उसके बाद माननीय सदस्य ने धार्मिक स्थानों के बारे में कैमरे लगाने की बात कही है । इस बारे में यह

कहना चाहूंगा कि सी.सी.टी.वी. एक बार तो लगाने की बात समझ में आती है परंतु इसके रख-रखाव और मोनिटरिंग की व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसकी मरम्मत की आवश्यकता रहेगी उसे कैसे किया जा सकता है? यह एक अलग तरह का विषय है। इसलिए असैस्ट के लिए विधायक निधि का प्रावधान बहुत कड़ा है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं कि युवक मंडल के लिए हम भवन का पैसा तो दे रहे हैं लेकिन उसी भवन में आप जिम लगाना चाहें तो उसके लिए विधायक पैसा नहीं दे सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अच्छा सुझाव हमारे सामने आया है इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

07.02.2019/1135/DT/HK -1

अगर यूथ जिम में जाता है और शारीरिक रूप से इस तरफ ध्यान देता है तो मुझे लगता है कि वो प्रिमिसिबल एक्टविटी में विचार करने लाईक बात है और निश्चित रूप से इस पर हम विचार करेंगे। जहां तक आपने प्रिमिसिबल एक्टविटीज़ को बढ़ाने की बात कही है, समय-समय पर माननीय विधायकों की और से सुझाव आए है और उन सुझावों को हमने शामिल किया है और शामिल करने के बाद फिर उनको हम प्रिमिसिबल एक्टिविटी में जोडते रहे है । बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं थी उनको शामिल किया गया है और अभी भी इसमें सभावनाएं विद्यमान है । जहां भी इसमें गुंजाइश होगी तो निश्चित रूप से इसमें हम विचार करेगे बशर्ते विधायक निधि में खर्च ठीक प्रकार से हो, उसमें विधायक निधि का दुरूपयोग होने की सभावना न हो और जो खर्च करे उस खर्च के माध्यम असैस क्रिएट हो यह भी मुझे लगता की बहुत आवश्यक है इसपर विचार करेगे ।

श्री सतपाल सिंह रायजादा ऊना: अध्यक्ष महोदय ,मैं मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना भूल गया, इसमें धार्मिक स्थल , मंदिर के लिए जैसे पैसे की बात है, मैं अपने ऊना क्षेत्र की बात करूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र ऊना में बहुत सी जगह ऐसी है जहा सामुदायिक भवन बनाने के लिए जगह नही है लेकिन मंदिर के पास जगह है ।

सामुदायिक भवन बनाने के लिए है जब हम पैसा देते है तो क्योंकि जगह मंदिर के नाम है तो वहां पर हम सामुदायिक भवन नही बना पाते हैं जबकि वह बनना पंचायतो के थ्रू ही होता है या एनएसी के थ्रू होता है वही उसको तैयार करेगी या लोक निर्माण विभाग तैयार करेगा हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, हमारा तो सिर्फ पैसा जाना होता है । क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर मंदिर की जगह है और वहां पर सामुदायिक भवन बनाना है तो क्या उसके लिए भी हम अलॉटमैन्ट कर सकते हैं?।

मुख्यमत्रीः अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक भवन और सराय भवन यह दोनो प्रिमिसिबल एक्टीविटी में शामिल किया जा सकता है। 20 हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जहा विधायक निधि से हम पैसा दे सकते है । लेकिन जहां आप इस बात को पूछ रहे है कि मंदिर की जगह है और मंदिर की जगह में सामुदायिक भवन बनाना है अगर मंदिर को एतराज नहीं है मंदिर कमेटी ज़मीन देती है तो पैसे को देकर के सामुदायिक भवन बना सकते है और इस प्रकार से बना भी रहे है।

अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मंदिर की प्रोपटी माईनर है that cannot be transferred in the name of the Government.

मुख्यमत्री : हां, यह एक टैक्निकल इशू इसमें जरूर है। उसमें सारी चीजों को लेकर विचार करेंगे आपका यह सुझाव आया है। दूसरी जगह जहां इस प्रकार मंदिर की जगह नहीं है, सरकारी जगह है वहां सामुदायिक भवन या सराय भवन निर्माण करते हैं

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,यह जो सी.सी.टीवी. के बारे में अभी शिक्षा बोर्ड ने एक निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में जितने भी परीक्षा केन्द्र हैं अगर वह 6 मार्च से पहले परीक्षा शुरू होने से पहले यह सी.सी.टीवी कैमरे नही लगाएंगे तो यह सारे परीक्षा केन्द्र को रद्द कर देंगे तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि 6मार्च से पहले-पहले हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूलो के जहां पर परीक्षा केन्द्र है वहां पर सी.सी. टीवी के लिए धन का प्रावधान करेंगे?

श्री विनोद कुमार (नाचन): माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसे पहले यह होता था जहां पर मंदिर के नाम से जगह होती थी वहां उस जगह पर हम सामुदायिक भवन या सराय बना देते थे क्योंकि मंदिर के नाम से जगह होती थी अब दिक्कत यह आ रही है कि जमीन सरकार के नाम ट्रांसफर करनी पड़ रही है । दूसरा, जहां पर सामुदायिक भवनों या मंदिर में सराय के निर्माण के लिए हमने पैसा दिया है किन्ही कारणों से वह पूरा नहीं हुआ है अब हम उसको पूरा करने के लिए जो पैसा दे रहे है तो यह जमीन आपको सरकार के नाम से करवानी पड़ेगी तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जिस तरह से पहले होता था कि सराय अगर मंदिर में बनानी है मंदिर के नाम से जमीन है तो उसी तरह से अभी भी होना चाहिए यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा। श्री आर0जी0 द्वारा जारी

07/02/2019/1140/RG/YK/1

प्रश्न सं. 1198---क्रमागत

श्री विनोद कुमार के पश्चात

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर तो दे दिया कि सुझाव आया है, उस पर विचार करेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने इसमें काफी विस्तार से अपनी बात कह दी है। जहां तक ऐडीशनलिटी की बात आ रही है, यह सच में एक विषय है। किसी सराय भवन या कम्युनिटी सेन्टर या किसी भी काम के लिए हम जितना पैसा पहले दे रहे हैं, उसमें ऐडीशनलिटी एक सीमा तक दी जा सकती है। कई बार क्या होता है कि जितना पैसा हमने किसी सराय भवन के लिए दिया है, जैसे तीन लाख रुपये दिया है तो दूसरी बार भी ऐडीशनलिटी तीन लाख रुपये अर्थात सौ प्रतिशत देने की बात आ जाती है। तो यह व्यवहारिक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि विधायक निधि के किसी काम में कुल कितना पैसा खर्च होगा या किसी भी काम का कम-से-कम एक प्रिलीमिनेरी ऐस्टीमेशन होना चाहिए। जब हमने पहली बार पैसा स्वीकृत कर दिया, तो उसके बाद उसको पूरा करने के लिए थोड़ा पैसा उसमें हम दे सकते हैं। शायद हम 20 या 30 प्रतिशत ऐडीशनलिटी के रूप

में हम पैसा दे सकते हैं लेकिन कई स्थानों पर फिर से ज्यादा पैसा मांगने की बात आती है तो वह व्यवहारिक नहीं हो पाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात जो माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी ने कही है तो इस बात पर **हम विचार करेंगे। जैसा मैंने कहा है कि मंदिर की जगह सरकार के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है, यह रैवेन्यू में एक टैकनीकल इशु है जिसके कारण दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी यदि सरकारी भूमि पर इस प्रकार से होता है तो वहां पर इस प्रकार की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो सुझाव दिए हैं, इन पर जो किया जा सकता है, वह हम करेंगे।**

श्री राम लाल ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जिम के लिए पैसा देने के बारे में कहा है, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो विधायक निधि का पैसा दिया जाता है उसका दुरूपयोग न हो। इसमें जो युवा सेवाएं एवं खेल विभाग है, उसमें consumable or non-consumable articles को खरीदने के लिए एक कमेटी बनी हुई है और सारे रेट्स अप्रूव्ड हैं। हर जिले में डी.वाई.एस.ओज़. हैं और वे खेल विभाग के अधीन काम करते हैं, विधायक निधि का पैसा हम उन अप्रूव्ड रेट्स के मुताबिक डी.आई.एस.ओज़. को दे दें, तो क्या वे आर्टिकल्ज खरीद कर युवक मण्डल को नहीं दिए जा सकते? मेरा निवेदन है कि क्या इस प्रकार का इन्तज़ाम माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, यह एक **अच्छा सुझाव है और उसमें इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। अगर रेट्स अप्रूव्ड हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई तकनीकी दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी युवक मण्डल को पैसे देने के बाद वह अपने आप जिम के लिए कहीं से सामान खरीदें तो निश्चित रूप से उसमें पारदर्शिता का विषय जरूर आएगा। अगर युवक मण्डल पैसे लेने के बाद अपने किसी माध्यम से सामान खरीदकर आ जाए, तो उससे अच्छा जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, यह बेहतर तरीका है। इसको लेकर निश्चित रूप से विचार करेंगे।**

प्रश्न सं 1199

श्री अनिरूद्ध सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि हर साल समाचार-पत्रों में किसी-न-किसी या सरकार के माध्यम से ट्रैफिक जाम की समस्या के बारे में समाचार छपता रहता है। यह समस्या बड़ी बसों के कारण भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भट्टाकुफर में बस अड्डे का निर्माण किया जाए या फिर ढली में जहां लगभग साढ़े तीन सौ मीटर लंबा स्थान परिवहन विभाग का है, वहां बस अड्डे का निर्माण किया जाए और पहाड़ की बसें वहां से चलाई जाएं। क्योंकि फोरलेन भी ढली तक आ रहा है। सरकार से मेरा यही निवेदन है क्योंकि बी.ओ.टी. पर यह निकाला गया था लेकिन किसी ने उसके लिए बोली नहीं लगाई। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भट्टाकुफर या ढली में बस अड्डा बनाया जाए।

07/02/2019/1145/MS/YK/1

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23/5/2001 को हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्ज ने एक मीटिंग करके यह कहा कि यहां पर लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से 11वें वित्त आयोग के द्वारा पैसा दिया गया था जिसमें से 6 करोड़ रुपये आ गए थे। उसके पश्चात 9 मई, 2007 को फिर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह निर्णय लिया कि यहां पर शिमला, करसोग और किन्नौर के लिए लोकल युनिट की जो बसिज हैं इनको ढली के लिए ट्रांसफर किया जाए। अतः 31 जुलाई, 2007 को उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वहां से इसको ट्रांसफर करने के लिए कहा। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद 7 रिकॉमेंडेशन्ज माननीय उच्च न्यायालय की एक कमेटी के द्वारा दी गई और फिलहाल जहां पर भूमि देखी गई थी, अभी तक वहां पर एच0आर0टी0सी0 की वर्कशॉप चल रही है। उसके बाद इस कमेटी की रिकॉमेंडेशन यह थी कि भूमि उपलब्धता और एच0आर0टी0सी0 के आर्थिक संसाधनों के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न संख्याः 1200

श्री मुलख राजः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे उत्तर काफी संतोषजनक है। मगर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इस रोड पर जो क्रॉसिंग है वहां ज्यादा ट्रैफिक रहता है। इस पुल के निर्माण की प्रक्रिया कब पूरी होगी? इसके साथ एक-दो रेलवे क्रॉसिंग और हैं जिनमें परयटकर-त्रेड़ खुरली सड़क और मझयाना रोड है। भविष्य में अगर इनके ऊपर भी रेलवे फाटक लग जाए तो इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर यह क्रॉसिंग बनती है तो इससे जो 15 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है उससे राहत मिलेगी।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया हुआ है। इस योजना की सी0आर0एफ0 के तहत परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र दिनांक 19-11-2015 द्वारा भेजी गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत पुराने समय से ये मसला वहां पर चल रहा है और वहां इसके कारण काफी दिक्कतें भी हैं। इसकी प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति अवर सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18-2-2016 द्वारा मु05.28 लाख रुपये की प्राप्त हुई थी जिसके अनुसार विभाग द्वारा वांछित राशि मु08,87,214.00/-रुपये XEN B&R(S&D) उत्तरी रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली के पक्ष में दिनांक 2-08-2017 को जमा करवाई गई थी। फिर उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, इसमें रिवाइज्ड ऐस्टीमेट मु06,45,04,271.00/-रुपये का दिनांक 26-4-2018 को प्राप्त हुआ और उसके अनुसार राशि को जमा करने के लिए मु0 5.81/- करोड़ रुपये की राशि Permissible Variation के साथ सेंट्रल रोड फण्ड के अंतर्गत उपलब्ध है। बाकी मु0 64.24/-लाख रुपये की राशि के लिए प्रक्रिया जारी है। जैसे ही यह धनराशि उपलब्ध होती है तो पूरी राशि जमा करवा दी जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम इसकी जल्दी-से-जल्दी ए0ए0 एण्ड ई0एस0 ले लेंगे।

7.2.2019/1150/जेके/एजी/1

और उसके बाद विभाग को कहा है कि इसको कुछ पैसा दे करके क्योंकि इसके कारण वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, हमने कहा है कि इसमें 2 करोड़ रुपये जारी करके काम की शुरूआत हो जाए और आने वाले समय में जल्दी-से-जल्दी कोशिश करें ताकि यह बन करके तैयार हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले लगभग डेढ़ सालों में यह बनकर तैयार भी हो जाएगा।

आपने दूसरा जो जिक्र किया है, उसकी डिटेल आप दे दें। क्योंकि ये मामले रेलवे मंत्रालय के साथ उठाने पड़ते हैं। इन छोटे-छोटे इशूज़ के लिए भी बहुत लम्बा प्रोसैस होता है। उसके बावजूद भी हम इन सारे मामलों को वहां पर उठाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कल ही बैजनाथ गया था। वहां पर एक नई शुरूआत हुई है। जो 164 किलोमीटर पठानकोट से जोगिन्द्रनगर की रेल है, उस सफ़र को पूरा करने में लगभग साढ़े सात घण्टे का समय लगता था। उसको कम करने के लिए हमने केन्द्रीय रेल मंत्रालय और केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के साथ मामला उठाया था। हम व्यक्तिगत रूप से भी उस सर्वे को एक बार देखने वहां गए थे। उन्होंने विभाग को आदेश दिए और उसका सार्थक परिणाम निकला। परिणाम यह निकला कि उसमें जो साढ़े सात घण्टे का सफ़र था वह पांच घण्टे पांच मिनट में पूरा होगा। उसकी एक शुरूआत हुई। पिछले कल हम विधिवत रूप से उस रेल की शुरूआत करके आए हैं और उसी के साथ उसमें और भी बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है।

प्रश्न संख्याः 1201

श्री राकेश सिंघा (ठियोग): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मैं समझता हूं कि सूचना एकत्रित करने में सरकार गम्भीर नज़र नहीं आ रही है और जो कार्रवाई करनी थी उस पर भी गम्भीर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी ज़वाब गम्भीरता से देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि केवल वर्ष 2018-19 की यह जानकारी है, इसमें जो फिगरज़ आए हैं, बहुत सीरियस हैं और ये सिर्फ हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले हैं। यह मुम्बई नहीं है, दिल्ली नहीं है, मद्रास नहीं है और कलकत्ता नहीं है। अगर हम किसान की आय को दोगुना करना चाहेंगे तो ये तथ्य कहते हैं कि यह इन्कम आधी होने वाली है। इसी वर्ष 2 करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों का फंसा हुआ है। अगर पीछे से देखेंगे तो कोई सैंकड़ों करोड़ है। जो प्रोक्लेम्ड अफैंडर्ज़ हुए, हमने सिर्फ 13 फीसदी अरैस्ट करवाए हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जो प्रोक्लेम्ड अफैंडर्ज़ कोर्ट से तय हुए कि हम सिर्फ 13 फीसदी को अरैस्ट कर सकें, वे 30 में से सिर्फ 4 केस हैं जहां हमने अरैस्ट किए? इसके क्या कारण है इसमें पुलिस की मिलीभगत तो नहीं है? दूसरे, इनको हम कब तक अरैस्ट करेंगे और इस पैसे को कब तक मुहैया करवा देंगे?

कृषि मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आदरणीय ठाकुर जय राम जी की सरकार इसके लिए चिंतित है। हमने 101 केसिज़ रजिस्टर्ड किए हैं। इससे पहले केसिज़ रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं और जो भी हमारे ध्यान में लाये गये हैं, जो भी एप्लिकेशन्ज हमारे पास आई हैं और जो भी सूचना हमारे ध्यान में आई है, हमने कोशिश की है। सच्चाई यह है कि जिन आढ़तियों द्वारा किसानों के प्रोड्यूस या प्रोडक्ट को खरीदा है, लगभग उनको 2 करोड़ 15 लाख के करीब धनराशि देनी है। हमने 30 लोगों के अंगेस्ट केस चलाए हैं और 4 लोगों को अरैस्ट भी किया है। श्री राकेश सिंघा जी की चिन्ता ठीक है परन्तु विषय यह नहीं है कि किसानों की आय को दोगुना होने में इससे हर्डल्ज़ पैदा होंगी। सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए

07-02-2019/1155/SS-AG/1

हमने समय-समय पर डिफरेंट मेज़र्स लिए हैं। हमने यह भी कहा है कि अगर आप लिस्ट देखें, आपका क्वैश्चन कोई टाइम बाउंड नहीं था लेकिन हमने पूरी रिपोर्ट दी है कि

शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने लोग हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट में 38 केसिज़ हैं और टोटल 101 केसिज़ हैं। यह चिन्ता आउट साइड यार्ड की है। जो हमारे मार्किटिंग यार्डस हैं, उसमें आढ़तियों का पैसा आ चुका है लेकिन आउट साइड यार्ड चिन्ता का विषय है। माननीय जय राम ठाकुर की सरकार बहुत जल्दी नियम/कानून लाने वाली है कि जो झोलाछाप आढ़ती लोगों की प्रोड्यूस लेते हैं उसके लिए कोई कानून बने, कोई व्यवस्था बने ताकि किसानों को उनके पैसे समय पर मिले। ऐसी हम योजना बनाने वाले हैं। मैं सिंघा साहब को बताना चाहूंगा कि 31 मार्च से पहले-पहले हम कोशिश कर रहे हैं, 30 आदमियों को नोटिसिज़ दे दिए हैं, पुलिस ने उनसे बात भी कर ली है और उन्होंने कहा है कि वे बहुत जल्दी पैसे देने वाले हैं। चार ऑफैंडर्ज़ लोगों को हमने अरैस्ट किया है। **बहुत जल्दी हम किसानों को पैसे दिलवायेंगे।**

श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो फिगर्ज़ यहां दिये हैं, मेरे चौपाल निर्वाचन क्षेत्र में ही 3 करोड़ से ऊपर-ऊपर किसानों का पैसा अभी तक आढ़तियों के पास फंसा हुआ है। यह फिगर सिर्फ वह है जो पुलिस में एफ0आई0आर0 हुई है। बहुत सारे केसिज़ ऐसे हैं जिनमें लोगों को चैक दिए गए लेकिन चैक में पैसा नहीं निकला। वे कोर्ट में गए। हजार से ऊपर केसिज़ ऐसे हैं जोकि कोर्टस में चल रहे हैं, जिनमें आढ़तियों ने चैक दिए थे और पैसे किसी को नहीं मिले। अगर यह पूरा स्कैंडल सामने आ जायेगा तो यह कम-से-कम 50 करोड़ रुपये से ऊपर जायेगा। इसमें कई सालों से सेब, टमाटर, गोभी और मटर वालों को पैसे नहीं मिल रहे। मैं आपको दो साल पहले की कहानी बताता हूं।

अध्यक्ष: बलबीर जी, कहानी मत बताईये। प्रश्न करिये अन्यथा प्रश्नकाल समाप्त होने का समय हो जायेगा।

श्री बलबीर सिंह वर्मा: सर, मैं शॉर्ट कट में बताता हूं। एक व्यक्ति पराला मंडी से एक-डेढ़ करोड़ रुपया का सेब लेकर भाग गया था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा और तीन महीने अरैस्ट करके रखा तथा उसका पूरा बायो डाटा निकाला तो पता चला कि वह वहां ठेले पर सेब बेचता था। परन्तु यहां से ठग कर डेढ़ करोड़ रुपये के सेब ले गया। इस प्रकार बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं और हमारे किसान को ठगकर ले जा रहे हैं। पैसा किसी को

नहीं मिल रहा। अगर आप इसकी पूरी जानकारी लेंगे तो यह 50 करोड़ से ऊपर का स्कैंडल होगा।

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। बहुत से आढ़ती ऐसे हैं जिनके अड्रैसिज़ हमें हिमाचल प्रदेश में नहीं मिले। ये बाहर के आढ़ती हैं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारे पास 101 केसिज़ हैं वे सिर्फ एफ0आई0आरज़0 लौज़ हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो बात इन्होंने कही है, हो सकता है कि ऐसे केसिज़ हमारे ध्यान में न हों क्योंकि किसानों से डायरेक्ट प्रोड्यूस खरीदकर लोग ले गए हैं। वे आढ़ती भी नहीं हैं। हम सब्जी मंडी के अंदर/बाहर लाइसैंसिज़ देते हैं। सब्जी मंडी के बाहर जो लाइसैंसिज़ देते हैं वे डायरैक्ट किसान से प्रोड्यूस खरीद रहे हैं। इसलिए हम कानून लाने की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा नियम/व्यवस्था बने ताकि लोग किसानों को ठग न सकें। हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं।

अध्यक्षः अंतिम सप्लीमैंटरी श्री राकेश सिंघा जी पूछेंगे।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग)ः पहली बात यह है कि मंत्री महोदय आप गलत जवाब दे रहे हैं। आपने खुद ए0पी0एम0सी0 कहा है। ये वाले केस ए0पी0एम0सी0 के अंदर हैं। ए0पी0एम0सी0 से बाहर के नहीं हैं। इसलिए छापामार नहीं हैं और छापामार है ही कोई चीज़ नहीं है। पूरा हिमाचल प्रदेश आपके कानून के मुताबिक मंडी है। वह सिर्फ एक यार्ड है, एक है मार्किट, सारा हिमाचल और मंडी है। इसलिए जो जानकारी में है आप इनको कब तक अरैस्ट करवायेंगे। इसके बारे में डेट दें।

दूसरा, कब तक यह पैसा वसूला जायेगा? मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं।

कृषि मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर सूचना देना चाहता हूं। मैंने सिंघा साहब को स्पष्ट कहा है कि मार्किटिंग यार्ड के बाहर के केसिज़ भी हैं। मैं आपको फिगर देना चाहता हूं। Number of cases outside the Marketing Yard, ठियोग-शिमला के अंदर 31 केसिज़ हैं। आपके मार्किटिंग यार्ड के 31 केसिज़ हैं। ...(व्यवधान)... मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

7.2.2019/1200/केएस/डीसी/1

मैं स्पष्ट करुं क्योंकि आपकी इन्फोर्मेशन गलत थी क्योंकि ये मार्किटिंग यार्ड के ही नहीं हैं, मार्किटिंग यार्ड के बाहर के केसिज भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जो 30 लोगों के अगेंस्ट केस बनाए हैं, हमने 6.2.2019 तक उनको डायरैक्शन दे दी है नहीं तो उनको अरैस्ट करेंगे। 30 लोगों पर केसिज़ चलाए हैं, 4 लोग अरैस्ट किए हैं। पुलिस से उनकी बात हो गई है । 30 लोगों पर जो केस चले हैं, उन्होंने कहा है कि हम उनको पैसे वापिस कर रहे हैं। नहीं तो हम उनको अरैस्ट करेंगे।

प्रश्न संख्या 1202

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जवाब में सारी बात सामने आ गई है कि कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी इन्होंने घोषणा की थी, मन्जूर नहीं हुआ है। इन्होंने साफतौर पर लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। 65 हजार करोड़ रुपये के 70 नेशनल हाइवे जो गडकरी जी से अनाउंस करवाए थे, एक भी सेंक्शन नहीं हुआ और अभी तक भी यह मामला सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी के स्तर पर फंसा है। दूसरा आपने फैक्टर-टू कहा था, वह आप अभी विचार कर रहे हैं और जमीन अधिग्रहण के बारे में आपने जी, नहीं कह दिया तो ये जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का सारा जाल फैलाया था,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए, उत्तर आ जाएगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने जाल फैलाया था, यह धड़ाम से गिर गया है । अब आपका इस बारे में क्या विचार है? आप प्रदेश को इस मायाजाल से कब बाहर निकालोगे?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत लम्बा प्रश्न करने की कोशिश की। क्योंकि समय बीच में आ गया इसलिए इनके दिल के कुछ अरमान दिल में ही रह गए। उनको भी हम पूरा करेंगें, ऐसी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो नेशनल हाइवेज़ की बात है, 2017 तक जब तक आपकी सरकार थी, इन प्रिंसिपल इनमें से बहुत सी नोटिफिकेशन हो गई थी। उसके बाद डी.पी.आर. का प्रोसैस करना था। आप लोगों ने कहा कि नहीं करिए, नहीं करिए, इसका चुनाव में बड़ा भारी असर होगा हम डी.पी.आर. का प्रोसैस शुरू कर देंगे तो चर्चा का विषय बनेगा। लगभग सवा साल का वक्त आपके पास था, आपने सिर्फ 8 डी.पी.आर. की आउटसोर्सिंग का प्रोसैस आगे बढ़ाया। हमारी सरकार आने के बाद अभी तक हमने

50 डी.पी.आर्ज़. की आउटसोर्सिज़ का प्रोसैस पूरा कर लिया है। ...(व्यवधान)... जो हकीकत है वह तो कहनी पड़ेगी। आपने तो दबा के रखा। ...(व्यवधान)...

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

दूसरे, माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्राफ्ट अलाइनमैंट रिपोर्ट की भारत सरकार से स्वीकृति हेतु भेजने की अगर बात करें तो 2017 दिसम्बर तक शून्य थी, और अब 2017 से हमने 54 कर दी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आगे बढ़े हैं। ...(व्यवधान)... आप धैर्य रखिए।

7.2.2019/1205/av/dc/1

इस बात को लेकर के जो भी किया जा सकेगा, हम उसको पूरा करेंगे।---(व्यवधान)---

अध्यक्ष :

प्रश्न काल समाप्त

(विपक्ष [कांग्रेस पार्टी] के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआऊट करके चले गये।)

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नेशनल हाई-वेज हमारे मित्रों के लिए एक बड़ा चिन्ता का विषय बना हुआ है। मैंने ठीक जानकारी दी है कि जब इन नेशनल हाई-वेज की सैद्धांतिक रूप से सैंक्शन प्राप्त हुई थी तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके डी0पी0आर0 का प्रोसैस शुरू किया जाना चाहिए था। लेकिन नहीं किया, कारण यह था कि अगर शुरू कर दिया तो यह चर्चा का विषय बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को राजनैतिक लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को राजनैतिक लाभ नहीं मिलना चाहिए इसलिए नेशनल हाई-वेज के सारे-के-सारे प्रोसैस को स्टॉल कर दिया गया। सवा साल में मात्र 8 डी0पी0आर0 की आऊटसोर्सिंग का प्रोसैस शुरू किया गया। आज हमें इस बात की खुशी है कि हमने एक साल के कार्यकाल में 50 डी0पी0आर0 की आऊटसोर्सिंग का प्रोसैस शुरू किया है। आखिरकार इनको इस बात को समझना चाहिए क्योंकि इसमें काफी लम्बा प्रोसैस होता है जिसमें वक्त लगता है। इसमें स्टैप वन में सैद्धांतिक रूप से हमारे नेशनल हाई-वे की डैक्लेरेशन के बाद डी0पी0आर0 के लिए कनसल्टैंट नियुक्त करने के लिए जो टैंडर की प्रक्रिया होती है, हमने उसको पूरा किया। उसके बाद टैंडरों पर आधारित ऐस्टिमेट्स भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं, यह दूसरा स्टैप आता है। उपरोक्त स्वीकृति के बाद कनसल्टैंट नियुक्त किए जाते हैं, हमने इस प्रोसैस को आगे बढ़ाया। इस तरह से आगे बढ़ाने के बाद हम एडवांस स्टेज पर पहुंचे हैं। नेशनल हाई-वेज की स्वीकृतियां जो हमें इन-प्रींसिपल मिली हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वे हमें नोटिफिकेशन के साथ वास्तव में प्राप्त हो। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के लोग पिछले कल से बाहर जाने का मौका ढूंढ रहे थे, वह मौका इनको आज मिला है। इन्होंने मौका भी ऐसा ढूंढा जिसका कोई अर्थ नहीं है। हमारी सरकार गम्भीर है और नेशनल हाई-वेज के बारे में हमने प्रधान मंत्री जी और सम्बंधित केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से मिलकर एक बार नहीं बल्कि अनेक बार बातचीत की है। बातचीत करने के अलावा हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार समन्वय करते रहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि यह कार्य जल्दी-से-जल्दी हो। लेकिन ये लोग हर चीज में राजनीति करते हैं, यहां तक कि विकास के कार्यों में भी

राजनीति करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके बाद पैसा कितना आया? मैं यह कहना चाहता हूं कि पैसा आयेगा। ये लोग पैसा उसको गिनते हैं जो जेब में आ जाए। मेरा जेब का कहने का मतलब यह है कि प्रोजैक्ट को भेजकर पैसा आने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को समझना चाहिए और अगर इन्होंने इस बात को समझा होता तो शायद ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं होती कि ये इस तरह का प्रश्न खड़ा करते। उसके बावजूद जिस मुद्दे को ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं और लोक सभा के चुनाव में इन सारी बातों को लेकर के शोर डाला जाए। लेकिन शोर डालने से कुछ नहीं होगा, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विकास हम सबका एक सांझा कार्यक्रम होना चाहिए। हमने इस प्रकार के जो प्रोजैक्ट प्रदेश के हित में आगे बढ़ाये हैं उनमें बाधा खड़ी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि आगे बढ़कर उसमें सहयोग देने की कोशिश करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये लोग अपने-आप कुछ नहीं कर पायें क्योंकि इनकी करने की मन्शा नहीं थी। हमने अगर अपनी मन्शा जाहिर करके उसमें आगे बढ़कर काम करने की कोशिश की है तो मुझे लगता है कि इनको उस बात की सराहना करनी चाहिए। इन्होंने सदन से बाहर जाकर के जिस प्रकार से अनावश्यक रूप से राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश की है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं।

07/02/2019/1210/टी0सी0वी0/एच0के0/1

<u>कागज़ात सभापटल पर</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग(सचिवालय प्रशासन सेवाएं) लिपिक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपी0ई0आर0(स.प्र.से.)-बी(2)-8/2009 दिनांक 18.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.05.2015 को प्रकाशित;

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग(सचिवालय प्रशासन सेवाएं) लिपिक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति(प्रथम संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःपी0ई0आर0(स0प्र0से0-I) बी(2)-8/2009-II दिनांक 09.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.05.2018 को प्रकाशित; और

iii. हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 ।

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार कश्यप सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2018 -19) , समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2018-19),का अष्टम मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि शहरी विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति,(वर्ष 2018-19), समिति का 10वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री सदन में वक्तव्य देंगे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, जब ये पाइपें बिछाई जा रही थी तो मुझे स्वयं ऐसा महसूस हुआ कि इनकी गुणवत्ता में कुछ कमी है। दिनांक 17 व 18 जनवरी, 2019 को जब मैं प्रदेश के दौरे पर था तो विभिन्न पेयजल योजनओं के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जी0आई0 पाइपों को जोड़ते व बेंड करते समय कुछ पाइपें टूट रही है। इस सदंर्भ में कार्य कर रहे ठेकेदारों से जब मैंने बात की तो इस बात की पुष्टि हो गई। इस पर तुरन्त संज्ञान लेते हुए मैंने सचिव व प्रमुख अभियन्ता को जांच के निर्देश दिए। प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा तुरन्त मुख्य अभियन्ता, हमीरपुर जोन को निरीक्षण करने व तीन दिन के अंदर fact finding report देने को कहा गया व reputed प्रयोगशाला से सैंपल टैस्टिंग करवाने को भी कहा गया ताकि पाइपों की गुणवत्ता के बारे में पता लगाया जा सके।

मुख्य अभियन्ता द्वारा इस मामले में उचित कार्रवाई की गई व प्रयोगशाला में टैस्टिंग के लिए भी उचित कदम उठाए गए। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में पाइपों की जांच करने के लिए अलग-अलग जोन के लिए मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में तीन निरीक्षण दल नियुक्त किए गए हैं। निरीक्षण दलों द्वारा पूरे प्रदेश में निरीक्षण प्रक्रिया जारी है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर पेयजल, सिंचाई व मल निकासी की नई योजनाओं के निर्माण तथा पुरानी योजनाओं के रख-रखाव के लिए विभिन्न ब्यास की जी0आई0, डी0आई0 पाइपों की खरीद हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से पूर्व निर्धारित शर्तों पर करता है जिनमें से मुख्य शर्तें इस प्रकार से हैंः-

(1) विभाग द्वारा पाइपों के क्रय के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जिससे संबंधित सभी दस्तावेज़ों की विभागीय तकनीकी समिति

द्वारा पूर्ण रूप से जांच-पड़ताल करने के पश्चात ही चिन्हित फर्मों की वित्तीय निविदाएं खोली जाती है।

(2) निविदाओं में भाग लेने वाली सभी फर्मों के गत तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार की सीमा 25 करोड़ होना अनिवार्य है।

07-02-2019/1215 /NS/HK /1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ------जारी।

(3) निविदाओं में भाग लेने वाली सभी फर्मों की गत तीन वर्षों में की गई आपूर्ति की सीमा 6 करोड़ निर्धारित है।

(4) सभी फर्मों का कच्चे माल के लिए सेल, टिसको, इसर, लियोडस, जे0एस0डब्ल्यू0 व भूषण पॉवर स्टील व पाइपों में प्रयोग होने वाले जिंक के लिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटिड से एम0ओ0यू0 होना अनिवार्य होता है।

(5) पाइप मेन्यूफैक्चर्ज़ द्वारा पाइप निर्माण के दौरान इनकी गुणवत्ता की जांच के लिए चार DGSD, RITES, WAPCOS LTD. and SGS स्वतंत्र एजैंसीज़ हैं, शत प्रतिशत जब पाइप बन रहा हो और जिन व्यक्तियों की स्पैशलाईजेशन इसमें हैं, उन व्यक्तियों को दिनरात वहां बैठना होता है, नियुक्त किए गए हैं जोकि भारत सरकार द्वारा भी मान्य हैं। इनमें से किसी एक एजैंसी द्वारा फर्म को इन पाइपों की निर्माण प्रक्रिया व उपयोग में लाई गई सामग्री का शत प्रतिशत निरीक्षण किया जाता है।

(6) पाइपों के निर्माण व शत प्रतिशत निरीक्षण के उपरांत जब पाइपों को डिस्पैच किया जाता है, से पहले फैक्टरी प्रांगण में पाइपों की गुणवत्ता की जांच के लिए उपरोक्त चार एजैंसियों के अलावा अन्य पांच एजैंसियां जिनमें DET NORSAKE VARITAS, BUREAU VARITAS, QSS, TUV India Pvt. Ltd. & Alpha Test House 3rd पार्टी निर्धारित हैं और 30 प्रतिशत का निरीक्षण करते हैं। इनमें से किसी भी एक एजैंसी को व हिमाचल प्रदेश के सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का अधिकारी व

विभागीय अधिकारी द्वारा पाइपों की रैंडमली बी0आई0एस0 कोड्ज़ अनुसार 30 प्रतिशत संयुक्त निरीक्षण करना अनिवार्य है व किया जाता है।

(7) निर्माण प्रक्रिया व निरीक्षण उपरांत हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के अधिकारी की देख रेख में पूरी पाईपें अपने सामने डिस्पैच करवाता है।

(8) मण्डलीय भंडार में पाइप पहुंचने पर सक्षम अधिकारी द्वारा पाइपों के भार, लंबाई व अन्य पैरा मीटर्ज़ का भौतिक निरीक्षण करके पाइपों को विभागीय रिकार्ड में लिया जाता है।

(9) जिन फर्मों को क्रय आदेश दिये जाते हैं, उन्हें निरीक्षण के दौरान तैयार किए गए माल के लिए प्राप्त कच्चे माल स्केलप, एच0आर0 कॉइल व जिंक के सभी बिल जोकि सेल, टिसको, इसर, लियोडस, जे0एस0डब्ल्यू0 व भूषण पॉवर स्टील एवं हिंदुस्तान जिंक लिमिटिड से प्राप्त किए गए हों। निरीक्षण एजैंसियों को दिखाने व हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को बिल के साथ देने होते हैं। जिसके बाद ही पाइपें सही हालत में प्राप्त होने के उपरांत ही सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन संबंधित फर्मों को बिल की अदायगी करने के आदेश जारी करता है।

अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार निरीक्षण के लिए निर्धारित उपरोक्त सभी नियमों का पालन किया गया है। बावजूद इसके विभागीय जांच दलों द्वारा निरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत जो भी कमियां जिस भी स्तर पर सामने आएंगी, उनका अध्ययन कर नियमानुसार दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खराब पाई गई पाइपों को बदलने के लिए फर्मों से भी मामला उठाया गया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी फर्मों की अदायगी पर रोक लगा दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पाइप क्रय की जो प्रक्रिया होती है, वह मंडल स्तर से शुरू होती है फिर सर्किल स्तर पर आती है, फिर जोन स्तर पर आती है फिर इंजीनियर इन चीफ ऑफिस में आती है और इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में आती है तथा यहां से आदेश किए जाते हैं। मैं माननीय सदन को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो भी कोई घटिया मैटीरियल आया होगा और जिन फर्मों का पाया जाएगा, उन फर्मों के

खिलाफ़ तुरंत कठोर-से-कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा जिन अधिकारियों की किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

07.02.2019/1220/RKS/YK-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री... जारी

और विशेष रूप से शत-प्रतिशत निरीक्षण के लिए जिन चार एजैंसियों को अधिकृत किया गया है, उन चार एजैंसियों में से जिस एजैंसी ने निरीक्षण किया होगा, उसमें जो कमी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू की जाएगी। ...(व्यवधान)... स्टेटमैंट के ऊपर चर्चा का प्रावधान नहीं है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेटमैंट तो घोटाले से जुड़ी हुई है, घटिया खरीद से जुड़ी हुई है। ...(व्यवधान)... आपको इस मामले की संवेदनशीलता देखनी चाहिए। यह सौ करोड़ रुपये की खरीद का मामला है और यह पाइपें सारे प्रदेश में बिछाई जानी है। माननीय मंत्री जी ने इस पर बयान दिया है और यह पाइपें सिविल सप्लाइज कोर्पोरेशन के माध्यम से खरीदी गई हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि चीफ इंजीनियर को इसकी जांच को जिम्मा दिया है। माननीय मंत्री जी आपके संज्ञान में यह मामला कब आया कि यह पाइपें निम्न स्तर की हैं? क्या सौ करोड़ रुपये की पाइपों का यह पूरा लॉट वापिस किया जाएगा और उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा या नहीं?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 व 19 जनवरी, 2019 को जब मैं प्रदेश भ्रमण पर था तो उस वक्त मैंने स्वयं इस खामी को पकड़ा है। इसमें जो भी कमी पाई जाएगी या जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन चार

एजैंसियों में से एक एजैंसी जिसकी वहां पर शत-प्रतिशत निरीक्षण की ड्यूटी होती है अगर उस एजैंसी की कमी पाई गई या जिन कंपनियों ने गलत माल सप्लाई किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। पाइपों की रिप्लेसमैंट भी की जाएगी और साथ ही यदि किसी अधिकारी की इसमें संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम बड़ी पारदर्शिता के साथ इस मसले को हल करेंगे। ...(व्यवधान)... लैब टैस्टिंग के लिए पाइप्स भेजें हैं। जब लैब टैस्टिंग के रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी। यदि हमें इस जांच को बाहर से करवाना पड़ेगा तो हम इसको बाहर से भी करवाएंगे। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किसी भी गांव में हम गलत मेटीरिअल बेचने नहीं देंगे। आपने रिप्लेसमैंट के बारे में कहा है यदि कोई गलत माल होगा तो निश्चित रूप से उसकी रिप्लेसमैंट की जाएगी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण

अध्यक्षः अब माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी और इस चर्चा का आज ही समापन होना है तथा उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। मुझे कांग्रेस विधायक दल की ओर से चार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आठ माननीय सदस्यों के नाम चर्चा में भाग लेने के लिए प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी चर्चा में भाग लेंगे। यदि सदन की अनुमति हो तो चार-चार माननीय सदस्य दोनों पक्षों की तरफ से चर्चा में भाग ले सकते हैं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है, दोनों तरफ से चार-चार माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। यहां एक सार्थक चर्चा हो रही है और इसमें किसी चीज को कम करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यदि इसका जवाब तीन या सवा तीन बजे तक शुरू कर दिया जाए तो ठीक रहेगा।

अध्यक्षः अब श्री हंस राज जी (माननीय उपाध्यक्ष महोदय) चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हंस राज (उपाध्यक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने 4 फरवरी, 2019 को अपना अभिभाषण यहां पर प्रस्तुत किया था जिसका माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने समर्थन के रूप में वक्तव्य रखा और इस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सभी माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तार से चर्चा की है।

07.02.2019/1225/बी0एस0/वाई0के0-1

जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस देश और इस प्रदेश के विकास के लिए प्रसास किए हैं वह सारे कार्य अपने-आप झलकते हैं। मैं तो सिर्फ इसमें दो चीजें रखना चाहूंगा कि जब केन्द्र में हमारी सरकार बनी तो जिला चम्बा को ऐस्पर्शनल जिला घोषित किया गया। पिछड़े जिलों में हमारी गणना पहले से की जाती थी। इस संबंध में जिला सिरमौर और जिला चम्बा का जिक्र वर्षों से किया जा रहा था। जैसे ही प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली में कार्यभार संभाला उन्होंने कम से कम हमें पिछड़ा माना । उसके साथ-साथ मैडिकल कॉलेज की शुरूआत करवाई वह जिला चम्बा के लिए एक अद्वितीय योगदान जिला चम्बा के लिए है और यह वरदान सिद्ध हुआ है, अन्यथा हमें टांडा, आई.जी.एम.सी. या पी.जी.आई. जाना पड़ता था। सभी तरह की योजनाओं का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है। उसमें सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि जिन योजनाओं ने आम जनता तक दस्तक दी है और आम जनता को सहुलियतें दी हैं। यह सराहनीय हैं। वह कार्य जब से माननीय मुख्य मंत्री जी ने पद भार संभाला है और प्रदेश में दौरे किए हैं प्रदेश में एक नई पहल हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बड़ा ऋणी हूं कि आपने ऐसे इलाके में जन सभा की है जहां पर कभी कोई मुख्य मंत्री नहीं गया था। यह इतिहास

बदला है और इतिहास नए तरीके से लिखना शुरू हुआ है। माननीय जय राम ठाकुर जी जिस तरीके से इस प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम पिछले पांच सालों तक यहां पर चिल्लाते रहे और मानीय पूर्व मुख्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं इनको भी बुरा लगता था। परंतु मुझे अपने क्षेत्र की चिंता थी । करीब 70 वर्ष के बाद चुराह क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का भी आभारी हूं कि उस वक्त हमें पी.डब्ल्यू.डी. का डीविजन मिला था, फायर स्टेशन भी मिला था। परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से हमें 100 किलोमीटर चम्बा जाना पड़ता था। आज मैं इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि आपने 100 बिस्तरों का अस्पताल हमारे पिछड़े हुए विधान सभा चुनाव क्षेत्र को दिया है। साथ ही मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं। देर से ही सही परंतु आपने हमारे को आशीर्वाद दिया। मैं आपका आभारी और ऋणी हूं। जब आप मेरे क्षेत्र में अस्पताल के उद्घाटन के लिए आएंगे पूरे स्टाफ के साथ हम वहां पूरी व्यवस्था करेंगे ऐसा मेरा निवेदन आपसे रहेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी आभारी हूं, जिस सरकारी औद्योगिक संस्थान के लिए हम बराबर पिछले पांच सालों से लड़ाई लड़ते रहे कि 47 पंचायतों की 90 हजार जनसंख्या को उनका हक मिले और उद्योगों और निजी सैक्टर में हमारे बच्चे भी कार्य करें उसके लिए हमारे लिए एक आई.टी.आई. दें। परंतु पिछली बार तो नहीं मिली लेकिन इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी आए और उन्होंने हमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी हूं। आपने चुराह के युवाओं को एक नई दिशा देने का कार्य किया है।

इसके साथ ही चुराह में बस अड्डे का शिलान्यास किया है और वहां पर भव्य बस अड्डा बनेगा इसके लिए आपने धन की व्यवस्था भी की है। मैं उसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपने बैरागढ़-शिमला तक के लिए सीधी बस लगाई है उसके लिए भी मैं माननीय

मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आई.पी.एच. डीविजन प्रदान करने की भी बात कही है, इस कार्य को अगली कैबिनेट में करने जा रहे है, इस तरह का हमें आश्वासन है । मैं समझता हूं कि चुराह के क्षेत्र को भी विकास के नए पंख लगे हैं। हम कह सकते हैं कि दो-तीन वर्षों पहले जो एक आंकड़ा दिया था जिसमें तीसा का ब्लॉक हिन्दुस्तान के 35 अति पिछड़े ब्लॉक्स हैं उसमें आता था। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस ऐस्पएर्शनल जिला को आगे करने के लिए नेशनल हाइवे से ले करके मैडिकल कालेज से ले करके और भी संस्थान दिए हैं। उसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे चुराह विधान सभा क्षेत्र को आगे ले जाने में अपना आशीर्वाद दिया है,

07.02.2019/1230/DT/AG -1

मुझे लगता है जब हम अगली बार चुनावों में उतरेंगे तो हमें घर द्वार उस तरह वोट मांगने की जरूरत नहीं होगी जिस तरह से हमें इस बार बहुत प्रयास करने पड़े थे । दोवारा हम इस माननीय सदन में लौटे है। मैं सिर्फ यहां पर दो तीन विषय रखने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसमें मुझे लगता है कि अभी और हमें काम करने को हैं। नई मंजिल नई राहें यह जो हमारा कार्यक्रम है इससे पर्यटन को नए पंख लगे हैं। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमत्री जी से इतना ही है कि जिस तरह से हिमाचल हर बैकबर्ड और वर्जन डैस्टिनेशन को हम नये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। वैसे ही डलहौजी और खजियार के अलावा चम्बा में भी बहुत बड़ा पोंटेशियल है चाहे वह भरमौर का चौरासी का एरिया हो, चाहे कुगती का क्षेत्र हो, चाहे भटियात में जोत का इलाका हो, चाहे डलहौजी का पधरी पास का एरिया हो जहां पर जम्मू-कश्मीर सरकार एनक्रोचमैंट भी कर रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि कोई कमेटी गठित करें और वहां देखें कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने बहुत एनगक्रोचमैंट की है। वहां की विधायिका से भी मेरा आग्रह है कि इस विषय को जल्दी टेकअप करें नहीं तो जम्मू -कश्मीर जिला चम्बा में लगभग 30-35 किलोमीटर तक अन्दर आ गया है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि सामरिक दृष्टि से भी महत्ववपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चम्बा प्रोपर चाहे चम्बा का चौगान

है, चाहे लक्ष्मी-नारायण मंदिर है । खजियार का क्षेत्र भी उसी में आता है। इसके अलावा भी जो ऐसे डेस्टिनेशंज हैं जिनको पर्यटन में शामिल किया जा सकता है । जहां तक चुराह चुनाव क्षेत्र की बात करू तो वहां Sach Pass is the only Pass जहां 12 महीने आपको बर्फ देखने को मिलती है। यह इलाका सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 1998 में जब आतंकवादी घटनाएं यहां पर हुई थी तो हमारे 35 लोग वहां शहीद हुए थे और 7 लोगों को वे साथ ले करके गए थे। जिनका आज दिन तक कोई पता नहीं है इस लिहाज़ से भी मैं यह कहना चाहूंगा कि एक हिमाचल प्रदेश पुलिस की बटालिन जो है वह चम्बा में गठित कर दी जाए ताकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उस क्षेत्र को भी हम पर्यटन के लिहाज से भी और डिफैन्स के लिहाज से भी हम उसको रख पाएं और दूसरा इसी के साथ लगता ही एक और विषय है जिस तरह हम पठानकोट वाया मण्डी मनाली से होते हुए लेह लद्दाख की तरफ जा रहे हो तो वह जो स्ट्रेच है जिसको भारत माला में शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने शामिल करवाया है उस ट्रैक से हमें 920 किलोमीटर बनता है लेकिन अगर पठानकोट हमारा बेस कैंप बनता है कल पाकिस्तान , चीन या किसी और की थ्रैट बनती है तो लेह - लद्दाख को हम वाया चम्बा चुराह पांगी से होते हुए लेह को जो है 420 किलोमीटर एकदम नजदीक से पकड़ सकते हैं। पीछे में माननीय प्रधान मत्री जी से भी मिला इस सिलसिले में माननीय राजनाथ सिंह जी से भी चर्चा हुई है। मेरा सिर्फ यह निवेदन माननीय मुख्यमत्री जी से है कि एक प्रपोजल जो है यहां से निकले, मण्डी मनाली वाला भी बने और उसके साथ-साथ जो पर्यटन को भी और उद्योग को चम्बा में ले जाने में भारी मदद करेगा सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण नैशनल हाईवे बनेगा । मैं ऐसा आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूंगा एस.पी.ओज़ की कल भी चर्चा हुई है मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने अपनी जवानी के 18,20 साल लागा दिए है स्पैशल पुलिस ऑफिसर्ज उन लोगों के साथ भी न्याय हो और 9 हजार की उनकी मांग है या उनको मर्ज कर दिया जाए किसी न किसी विभाग में क्योंकि 5 सौ परिवारों के भविष्य का सवाल है इसमें माननीय मुख्यमत्री कोई न कोई कदम उठाएंगे। खेलों में चुराह बहुत आगे निकला है हमारी तीन बेटियों ने कमाल कर दिया है पूरे नैशनल लेबल पर कुमारी शीतल ठाकुर

जिन्होंने तमिलनाडू में जो नैशलन हैड बॉल में हिस्सा लिया और उसमें गोल्ड मैडल लिया कुमारी सीमा का नाम आज पूरा प्रदेश जानता है जो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र से आती है इसने भी एथलैटिक्स में बहुत जबरदस्त नाम कमाया है और गोल्ड मैडल पीछे नेपाल में लिया था और उसके साथ-साथ एक नई बेटी जो है चम्पा ने कबड़ी में गोल्ड जीता है वह भी हमारे चम्बा से आती है तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है क कि जो स्पोटर्स कम्पलैक्स चम्बा जिला में मांग हुई थी जो चम्बा में प्रस्तावित भी है ,पैसा भी है तो जल्द से जल्द इसका काम चले तो हमारे जिस तरह साई हॉस्टल ने धर्मशाला बेस कैप बनाते हुए पूरे थ्रू आऊट हिमाचल के बच्चों को निखारा है वैसे ही हम चम्बा और चुराह जैसे इलाके के बच्चों को भी स्पोटर्स जैसी एक्टीविटी से बाहर निकल सकते हैं जिस तरह हरियाणा ने खेलों के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त नाम कमाया है ।

07/02/2019/1235/RG/AG/1

वैसे ही हम कबड्डी, बालीबॉल, बासकेटबॉल ओर अन्य खेलों में जबरदस्त नाम कमाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। इसके लिए इस तरह के कोचिंग सेन्टर्ज भी पिछड़े क्षेत्रों में खोले जाएं।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में जो हमारे यहां आर्मी की भर्ती हुई है, मैं बहुत ही गर्व के साथ इस माननीय सदन में कहना चाहूंगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 720 जवान निकले थे जिसमें से 130 जवान चुराह विधान सभा क्षेत्र से ही निकले हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां नशे के कारण नारकोटिक्स में भांग के कारण हम बदनाम हुए लेकिन मैंने जनसभाओं एवं सरकारी कार्यक्रमों में भी कहा कि इस पर धर-पकड़ हो और जो इस नशे के कारोबार में शामिल हैं, वे लोग पकड़े जाएं। लेकिन गरीबी के कारण लोग भटक जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वैकल्पिक स्तर पर हमें रोज़गार के लिए साधन मुहैया करवाने पड़ेंगे। कल जिस तरह से यहां सिकरी सीमेंट प्लांट का मुद्दा उठा था, वह पूरा-का-पूरा मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह ठीक कहा कि पीछे तो सरकारों ने बहुत वायदे किए थे, उसमें हम लोग भी शामिल हैं और कुछ लोगों ने चुनावों के समय भी मुद्दे उठाए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले तीन महीनों में हमारे यहां लगभग 52 लोग चरस के कारण अंदर गए हैं, अब

उनके परिवार तो पीछे रो ही रहे हैं, लेकिन जो दोषी है, वह पकड़ा जाए, यह अच्छी बात है। हमें उसके लिए कोई-न-कोई व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी। जो युवा 18-20 या 25 साल का किसी कारण से 2000 या 10,000/-रुपये के लिए 14-14 साल के लिए अंदर जा रहा है, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि यह जो सिकरी में सीमेंट उद्योग खुलना है, वह शीघ्र खुले। इसके लिए हमारी जनता सहयोग करेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, हाइड्रो में बहुत पोटेन्शियल है। जबकि हम लोग अब सोलर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 10-15 सालों के पश्चात सोलर के पैनल नष्ट करने में हमें बहुत मुश्किल आएगी और उन्न्त देशों ने भी इसके लिए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसलिए hydro is the only green energy. इसमें पोटेन्शियल भी है और हिमाचल में इसका दोहन हो सकता है। अतः माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जो चार प्रोजैक्ट्स हमारे चलने हैं, आप उनका जल्दी ही शिलान्यास करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है और आने वाले समय में चुराह के युवाओं को चुराह या चम्बा में या चम्बा के युवाओं को बद्दी, बरोटीवाला या कहीं और न भटकना न पड़े, ऐसा हम लोग करें। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उद्योग लगाने की ओर ग्रास रूट लेवल पर गंभीर प्रयास करेंगे। मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं, आप भी प्रयत्न कर रहे हैं और पिछली सरकार ने भी किया। लेकिन यदि धरातल पर कोई चीज नहीं उतरेगी तो लोग हमें कहेंगे कि जब भी बी.जे.पी. सत्ता में आती है या ये लोग सत्ता में आते हैं या जब चुनाव आता है तो यही लोग मुद्दा उठाते हैं। हमने जिस तरह से पूरे प्रदेश का भला करके आज जिन लोगों ने 55 साल शासन किया, उन लोगों के मुंह बन्द किए हैं और आने वाले समय में हम चम्बा में भी ऐसी व्यवस्था करेंगे। जिस तरह से समाज के उत्थान के लिए मुख्य मंत्री जी भरसक प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम इसके लिए उनके आभारी रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्वांट छूट गया है, मैं उसको भी यहां रखना चाहूंगा। पौली हॉऊसिज, बागवानी और कृषि में बहुत पोटेन्शियल है। लेकिन इस बार हमें सेब के नए पौधे नहीं मिले। इसमें भी थोड़ी पारदर्शिता आए और नए पौधे हर जगह मिलें। कीवी और अनार के उत्पादन की ओर यदि हम जाएंगे तो और बेहतर होगा। कैश क्रॉप्स जैसे मटर, आलू की ओर यदि हम जाएं तो बेहतर है। यही मेरा आग्रह था। मुझे पूर्ण विश्वास है

कि जितने पी.टी.ए., 'पैट' और एस.एम.सी. के लोगों ने यहां अपने 15-15 साल लगाए हैं, उनके साथ भी न्याय होगा। ऐसा मैं समझता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और आने वाले सेशन में मार्च के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चुराह में चल पड़ेगा, ऐसा मैं माननीय मुख्य मंत्री से विश्वास रख रहा हूं। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहां लोक निर्माण विभाग का डिवीजन दिया था, उसमें पूरी पोस्ट्ज हमें नहीं मिली थीं, वह internalization से हुआ था। जिस तरह से नए डिवीजन्स को बीस-बीस पोस्ट्ज दी हैं, उस तरह से मेरे डिवीजन को भी मिल जाएं। माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से पहले जब मैं विधायक बना था तो मुझे 12 ही सड़कें मिली थीं, लेकिन उनके आशीर्वाद से आज 35 सड़कों का शिलान्यास एक साल में मैं ही कर चुका हूं जो एक बहुत ही बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूं और माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने यहां जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय हिमाचल।

07/02/2019/1240/MS/DC/1

श्री हर्षवर्धन चौहान(शिलाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव कर्नल इन्द्र सिंह जी ने इस सदन में रखा है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने 36 पन्नों के इस अभिभाषण को देखा और यह भी देखा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कितनी परेशानी से इसे आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ा। इसमें क्या लिखा है उस पर हमने चर्चा की है। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि हम विपक्ष के विधायक जब मंत्री या सरकार से प्रश्न पूछते हैं तो इनका जवाब आता है कि 60 साल तक तुमने क्या किया। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें यह जवाब देने का तरीका नहीं है और यह इस बात को दर्शाता है कि जब मंत्री या सरकार के पास कुछ जवाब नहीं होता है तो यही कह दो कि तुमने क्या किया। माना हमने

कुछ नहीं किया लेकिन आप तो सत्ता में हो और लोगों ने आपको काम करने के लिए चुना है। विपक्ष जनता की आवाज है और आपसे प्रश्न पूछना हमारा अधिकार और हक है तथा आपका अधिकार हमें जवाब देना है। हम जो पुराने विधायक हैं अभी हम चर्चा कर रहे थे और मैं माननीय जगत सिंह नेगी जी से चर्चा कर रहा था कि हम विधायकों को मंत्री या सरकार से केवल इतना आश्वासन चाहिए होता है कि काम हो जाएगा और हम देख रहे हैं। मगर जब मंत्री लम्बे-लम्बे जवाब देंगे और जवाब को घुमाएंगे तो एक घण्टे में दो और तीन ही प्रश्न लग पाते हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से भी निवेदन रहेगा कि ये सीधा और ठीक जवाब दें।

इस अभिभाषण में बहुत सारी यानी 30 से अधिक स्कीमों का जिक्र किया गया है। बहुत से सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि अभी तो इन स्कीमों ने उड़ान ही नहीं भरी है और जब ये स्कीमें धरातल पर आएंगी तो प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि आज इस सरकार को बने हुए लगभग सवा साल का समय हो गया है और आपके पास काम करने का समय केवल साढ़े तीन साल बचा है। आपकी सवा साल में क्या उपलब्धि है? ...(व्यवधान)...माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 30 से अधिक स्कीमों का जिक्र है लेकिन जमीन पर कोई स्कीम नहीं है। केवल स्कीमों के नाम बदल दिए हैं। मैंने एक बात देखी है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में स्कीमों के नाम लम्बे-लम्बे और बड़े लुभावने होते हैं जोकि शुद्ध संस्कृत और हिन्दी में होंगे और जब स्कीम का नाम लेंगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या स्कीम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्कीमें वही हैं जो पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई थीं फिर चाहे वह "मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना" है, "मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना" है, "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना" है, "हिमाचल पुष्प क्रांति योजना" है, "आयुष्मान-भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" तथा हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर की योजनाएं हैं। ये सारी पुरानी स्कीमें हैं। आपने केवल इनके नाम बदले हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि स्कीमों की इम्प्लीमैंटेशन कैसे होती है। दूसरी बात, आपकी पुरानी स्कीमों पर इम्प्लीमैंटेशन पुअर है। आपने वर्दी के बारे में इस सदन में कहा लेकिन आप पिछले एक साल में स्कूलों में बच्चों को वर्दी नहीं दे पाए। 10 हजार बच्चों को लैपटॉप देने की स्कीम जो पूर्व सरकार द्वारा चलाई गई थी, पिछले

वित्तीय वर्ष में आप बच्चों को लैपटॉप नहीं दे पाए। मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में अपने भाषण में कहा था कि हम पहली, तीसरी, छठी और नौवीं के बच्चों को स्कूल बैग देंगे लेकिन आप स्कूल बैग उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। आपमें से बहुत सारे विधायकों ने कहा कि हम केन्द्र से 10 हजार करोड़ रुपये लाए हैं और जब वह पैसा लगेगा, तब आपको दिखेगा। लेकिन हमें सवा साल में यहां कुछ नहीं दिखा। वह 10 हजार करोड़ रुपया आपका आ रहा है या कब आ रहा है, आएगा भी या नहीं आएगा, पता नहीं है। कभी कोई मंत्री कहता है कि 15 हजार करोड़ रुपये है, कोई कहता है कि 11 हजार करोड़ रुपये है और कोई कहता है कि साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहेंगे कि कितना पैसा है? बी0जे0पी0 के विज़न डॉक्यूमैंट में लिखा था कि इस प्रदेश को कर्ज़-मुक्त राज्य बनाएंगे।

7.2.2019/1245/जेके/डीसी/1

मगर आपने पिछले एक साल के अन्दर लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का ऋण ले लिया है। हिमाचल प्रदेश का जो ऋण का आंकड़ा है वह 50 हजार करोड़ से भी निकल गया है। आप हमको कहते थे कि हिमाचल को कर्ज़ में डूबो दिया। आप क्या काम कर रहे हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप नये-नये कार्पोरेशन्ज़ और बोर्डज़ खोल रहे हैं। आपने अभी गो-सदन आयोग बना दिया, गुड़िया बोर्ड बना दिया और एजुकेशन में भी आपने एक बोर्ड बना दिया। राजनीतिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आप रास्ते निकाल रहे हैं। आप लोग हमारी आलोचना करते थे कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना दिए और उनकी फौज़ खड़ी कर दी। आप भी तो उसी रास्ते पर जा रहे हैं। आप और हमारे में क्या अन्तर है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की दो उपलब्धियां हैं। एक सामाजिक सुरक्षा पैंशन जो 80 से 70 साल की और दूसरी शौचालय। गैस कनैक्शन के बारे में तो क्या कहें क्योंकि किशन कपूर जी तो मेरे मित्र हैं। जब मैंने कहा कि 1 लाख 38 हजार के गैस कनैक्शन्ज़ की पैंडेंसी हिमाचल प्रदेश में है तो ये गुस्सा खा गए। फिर ये कहने लगे कि

आपने 60 साल में क्या किया? आप इसको करो यह बहुत अच्छी बात है। हमने तो हिन्दुस्तान के 120 करोड़ लोगों को दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति, जो बेटा अपने पूवर्जों को यह कहता है कि आपने कुछ नहीं किया, उससे बड़ा नालायक, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता । आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो हम सत्ता का सुख भोग रहे हैं it is due to Congress Party. उस वक्त जब हिन्दुस्तान अंग्रेजों से, गोरों से लड़ रहा था और फिर कांग्रेस के लोगों ने इस देश को आजाद करवाया, आपके आर0एस0एस0 के लोग क्या कर रहे थे? इस देश को स्वतंत्र करवाने में आपका कोई योगदान नहीं है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि हिन्दुस्तान में 1947 से 1952 तक कोई सरकार नहीं थी, केवल इन्टेरिम गवर्नमैंट थी। पहली सरकार 1952 में बनी। हिन्दुस्तान में जब बंटवारा हुआ, हिन्दुस्तान में टर्मोइल था, रिफ्यूजी आए, मार-काट हुई और इस देश में ...(व्यवधान)... 1952 से 1977 तक पांच चुनाव हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ठुकराया। क्यों, क्योंकि उस वक्त की सरकारों ने इस देश में योगदान किया होगा। 1977 में आप सत्ता में क्यों आए क्योंकि कांग्रेस की इमरजैंसी की गलती की वजह से आए? आप अढ़ाई साल तक भी हिन्दुस्तान को नहीं चला पाए। आपको हिन्दुस्तान की जनता ने बाहर कर दिया। आप लोगों का क्या कॉन्ट्रिब्युशन है? इस देश में सूई तक नहीं बनती थी। आज हम सैटेलाइट, मोबाइल तक बना रहे हैं। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब राजीव गांधी ने हिन्दुस्तान में कम्प्यूटर लाया उस वक्त हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट आप लोगों ने नहीं चलने दी। आपने कहा कि हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब अनिल शर्मा जी के पिता जी, पंडित सुख राम जी ने मोबाइल लाया और हिन्दुस्तान में मोबाइल और टैलीकम्यूनिकेशन की क्रांति कांग्रेस ने लाई तो उस वक्त भी आप लोग इस सदन में टेलिफोन बांध करके आए थे। आप लोगों को ये बातें नहीं कहनी चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश 19वां राज्य बना उस वक्त आपके लोग पंजाब का समर्थन करते थे। आप यह कहते थे कि स्टेट हुड को मारो ठुड। ...(व्यवधान)... मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपके प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी

वाजपेयी जी थे उन्होंने पार्लियामैंट में कहा कि मैं यह नहीं कहता कि मेरे से पूर्व की सरकारें और पूर्व प्रधान मंत्रियों ने देश में योगदान नहीं किया और अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मैं उनके साथ और देश के साथ अन्याय करूंगा। आप लोगों को उनसे सीखना चाहिए। ...(व्यवधान)...

07-02-2019/1250/SS-HK/1

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि इन्होंने मनरेगा का नाम अभिभाषण में लिया कि मनरेगा की उपलब्धियां हैं। जिस वक्त मनरेगा को केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार ने इंट्रोड्यूस किया तो आप उसके विरोधी थे। आज आप उसकी उपलब्धियां मानते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... अच्छी बात है कि आपने उसको ठीक किया।

माननीय अध्यक्ष जी, ये मनरेगा को उपलब्धि मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। देर आयद दुरुस्त आयद, बहुत अच्छी बात है। मैं बी0जे0पी0 को कहना चाहूंगा कि आप डबल फेस हैं। सत्ता में अलग और विपक्ष में अलग होते हैं। आपकी केन्द्र सरकार के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो वे कहते थे कि आधार गलत है। एफ0डी0आई0 गलत है। मनरेगा गलत है। जी0एस0टी0 गलत है। जब आप सत्ता में आए, वह पॉलिसी और सोच जो यू0पी0ए0 सरकार की थी, उसे आपने इम्प्लीमैंट किया। आपके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है कि आप आधार कार्ड के आधार पर डायरेक्ट सबसिडी लोगों को देंगे। आपमें से बहुत सारे विधायकों ने ज़िक्र किया कि लोग सबसिडी का गबन कर जाते थे। ऐसे लोगों को सबसिडी मिल जाती थी, जो हैं भी नहीं। उस चीज़ को किसने रोका। उसको आधार कार्ड ने रोका। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको आपको मानना चाहिए। हमारा भी इस प्रदेश के लिए कंट्रीब्यूशन है। आज आपकी सरकार है तो आप काम करो। आपकी कोई अच्छी स्कीम होगी, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। आपकी आयुष्मान भारत बहुत अच्छी स्कीम है, मैं उसकी तारीफ करता हूं। जो वास्तव में अच्छी स्कीम है, वह अच्छी स्कीम है। आपमें से बहुत सारे लोगों ने नड्डा साहब का नाम भी नहीं लिया। शायद

एक सदस्य ने लिया होगा। वे हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका भी काफी योगदान है। उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा।

बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। रोज़गार को लेकर आज गवर्नमैंट सैक्टर में सैचुरेशन प्वाइंट आ चुका है। आज हमको प्राइवेट सैक्टर में रोज़गार खोजना होगा। अभी माननीय उपाध्यक्ष, श्री हंस राज जी ने भाषण दिया। अपने सीमेंट प्लांट का ज़िक्र किया। मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ लगते गुम्मा में, बलबीर वर्मा जी के वहां पर पहले सीमेंट इंडिया को दिया, फिर रिलायंस वालों को दिया, मगर वे कम्पनियां भाग गईं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में अगर रिसोर्स जनरेट करने हैं तो हमको एक पॉलिटिकल कंसैंसस लानी पड़ेगी। जब कोई सरकार कुछ करती है, कोई नयी चीज़ लाती है या चेंज करती है तो हम बोलते हैं कि खा लिया, लूट लिया। सीमेंट प्लांट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सिज़ में क्या है, हमारे पास लाइम स्टोन हैं। हमको लाइम स्टोन बेसड इंडस्ट्रीज़ को एन्क्रेज करना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि प्लयूशन होता है। कुछ लोगों का मानना है कि प्लयूशन नहीं होना चाहिए। मगर जहां हमको रोज़गार के साधन मिलते हैं, वह अवश्य करना चाहिए। बाहर से हिमाचल प्रदेश में उद्योग तब आयेगा जब उनको सुविधा देंगे। अभी कल रोड का ज़िक्र कर रहे थे। मुझे पता है, मैंने भी लाइम-स्टोन, चूना-पत्थर का काम किया है। एक छोटी-सी माइन को चलाने के लिए हम लोकल लोगों के भी बट निकल जाते हैं तो बाहर का आदमी कैसे आयेगा। आप उनको रोड बनाकर दो, टैक्सिज़ में इंसैंटिव्ज़ दो, सस्ती बिजली प्रोवाईड करो, तब लोग यहां आयेंगे। हिमाचल प्रदेश तो वैसे भी एक डिस-एडवांटेज पॉजिशन में है। हम ऐसी जगह पर हैं जहां मार्किट से दूर हैं। रॉ मैटिरियल हमको लाना है। फिनिश वुड बनाकर बाहर को भेजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी लोकल प्रॉब्लम्ज़ हैं जिसको हमारी सरकारें ठीक ढंग से टैकल नहीं कर पा रही हैं। आज ट्रकों की यूनियन एक बहुत बड़ी समस्या है। आज उद्योगपति यहां नहीं आना चाहता है। ...(व्यवधान)... मुझे याद है, आपने अपने पांच साल क्या किया। आपने यही किया कि खा लिया, लूट लिया, हिमाचल ऑन सेल। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है 2003-2004 की बात है एक हीरो हौंडा वाले

हिमाचल प्रदेश में आए। उन्होंने नालागढ़ के पास एक बहुत बड़ी साइट सिलैक्ट की। मगर इस सदन और सदन के बाहर हंगामा कर दिया। डी0एफ0ओ0 की डैथ हो गई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वह प्लांट उत्तराखंड चला गया। आप हैरान होंगे कि अगर वह प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगता तो 5000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्रदेश को आता।

7.2.2019/1255/केएस/एचके/1

मगर जब हम ऐसी सोच रखेंगें तो मुझे लगता है कि हमारे यहां उद्योग नहीं आएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इफैक्ट हुआ है। परवाणू से सोलन सड़क की फोरलेनिंग की स्पीड हमारे सामने हैं। शिमला से अगर हमको चंडीगढ़ जाना है, जहां पहले ढाई या तीन घंटे लगते थे, आज चार-साढ़े चार घंटे लगते हैं। आज चंडीगढ़-मनाली रोड़ की हालत खराब है। कम्पनी भाग कर चली गई। आज हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट नहीं आ रहा है। आज ही मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि पठानकोट-मण्डी की जो फोरलेनिंग है, उसकी 20 परसेंट एक्विज़िशन नहीं हुई है। आज सरकार क्या कर रही है? हमको चाहिए कि जब भी हमारे पास प्रोजैक्ट आता है, प्रोजैक्ट आने से पहले हमको उसकी एक्विज़िशन करनी चाहिए। हम टैंडर कर देते हैं, काम शुरू हो जाता है फिर हम एक्विज़िशन करते हैं। कहां काम चलेगा? अभी जो केन्द्र का बजट आया, उसमें मैं देख रहा था कि हरियाणा को एम्ज़ दिया और अगले दिन हरियाणा के अधिकारी एम्ज़ की साइट सलैक्शन के लिए मौके पर चले गए। तो अधिकारियों के लैवल पर भी हमको आज तेजी लाने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनइम्प्लॉयमैंट की बात है। ऐजुकेशन सैक्टर के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने जो स्कूल खोले उससे बी.जे.पी. वालों को क्या तकलीफ है? आज जो केरल के बाद हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर सबसे हाइएस्ट है, वह इसलिए है क्योंकि हमारी कांग्रेस सरकार ने, राजा साहब ने गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, सीनियर सैकंडरी स्कूल और कॉलेजिज़ खोले।

आज वह स्थिति आ गई है कि हमारा सैचुरेशन प्वाइंट है। आज प्लायन हो रहा है। आज लोगों को सरकारी क्षेत्रों में या सरकारी स्कूलों में विश्वास नहीं रह गया है। प्रश्न यह है कि हमको एजुकेशन सैक्टर को, उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। मेरे भाई सुखराम चौधरी जी एस.एम.सी. और पी.टी.ए. के बारे में कह रहे थे लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कभी भी आज तक और मेरे क्या, शिमला जिला के ग्रामीण क्षेत्र हैं, किन्नौर, लाहौल-स्पिति, चम्बा, मण्डी, मुख्य मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र और बहुत सारे क्षेत्रों में, और हमारे यहां तो पिछले 25 सालों में कभी भी स्कूलों में 100 प्रतिशत अध्यापक नहीं हुए हैं। अगर 70 या 80 प्रतिशत भी हुए हैं तो वे इस वजह से हुए क्योंकि यह एस.एम.सी., पी.टी.ए., पैट की पॉलिसी आई हैं। इस वजह से हमारे यहां भर्तियां हुई है । अगर ये पॉलिसी गलत है तो आप क्यों इसको लागू कर रहे हैं? पी.टी.ए. हमने लाई लेकिन एस.एम.सी. तो वर्ष 2007 से वर्ष 2012 के बीच में जब आपकी सरकार थी, प्रेम कुमार धूमल जी ने शुरू की। आपने उसको बैकवर्ड पंचायतों में शुरू किया और हमने उसको हार्ड एरिया में शुरू किया। ठीक है, खामियां हो सकती हैं। कई जगह गलत सलैक्शन हो सकती है। गलत सलैक्शन आपके समय में भी और हमारे समय में भी हुई है लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उसके लिए मुख्य मंत्री या सरकार जिम्मेवार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करुंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, हार्ड क्षेत्रों में जहां अध्यापकों की कमी है, उसको पूरा किया जाए और एक सबसे बड़ी कमी है कि खाली पदों की मार सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र सहते हैं। हिमाचल प्रदेश के 20 से 25 चुनाव क्षेत्र हैं जो खाली पदों की मार सहते हैं। वह चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो। मुझे खुशी है, अभी उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज इनके क्षेत्र और चम्बा के नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। अभी आर्मी का जिक्र किया गया, डेढ़ सौ के करीब नौजवान तो मेरे चुनाव क्षेत्र शिलाई से भी आर्मी में निकले हैं। मेरे शिलाई चुनाव क्षेत्र से पिछले पांच-छः सालों में कम से कम 70 से 80 क्लास-I और क्लास-II अधिकारी बने हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। आज सरकारों ने स्कूल, सड़क, बिजली, पानी प्रावाइड किया है। सबसे बड़ी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की एक

उपलब्धि है कि हिमाचल प्रदेश में माइग्रेशन रेट बहुत कम है। केवल 11-12 परसेंट शहरों और गांव के बीच का गैप है। वह 12 परसेंट शहर में है और लगभग 80-85 परसेंट गांव में है। लोग गांव से क्यों प्लायन नहीं कर रहे हैं, रोज़गार की खोज में बाहर क्यों नही जा रहे हैं? क्योंकि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे साधन मुहैया करवाए हैं।

7.2.2019/1300/av/hk/1

एग्रिकल्चर सैक्टर का जिक्र आया तो एग्रिकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ है। एग्रिकल्चर में हिमाचल प्रदेश मे 5 प्रतिशत नेगेटिव ग्रोथ है। यहां पर होर्टिकल्चर का भी जिक्र आया, उसमें भी हमें नये पौधे और नई चीजें इम्प्रूव करने की जरुरत है। अभी उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारे पास नये पौधे उपलब्ध नहीं है, 1138 करोड़ के होर्टिकल्चर प्रोजैक्ट को रोक दिया गया है। आप यहां पर जैविक खेती की बात करते हैं, आप इस प्रदेश और देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? क्या हम पीछे जाएं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम आज से 50 साल पहले करते थे या हम आगे को जाएं? हमें नये सीड और नई टैक्नोलॉजी की जरुरत है।

मैंने बहुत सारी बातें कही हैं और आगे भी कहना चाहूंगा क्योंकि अभी तो हमारी बजट पर भी चर्चा होगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपका जो अभिभाषण है इसमें कुछ विशेष नहीं है। यह सिर्फ आंकड़ों का जाल है और एक कहानी लिखी गई है। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के निमित्त

यहां प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें कर दी हैं जो कि इस सदन की गरीमा तथा यहां पर रखे गए प्रस्ताव के विषय से हटकर हैं। इनको हर विषय में आर0एस0एस0 दिखाई देता है। ---(व्यवधान)--- लिया हुआ है, आप रिकॉर्ड देखिए। ---(व्यवधान)--- कोई योगदान नहीं किया। ---(व्यवधान)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो इनका तो (***) है। यहां शिमला में होलीलॉज के ऊपर वह कोठी आज भी विद्यमान है जिसमें श्री ए0ओ0 ह्यूम रहा करते थे जिन्होंने इस इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ---(व्यवधान)--- यह तो बीच में महात्मा गांधी जी आ गये।---(व्यवधान)--- आज दुनिया के नक्शे पर जो पाकिस्तान आया है वह इनकी करामात है। इनके कारण पाकिस्तान बना है। ---(व्यवधान)--- भारत माता के टुकड़े करने के लिए इनको शर्म आनी चाहिए। केवलमात्र अपने-आपको प्रधान मंत्री बनाने के लिए इन्होंने इस भारत माता के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, यह शर्म की बात है। ---(व्यवधान)--- यह कश्मीर जो आज हिन्दुस्तान में है यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की देन है। पं0 जवाहर लाल नेहरु और कृष्णा मेनन की गलती के कारण वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने काम किया था जिसके कारण पं0 जवाहर लाल नेहरु जी ने वर्ष 1963 की 26 जनवरी को दिल्ली की परेड में उनको बुलाया था। ---(व्यवधान)---

07/02/2019/1305/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

(विपक्ष (कांग्रेस पार्टी) के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोर-शराबा करते रहे।)

यदि आप नहीं जानते हैं तो राजा साहब से पूछ लीजिए। ---(व्यवधान)--- कोई बाढ़ आती है, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वह इनको नज़र आ जाती है, वरना हिन्दुस्तान में कोई भी काम हो उसके लिए इनको आर0एस0एस0 दिखाई देता है। आर0एस0एस0

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी संस्था है। ---(व्यवधान)--- जिसका मुकाबला ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन हेतु 2.10 बज़े अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

07-02-2019/1410 /NS/AG /1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त अपराह्न 2.10 बजे पुनः आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाईंट ऑफ ऑर्डर। अभी मेरे भाषण के बाद भारद्वाज जी (शिक्षा मंत्री) ने जो यहां शब्द कहें हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ए0ओ0 ह्यूम थे और वे (***) थे।

07.02.2019/1415/RKS/AG-1

मैं आपसे निवेदन करूंगा की (***) शब्द अनपार्लियामैंट्री है इसलिए इस शब्द को कार्यवाही से निकाला जाए। ...(व्यवधान)... यहां RSS का जिक्र किया गया और मैंने RSS के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इस देश की आजादी में RSS का कोई योगदान नहीं है। यह बात आदरणीय लाल कृष्ण अडवाणी जी की ऑटो बायोग्राफी 'My Country, My Life' में है जिसमें उन्होंने कहा है कि आजादी की लड़ाई में

RSS का कोई योगदान नहीं था और RSS वाले केवल शाखाएं ही लगाया करते थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह अडवाणी जी ने कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो 'A.O. Hume' और (***) अंग्रेज' है इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य क्लैरिफिकेशन्ज दे रहे हैं इन्होंने out of context कुछ चीजें कही थी जिनकी आवश्यकता गवर्नर अड्रैस में नहीं थी। इसलिए यदि (***) शब्द अनपार्लियामैंट्री है तब तो हम सब अनपार्लियामैंट्री हैं। फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति पार्लियामैंट्री नहीं है। This is very strange. (***) शब्द किसी भी डिक्शनरी में खोज लीजिए अगर बाप का अर्थ अनपार्लियामैंट्री निकलेगा तो हम इनकी बात मान लेंगे। ...(व्यवधान)... आप मना कर दीजिए कि इंडियन नैशनल कांग्रेस का जन्मदाता ए.ओ.ह्यूम नहीं था। You deny the fact. This is a fact on record. It was a registered society under the Act of 1860. A.O. Hume was the founder of that and became the creator. बाप का मतलब है क्रिएटर यानी पैदा करने वाला। ...(व्यवधान)... आप कह दीजिए कि ए.ओ.ह्यूम पैदा करने वाला नहीं था। आप इसे ऑन रिकॉर्ड लाइए हम आपकी बात मान लेंगे। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय भारद्वाज जी मैं आपको समय दूंगा। पहले मुझे व्यवस्था देने दीजिए। अब माननीय सदस्य, श्री वीरभद्र सिंह जी कुछ कहेंगे।

श्री वीरभद्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि (***) अंग्रेज था, यह अभद्र है। इन्हें यह कहना चाहिए था कि अंग्रेज कांग्रेस पार्टी का जन्मदाता था। (***) अंग्रेज था यह अनपार्लियामैंट्री शब्द है। He should withdraw these words or you must expunge it from the proceedings.

अध्यक्षः माननीय शिक्षा मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो पैदा करने वाला (***) है, वह ए.ओ.ह्यूम है जिनकी कोठी आज भी जाखू में विद्यमान है। ...(व्यवधान)...

(सत्तापक्ष और कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर आपस में नोकझोंक करने लगे।)

अध्यक्षः कृपया बैठिए, आप एक मिनट बैठिए। ...(व्यवधान)... बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)... मुझे लगता है कि यह न तो माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान की मंशा थी और

07.02.2019/1420/बी0एस0/डी0सी0-1

न ही माननीय शिक्षा मंत्री , श्री सुरेश भारद्वाज जी की कोई ऐसी मंशा थी । परंतु जो बात अभी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कही है वह सही है। मेरी ओर से ऐसा निणर्य दिया जाता है कि **जो (***) शब्द आया है उसे एक्सपंज किया जाता है।** इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा शायद जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। परंतु माननीय न्यायालय ने लगातार यह फैसला दिया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नथूराम गोडसे और उनकी विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। पूजनीय बापू जी की हत्या में किसी प्रकार आर.एस.एस. का रोल नहीं था। जिसके आधार पर हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने संघ पर से प्रतिबंध हटा दिया था। अतः इसे किसी भी प्रकार से इस विषय को सदन का विषय न बनाएं ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। ...(व्यवधान)...

शिक्षा मंत्री : (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) आप मुझे बोलने से इस प्रकार नहीं रोक सकते। मैं अपने विषय पर पहले से बोल रहा था।

अध्यक्ष : आप लोग बैठिए मैं आपको बोलने का समय दे रहा है। कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं अपने स्थान पर खड़ा हो कर बोल रहा हूं, कृपया मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपका नाम नहीं लिया है तो आप कैसे बोल सकते हैं।

अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी ने चर्चा के लिए समय मांगा है और इस विषय पर उनका चिट भी मेरे पास आया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी आप बोलिए।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय कर्नल इंद्र सिंह जी जो धन्यवाद प्रस्ताव लाए हैं उसमें चर्चा के लिए मैंने अनुमति मांगी थी उसी संदर्भ में माननीय हर्षबर्धन चौहान जी बोल रहे थे । इन्होंने 2-3 बातें बोली हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस बात पर आपने व्यवस्था दी है उस पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात इन्होंने स्वयं मानी कि 1975 में इमरजेंसी लागू हुई वह कांग्रेस की गलती थी।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर माननीय मंत्री जी को बोलने के लिए समय दिया है वे उस पर बोलें। वे शिक्षा विभाग की बात करें। ...(व्यवधान)...

शिक्षा मंत्री : विपक्ष के माननीय सदस्य जिस विषय पर बोले हों और मैं नहीं बोलूं यह नहीं हो सकता। मुझे भी उस पर बोलने का अधिकार है। आपका भाषण रिकार्ड पर है, आप भी सुनने का मादा रखें। ...(व्यवधान)...

07.02.2019/1425/dt/dc-1

माननीय हर्षवर्धन जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बातें शिक्षा को लेकर की है जिसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल की रेग्यूलर अप्वाईंटमैंट नहीं हुई थी। एक वर्ष में हमने 30 हजार ए.सी.आर्ज इकट्ठे किए और वर्ष 2007 से लेकर 2016 तक लगभग 7 हजार प्रिंसिपल को रेग्यूलर किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जब इनका पहला साल था ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय वीरभद्र सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री वीरभद्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय this is a wrong statement. यह कहना कि प्रमोशन्ज हुई ही नहीं यह गलत है। There is a procedure for promotion of teacher to the post of Principal and it is done annually. It is wrong statement.

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि वर्ष 2007 से 2016 के बीच हमारी भी सरकार रही है और इनकी भी सरकार रही है। उन दोनों सरकारों में दस साल तक सिर्फ प्लेसमैंट के आधार पर प्रिंसिपल रखे गए। जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक सभी प्रिंसिपल प्लेसमैंट पर रखे गए थे उनको एक पैसा नहीं मिलता था, वे पूरे प्रिंसिपल नहीं थे, उन्हें रेग्यूलर किया गया। यह मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। 24-25 दिसम्बर को इन्होंने ऑथ ले ली थी और 01.01.2013 से इनका कार्यकाल प्रारम्भ हुआ था तब से 31.12.2013 तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो शिक्षकों की सीधी भर्ती हुई वह केवल 269 थी। हमारे कार्यकाल में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की कुल भर्तिया 01.01.2018 से 31.12.2018 तक 6,146 हुई जिसमें से 3,021 शिक्षक हैं। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5,502 इनकी प्रक्रिया की स्टाफ सलैक्शन बोर्ड, हमीरपुर और पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहले ही रिकॉजिशन गई है जोकि 5,500 है और यह यह एक वर्ष का आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त हमने एक वर्ष में 1123 शिक्षकों को नियुक्त किया है। पहली वर्ष में हमने प्राथमिक,माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च विद्यालय सभी प्रकार के विद्यालय खोले और जो इन्होंने 21 महाविद्यालय खोले थे वे ज्यादातर अक्तूबर, 2017 में

07/02/2019/1430/RG/HK/1

खोले गए थे और जो इन्होंने 21 महाविद्यालय खोले थे जो ज्यादातर अक्तूबर, 2017 में खोले गए थे। जो इनकी परम्परा थी, माननीय उद्योग मंत्री के चुनाव क्षेत्र में माननीय प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने एक कॉलेज खोला था, लेकिन इन्होंने वह बन्द कर दिया था, उसको दूसरी जगह खोल दिया। माननीय उद्योग मंत्री जी को उसके लिएस माननीय उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ा तब जाकर वहां से उनको इन्साफ मिला था। लेकिन हमने इनके 21 कॉलेज में से 16 कॉलेज फंक्शनल कर दिए हैं जिसके लिए इन्होंने केवल एक लाख रुपये का प्रावधान किया था। इन्होंने पांच करोड़ रुपये की घोषणा की और केवल एक लाख रुपये उसमें दिया था। वे सबके सब हमने पिछले एक वर्ष में चलाए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जो अंशकालीन जलवाहक लगते हैं। पहले उनको 1900/-रुपये मिलते थे लेकिन अब हमने उसको बढ़ाकर 2200/-रुपये कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष हमने तीन नई योजनाएं चलाई हैं। एक योजना बिना बजट या बिना पैसे की है। माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी बखूबी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारा अधिकांश पैसा सेलरीज़ या पेन्शन में चला जाता है और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रियेट करने के लिए पैसा नहीं होता। हमारे यहां स्कूल, कॉलेज और सीनियर सैकण्डरी स्कूल माकूल हैं लेकिन वहां बैठने के लिए जगह नहीं है और महाविद्यालयों में भी बैठने के लिए जगह नहीं है। लेकिन इन विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़े हैं, वे बहुत ऊंचे-ऊंचे स्थानों तक गए हैं। उनको अपने स्कूल के साथ जोड़ा जाए ताकि उस स्कूल का कुछ फायदा भी हो, इसके लिए हमने 'अखण्ड शिक्षा ज्योति, अपने स्कूल से निकले मोती' नाम की एक योजना चलाई है जो सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने चुनाव क्षेत्र में उनके स्कूल बगश्याण से प्रारम्भ की। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां जाकर अपनी जेब से 51,000/-रुपये उस स्कूल को उस कार्यक्रम में दिए। यह एक ऐसी योजना है जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे हिमाचल में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह मजबूत हो और जो लोग उस स्कूल से पढ़कर निकले हैं, उसमें वे मदद करें। दूसरी योजना एक 'अटल आदर्श विद्यालय' की है। इसके तहत हमने दस विद्यालय इस वर्ष खोलना तय किया है जिसमें से 9 की जमीन के कागज़ात हमारे पास पहुंच गए हैं। झण्डुता में एक की लॉन्चिंग कर दी है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं वहां उसको प्रारम्भ किया है।

07/02/2019/1430/RG/HK/2

इसलिए हिमाचल प्रदेश में आज बहुत ज्यादा स्कूल-कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वहां गुणवत्ता पर जोर देने की आवश्यकता है। हमारे यहां पिछले साल प्राईमरी की ऐनरोलमेंट खत्म हो रही थी, हमने उसको रोकने के लिए नई व्यवस्था की है, नए स्कूल प्रारम्भ किए हैं और जो गरीब लोग निजी विद्यालय की फीस नहीं दे सकते, वे लोग भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करें, यह उनका अधिकार है और उस अधिकार को समझते हुए हमने सरकारी स्कूलों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए ये आदर्श विद्यालय प्रारम्भ करने की योजना बनाई है। वह केवल बजट में ही नहीं रही बल्कि उसको हमने जमीन पर भी उतार कर दिखा दिया है। इसके अतिरिक्त 'मेधा प्रोत्साहन योजना' है। हमारे बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसिज और 'नीट' में जाते हैं।

अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी, कृपया थोड़ा संक्षेप में कहें।

शिक्षा मंत्री : मैं दो मिनट में समाप्त करुंगा। तो तीसरी योजना भी हमने प्रारम्भ कर दी है। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका ठाकुर जय राम जी की सरकार ने अपने बजट में प्रावधान किया था, वह प्रारम्भ न न हुई हो।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात का जो बार-बार ये लोग यहां जिक्र करते हैं कि वर्दी देने में हम लेट हुए हैं। हम लेट हैं, मैं इस बात से सहमत हूं और अपनी गलती स्वीकार करता हूं। लेकिन साथ में मैं इसका संक्षिप्त इतिहास भी बता देना चाहता हूं। दिनांक 1-1-2012 को यह 'अटल वर्दी योजना' प्रारम्भ हुई थी। प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने इसको शुरू किया था। वर्ष 2013 में हमारी सरकार चली गई और इनकी सरकार आ गई और इन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में फैसला किया कि अटल वर्दी योजना का नाम बदल दिया जाए।

और इन्होंने उसका नाम "महात्मा गांधी वर्दी योजना" कर दिया। इन्होंने वर्दी का ऑर्डर अम्बाला की दो फर्म्ज को दिया। उसमें न ही कोई एल-वन था और न ही कोई मैन्युफैक्चरर था, जिसके द्वारा वर्दी खरीदी जानी चाहिए थी। उन अम्बाला की फर्म्ज के द्वारा जोकि एक भील्वाड़ा के नाम से है और एक नोएड के नाम से है, उनको वर्दी का ऑर्डर दिया गया लेकिन वह ऑर्डर पूरी साल नहीं आया। जब इनका प्रथम वर्ष था तो इन्होंने उस पूरे साल में वर्दी नहीं दी। 31 दिसम्बर, 2013 को सिविल सप्लाइज कारपोरेशन के एम0डी0 ने पत्र लिखा कि यह फर्म सप्लाई करने में फेल हो रही है और इनका सैम्पल भी फेल हो रहा है इसलिए 31 जनवरी तक एक्सटैंशन दे दी जाए। ...(व्यवधान)... एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुकेश अग्निहोत्री जी आप बहुत जल्दी कुर्सी से उठ जाते हैं। इस कुर्सी पर कोई कांटे नहीं लगे हुए हैं। ...(व्यवधान)...आपने भी नहीं दी थी। मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आपके सिविल सप्लाइज कारपोरेशन के एम0डी0 ने 4 महीने पहले आपको टैण्डर फाइनल करके दिए। आपने क्यों फाइल अपने पास रोक कर रखी? आपने टैण्डर रद्द क्यों किया?

शिक्षा मंत्रीः मैं यही बता रहा हूं कि किस एम0डी0 ने 4 महीने पहले टैण्डर फाइनल करके दिए। ...(व्यवधान)...आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। ...(व्यवधान)... सुन लीजिए। ठीक है, उन्होंने सारी सूचना आपको दे दी और फाइल की मूवमैंट भी आपको बता दी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वर्ष 2017 जोकि अंतिम वर्ष था, उस समय 12 अक्तूबर को कोड ऑफ कन्डक्ट लग गया था और वर्ष 2016-17 की वर्दी 3 नवम्बर, 2017 को पहुंची। कोड ऑफ कन्डक्ट लगने के बाद भी पूरी साल वर्दी नहीं दी गई थी। इन्होंने किसी भी साल बच्चों को वर्दी नहीं दी बल्कि अगले साल में वर्दी दी है। मैंने शुरु में कह दिया कि जब हम आए तो पूरी-की-पूरी वर्दी बदलने की जरुरत थी क्योंकि इस हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की एनरोलमैंट कम हो रही थी। लोगों का प्राइवेट स्कूलों की ओर रूझान हो रहा था इसलिए हमने स्मार्ट युनिफॉर्म देने के लिए नई वर्दी का नमूना बनाया और सैम्पल भी केबिनैट से एप्रूव करवाया। एल-

वन के द्वारा वर्दी खरीदी जाए, यह निर्देश भी दिया। जो टैण्डर प्रोसैस हुआ, वह अगस्त/सितम्बर में पूरा हुआ। लेकिन उस वक्त क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी, कम्पीटीशन पूरा नहीं था और एग्जोर्बिटैंट रेट का टैण्डर था इसलिए केबिनैट ने उसको कैंसल किया और रि-टैण्डर हुआ। हम रि-टैण्डर करके इसी एकेडेमिक ईयर में प्रयत्न करेंगे कि वर्दी बच्चों को मिल जाए लेकिन यह सब हम इनकी तरह छुपाकर नहीं करेंगे। जो चीज हुई है वह सामने है। यह ठीक है कि हमसे गलती हुई है जबकि ये लोग तो गलतियां करते ही रहते हैं और जान-बूझकर भी करते हैं। हमसे यह गलती हुई है कि देर हुई लेकिन वह टैण्डर प्रोसैस ही ठीक नहीं था। उस टैण्डर को कैंसल करना था और दूसरा देना था इसलिए उसमें देर हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, जो पिछले साल 3 नवम्बर, 2017 को वर्दी आई थी, वह पिछले वर्ष की वर्दी थी और उसे इस वर्ष हमने बांटा है। जो लैपटॉप इनके पिछले वर्ष के थे वे भी मार्च/अप्रैल में मैंने स्वयं बांटे हैं और स्थान-स्थान पर सब लोगों ने भी बांटे हैं। इसलिए नये लैपटॉप, जैसे पुरानी परम्परा चली है कि उनको इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन खरीदता है और शिक्षा विभाग स्वयं किसी चीज की खरीद नहीं करता है, हम केवल पैसा देते हैं। इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन को हमने बहुत पहले से बायोमीट्रिक मशीनें खरीदने के लिए कहा है लेकिन अभी तक वे नहीं खरीद पाए हैं। इसलिए इसमें भी देर हो रही है। पिछली साल मैंने इनके समय के लैपटॉप बांटे हैं।

7.2.2019/1440/जेके/डीसी/1

अब लैपटॉप इसी वर्ष इसी अकेडेमिक ईयर के अन्दर आने वाले हैं। वे लैपटॉप केवल स्कूलों तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि स्कूल के मैरिटॉरिअस स्टूडैंट्स के साथ-साथ कॉलेजिज़ के भी जो मैरिटॉरिअस स्टूडैंट्स हैं, उनको एक जी0बी0 डाटा और डोंगल के साथ हम देने वाले हैं। मैं केवलमात्र इतनी सी बात करना चाहता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्वाइंट ऑफ ऑर्डर

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः माननीय जगत सिंह नेगी जी, सत्र को चलने दो। ...(व्यवधान)...

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए समय दिया हुआ है, उसके ऊपर दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखनी है। अब बीच-बीच में नया ट्रैंड शुरू हो गया कि मंत्रिगण बीच में अपनी-अपनी स्टेटमैंट देना शुरू कर देते हैं। अभी आई0पी0एच0 मिनिस्टर साहब दे करके गए हैं फिर शिक्षा मंत्री दे करके गए हैं। जो बीच में हमारा असली मुद्दा है वह तो इस तरह से खत्म हो रहा है। हम यहां से बोल रहे हैं और उधर से मंत्री बोलने लग जाए और हरेक का ज़वाब आ जाएगा, फिर मुख्य मंत्री जी किस चीज़ का ज़वाब देंगे? यह तो एक नई प्रथा शुरू हो गई है। आप यह बिल्कुल गलत व्यवस्था कर रहे हैं। नियम 317 पर स्टेटमैंट तब देते हैं जब कोई विशेष बात हो। ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं है। वर्दी आपने एक साल से नहीं दी है। इसमें क्या विशेष बात हो गई है? आपने पैंट या निक्कर बनाने में एक साल लगा दिया। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः प्लीज, माननीय सदस्य अब आप बैठिए। कोई भी विषय आता है माननीय मंत्री उसमें इन्टरवीन कर सकते हैं। अब सत्र को आगे बढ़ने दो। यदि यही चलता रहेगा तो कैसे होगा? श्री सुख राम जी, आप एक मिनट में अपनी बात रखें।

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हर्षवर्धन चौहान जी जो एस0एम0सी0 के बारे में बोल रहे थे, उस सम्बन्ध में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। एस0एम0सी0 के माध्यम से उसका भरने का काडर ड्रॉइंग टीचर, पी0टी0आई0, एल0टी0, टी0जी0टी0, पी0जी0टी0, पटवार सर्कल था और पटवार सर्कल के जो उसमें कैंडिडेट्स आते थे, उनको 5 नम्बर मिलते थे। उनकी भर्ती हो जाती है। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज आप शॉर्ट करिए। मैं आपको ज्यादा अलाउ नहीं कर सकता । मैं अगले सदस्य को बोलने के लिए कह दूंगा। आप बोलिए।

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान जी मेरे बारे में बोल रहे थे। ...(व्यवधान)...जब एस0एम0सी0 के माध्यम से वह व्यक्ति उस स्कूल में भर्ती हो जाता है, जिसमें दो साल से पोस्ट खाली रहती है, वह उसका बेनिफिट लेता है, अपने घर में लगता है और जब उसको तीन साल हो जाते हैं, वह ट्रांसफर करके वहां से दूसरे स्कूल में चला जाता है और फिर पोस्ट खाली हो जाती है। फिर दोबारा से एस0एम0सी0 के माध्यम से वह पोस्ट भरी जाती है। मैरिट भी दर-किनार हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो एस0एम0सी0 के माध्यम से भर्ती हो वहां लोकल कोई नहीं होना चाहिए। स्टेट काडर की, स्टेट काडर की पोस्ट बनें, डिस्ट्रिक्ट कॉडर की, डिस्ट्रिक्ट कॉडर की पोस्ट बनें। जो शिक्षक एस0एम0सी0 के माध्यम से भर्ती हो, कम-से-कम वह 10 साल तक उस स्कूल में रहे ताकि बच्चे वहां पर प्रॉपर शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसमें बैकडोर एन्ट्री है और मैं सीधी और सही बात इस माननीय सदन में कहना चाहता हूं।

श्री हर्षवर्धन चौहानः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो श्री सुख राम ने यहां पर कहा मैं उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्षः बिल्कुल ठीक है। आप दोनों माननीय सदस्यों की बात एक ही है। अब श्री रमेश ध्वाला जी अपनी बात कहेंगे। मेरी सभी से एक प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी को उत्तर देना है। कृपया 10 मिनट में अपनी बात रखें। श्री रमेश चन्द ध्वाला जी।

श्री रमेश ध्वाला(ज्वालामुखी)ः माननीय अध्यक्ष जी, 10 मिनट में तो गाड़ी गर्म ही होती है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा माननीय श्री इन्द्र सिंह जी द्वारा रखी गई थी, इस महत्वपूर्ण अभिभाषण के लिए मैं, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का भी धन्यवाद करता हूं और साथ-ही-साथ यह भी कहूंगा कि हमारी सरकार लोक कल्याण कार्यों के प्रति सजग है, सचेत है और

07-02-2019/1445/SS-YK/1

यह अभिभाषण उसकी अभिव्यक्ति भी है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आप हर कसौटी पर ठीक उतरे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की कार्यशैली, सादगी, ईमानदारी, सच्चाई पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा सकता। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए सरकार प्रयासरत है और जो पहली पौढ़ी पर व्यक्ति खड़ा है उसको गौरवपूर्ण जिन्दगी व्यतीत करने का अहसास हो रहा है। हमारे मित्र जो यहां पर कह रहे हैं, कुछ लोगों ने तो दरवाजे, खिड़कियां और वैंटीलेटर बंद कर लिये। लेकिन मैं चौहान जी का धन्यवाद करूंगा कि कम-से-कम इन्होंने इतना बोला कि आपकी स्वच्छता, आयुष्मान भारत और पैंशन संबंधी स्कीमें अच्छी हैं। कुछ सदस्यों ने दरवाजे, खिड़कियां बंद कर ली और कहा कि हुआ ही कुछ नहीं है। ऐसी बात करना गलत है। आप जो कह रहे हैं, बड़े निस्सहाय महसूस कर रहे हैं। You are also part and parcel of the Government. आप भी उतने उत्तराधिकारी हैं जितने हम हैं। यह ठीक है कि मंत्री लोगों को जिम्मेवारी मिली है और मुख्य मंत्री पूरे हिमाचल प्रदेश को एक समान दृष्टि से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि हम तो कभी-कभी मुख्य मंत्री के पास जाते हैं। लेकिन हमारे मित्र, चाहे वह ऑपोजिशन का है या रूलिंग का है, जो भी मुख्य मंत्री के पास जाता है उसके काम से इंकार नहीं करते। कोई व्यक्ति बता दे कि उसे काम से इंकार किया है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी दूरदृष्टि पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे टाइम कम दिया है, मैं तो वैसे बड़ी दूरबीन से देखता हूं कि कहां क्या हो रहा है। मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। हम भी प्रधान रहे हैं। हमारे टाइम में पांच साल में एक लाख रुपया मिलता था। आज 14वें वित्तायोग के अंतर्गत कम-से-कम एक-एक पंचायत में 40-40 लाख रुपये अनस्पैंट पड़े हुए हैं। इतना पैसा भारत सरकार से आ रहा है। मैं हैरान हूं, इसके अलावा एक जगह मनरेगा में 50 लाख रुपये की सड़क बन रही है। मनरेगा से 50 लाख की सड़क पंचायत वाले बना रहे हैं। पहले हमें भारत सरकार से 25 और 75 की रेशो से प्रोजैक्टों को पैसे मिलते थे। लेकिन अब हमें 10:90 की रेशो से अनुदान राशि मिल रही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहां कुछ नहीं हो रहा है।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

हमारे विपक्ष के मित्र, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। न एन0एच0 का काम हुआ, न फोरलेन का काम हुआ। इसमें कुछ टाइम तो लगता है। जो बच्चा आज जन्म लेता है, क्या वह महीने बाद चलना शुरू हो जाता है? उसको चलने में समय तो लगता है। इसलिए मेरे इलाके में जो फोरलेन बन रही है उसका पहले सर्वे हुआ। सर्वे के बाद सैक्शन-4 की कार्रवाई हुई। अब उनको कम्पनसेशन मिलने जा रहा है। उसमें समय तो लगेगा। इसलिए आज जो बच्चा जन्म लेगा, क्या वह महीने के बाद चलना शुरू कर देगा? अब यह एक साल की सरकार हुई है तो इसमें रिजल्ट आने में समय लगेगा। इसलिए जो-जो बातें यहां पर कही हैं मैं मुख्य रूप से शिक्षा पर फोकस करूंगा। शिक्षा में दोषी आप भी हैं और ये कहते थे कि पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा सिस्टम हो चुका है। पहले कहते थे कि 'Education is a backbone of every country.' लेकिन अब जो हालत है, अब माननीय मंत्री जी प्री-प्राइमरी क्लास से इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं वरना मैं यह कह रहा हूं कि ये स्कूल बंद हो जायेंगे। निजीकरण से सारे-के-सारे स्कूल बंद हो जायेंगे

7.2.2019/1450/केएस/एजी/1

और टीचरों को 33 परसेंट नौकरियां हिमाचल प्रदेश में मिलती है। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो वे टीचर्ज़ कहां जाएंगे? इसलिए इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करिए। मुझे इस बात का गिला है, ठीक है, राजनीति के सूत्रधार होने के नाते हमने भी ऐसे-ऐसे गलत काम किए हैं, एक बच्चे का स्कूल, दो या तीन बच्चों का स्कूल खोल दिया और एजुकेशन के साथ राजनीति की है। आज वे सारे स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। इसके लिए गम्भीरता से विचार किया जाए और जो प्रदेश शिक्षा में पिछड़ जाएगा वहां डवैल्पमैंट नहीं हो सकती इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों की क्लबिंग करिए । मेरी पंचायत में 6 स्कूल हैं वहां पर एक ही दिन में 3 स्कूल खोल दिए। एक ही पंचायत में 6 प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें किसी में 4 बच्चे, किसी में 5 बच्चे और किसी में 11 बच्चे हैं । तो क्या यह सिस्टम गलत नहीं है? वे बच्चे कैसे पढ़ेंगें, कौन पढ़ाएगा? पांचवी में

पांच सब्जैक्ट्स हैं। वहां एक या दो अध्यापक हैं, वे क्या पढ़ायेंगे? इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, समय का अभाव है, समय के अभाव को देखते हुए मेरा मुख्य रूप से एक ही विषय है कि अगर दूध में मक्खी पड़ी हो तो मेरी फितरत नहीं है, मैं उस दूध को नहीं पी सकता। इसलिए मैं खासकर फोकस करने जा रहा हूं, मैं यहां पर तथ्य लाया हूं। आपको ऑथेंटिक करके दे रहा हूं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें जीरो टॉलरेशन होगी और मैं यहां पर एक शेर से शुरू कर रहा हूंः-

भारतीय राजनीति भ्रष्टाचारियों, अपराधियों की सैरगाह नहीं है,
शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया है,
यह शहीदों की विरासत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां लोगों ने मंदिर नहीं छोड़े, मस्जिद नहीं छोड़ी। इस समाज से क्या ले जाएंगे? खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। अगर अच्छा काम करके जाएंगे तो people will appreciate your betterment. लेकिन हमारे यहां तो ऐसा हुआ है कि मंदिर ही खा लिया। 6 करोड़ के मैंने आते ही टैंडर कैंसल कर दिए थे। दोगुने रेट्स पर काम दिए गए थे। अरे, उसका कोई प्रोसिज़र है, कोई मापदण्ड है। मापदण्ड यह है कि पी.डब्ल्यू.डी. के नॉर्मज़ के अनुसार 10 लाख तक लेकिन अब तो 5 लाख तक कर दिया, उसमें ऑन लाइन टैंडर होते हैं लेकिन यहां तो 6-6 करोड़ के ऑन लाइन टैंडर हुए। 16 करोड़ रु0 के 6 टैंडर मैंने कैंसल करवा दिए। मैं बताना चाहूंगा कि यहां जो कुछ हुआ है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करुंगा कि इसकी पूरी जांच करवाई जाए। यह पैसा लोगों का दिया हुआ दान है और उस पैसे से भ्रष्टाचार हुआ है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह पैसा लोगों का पैसा है। माननीय मुख्य मंत्री जी को पौने दो करोड़ के लगभग रिलीफ में पैसा दिया था, ठीक है वह दे दिया, लोगों के भले के लिए वह अगर कहीं लगा है लेकिन यहां पर एक ही फर्म है और उसकी तीन-तीन फर्में बनाई है,

7.2.2019/1455/av/hk/1

मैं उसको पढ़कर बताने जा रहा हूं। मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का गुणगान करना भी ठीक है क्योंकि आपके लिए इन्होंने इतना कुछ किया है। आपको इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय शांता कुमार जी पानी वाले मुख्य मंत्री और धूमल जी सड़क बनाने वाले मुख्य मंत्री थे। लेकिन मैं माननीय जय राम ठाकुर जी को यह कहूंगा कि इस भ्रष्टाचार को हम जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे; हमने ऐसी प्रतिज्ञा की है। इसमें दिक्कतें तो बहुत है, इसलिए मैं यहां पर दो पंक्तियां कहना चाहता हूंः-

माना कि मुश्किलें बेशुमार हैं,

मगर उनसे लड़ने को हम भी बेकरार हैं।

कितनी भी गहरी क्यों न हों जड़ें भ्रष्टाचार की,

जय राम जी के नेतृत्व में उन्हें उखाड़ने को हम तैयार हैं॥

ये जो कुछ मामला हुआ है मैं उसके बारे में यहां पर पढ़ने जा रहा हूं। मैं इस बारे में पूरा मामला तैयार करके लाया हूं। यह आरोप पत्र वर्ष 2013 से वर्ष 2017 के दौरान श्री ज्वालामुखी मंदिर ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि से करवाए गए निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के बारे में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि श्री ज्वालामुखी मंदिर ट्रस्ट के धन का विभिन्न कार्यों में अत्यधिक दुरुपयोग हुआ है तथा व्यापक अनियमितताओं के साथ-साथ अत्यधिक भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक लगभग 15 करोड़ रुपये के कार्य किए गए जिनके सभी टैंडर ऑन लाइन की जगह ऑफ लाइन किए गए। उसमें विज्ञान ब्लॉक महाविद्यालय ज्वालामुखी का निर्माण 5.77 करोड़ रुपये में किया गया। जब सरकार ने कॉलेज टेकओवर कर दिया तो वहां पर बिल्डिंग की क्या जरुरत थी? वहां

पर जो साईंस ब्लॉक बना उसकी निविदा 5.77 करोड़ रुपये की थी। वहां पर वह निविदा नहीं बल्कि एक गोलमाल हुआ है। उसके लिए कोई टैक्निकल सैंक्शन नहीं ली गई, उसकी फाइनैंशियलसैंक्शन एक करोड़ रुपये की थी। काम करने के बाद 4.37 करोड़ रुपये की सैंक्शन अभी तक नहीं मिली है, केवल फाइनैंशियल सैंक्शन मिली है। इसके बाद मातृ सदन के निर्माण/मुरम्मत के लिए 1.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए। संस्कृत महाविद्यालय ज्वालामुखी के निर्माण पर 1.54 करोड़ रुपये, भैरव मंदिर मार्ग के निर्माण पर 1.00 करोड़ रुपये, अन्य छोटे निर्माण कार्यों पर 5 करोड़ रुपये और मुख्य मंदिर मार्ग पर 5.35 लाख रुपये व्यय किए गए।

मातृ सदन, संस्कृत महाविद्यालय तथा भैरव मंदिर मार्ग का कार्य एक ही फर्म को दिया गया। यह एक ही फर्म है मगर इनके नाम अलग-अलग हैं। ये सारे कार्य बिना टैक्निकल सैंक्शन के कार्यान्वित करवाए गए। विज्ञान ब्लॉक महाविद्यालय ज्वालामुखी हेतु दिनांक 22.8.2015 को 1 करोड़ रुपये की प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति प्रदान की गई जबकि इसके विरुद्ध 4.66 करोड़ रुपये के टैंडर किए गए जो कि लोक निर्माण विभाग की अनुमोदित दरों से 25 प्रतिशत अधिक थे। इसके अतिरिक्त पी0/एल0 टोर स्टील आइटम में 68.73 लाख रुपये की डेविएशन शो की गई है जबकि कोई डेविएशन नहीं हुई, इन्होंने वह अप्रूव ही नहीं की थी। उसमें 1175 क्विंटल स्टील लगनी चाहिए थी जबकि वहां पर 2232 क्विंटल स्टील दर्शाई गई है जो कि एक जांच का विषय बनता है। इसके अतिरिक्त अर्थ फीलिंग की आइटम जो 3043.73क्युबिक मीटर रखी गई है जो कि 600 ट्रक बनते हैं जिसकी राशि 375 रुपये प्रति क्युबिक मीटर के हिसाब से 11.42 लाख रुपये बनती है जो कि बेसमैंट बनाने के बावजूद एम0बी0 में दर्शाई गई है। यह मौके की स्थिति से मेल नहीं खाती है। इसके लिए न कोई कंटूर प्लान (Contour Plan) बनाया गया और न ही कोई एक्स-सैक्शन बनाया गया।

07/02/2019/1500/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

मंदिर न्यास के धन से किए गए सारे कार्य न्यास द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं किए गए, न किसी कम्पीटेंट अथॉरिटी से टेस्ट चैक हुए और न ही डेविएशन स्टेटमेंट कम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित की गई। ---(व्यवधान)---

उपाध्यक्षः माननीय विधायक ध्वाला जी कृपया वाइंडअप कीजिए। अभी 4-5 माननीय सदस्य बोलने को बाकी है।

श्री रमेश चंद ध्वालाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्वालामुखी अस्पताल की मरम्मत का कार्य जो वर्ष 2016-17 में किया गया, जिस पर 22 लाख रुपये व्यय हुए। इस कार्य निर्माण की दरों में भी भारी अंतर है जैसे सी0जी0आई0 शीट का बाजार भाव 1200 से 1600 रुपये तक है जबकि टेंडर में 4200 रुपये प्रति शीट दर्शाया गया है। अभी समय का अभाव है अगली बार जब और समय मिलेगा तो इस पर और बात करेंगे। यदि इस प्रकार की धांधलियां होती रही तो इस समाज का क्या होगा? जनता ने हमें विश्वास के साथ इस सदन में भेजा है, यदि उनका हम पर से विश्वास उठ जाएगा तो हमारे साथ कोई भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ़ पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। मैं सब कुछ देखता रहता हूं कि कहां पर क्या हो रहा है? इसके बारे में मैंने जो दस्तावेज़ तैयार किए हैं, वे सभी संलग्न है। मैं इनको सभापटल पर ले करता हूं। इसके अलावा मैं यह भी चाहूंगा कि आज तक इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ है, इसका ऑडिट करवाया जाए। इसकी विजिलेंस से इंक्वायरी करवाई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारे अधिकारी जो हमारे आंख और कान है, यदि ये ही गलत करेंगे तो लोग हमसे क्या अपेक्षा करेंगे? माननीय उपाध्यक्ष जी आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय कृषि मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

कृषि मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पिछले कल ही बनीखेत की माननीय विधायिका श्रीमती आशा कुमारी जी ने फसल बीमा योजना के बारे में यहां सदन में चर्चा की । आज अखबारों में बहुत ---(व्यवधान)---

उपाध्यक्षः चलो रिफ्रैंस में बता देंगे। आप लोग तो हो, आप ही बता देना। ---(व्यवधान)--- आप प्लीज़ शांत रहें। मेरा आपसे निवेदन है, आप शांत रहें। माननीय मंत्री जी आप बोलिए।

कृषि मंत्रीः श्रीमती आशा कुमारी जी इस हाउस की सदस्या है। पिछले कल उन्होंने 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के बारे में चर्चा की ।आज कुछ अखबारों में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिला है। हालांकि, पिछले कल मैंने इसका उत्तर देना ठीक नहीं समझा क्योंकि वे भारत सरकार के बजट पर बात कर रही थी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने 68863 किसानों को लाभ पहुंचाया है और 12,74,68,569/- रुपये का मुआव़जा दिया गया है। इस साल के लिए हमने एक लाख पच्चीस हजार किसानों को चयनित किया है और उनको लाभ दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है कि किसानों को लाभ नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लाल (रामपुर)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस माननीय सदन में जो अभिभाषण दिया है और जिस पर कल कर्नल इन्द्र सिंह जी धन्यवाद प्रस्ताव लाए हैं, मैं भी अपने आप को उस चर्चा में शामिल करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय यहां पर जो अभिभाषण देते हैं, परम्परा के मुताबिक उसमें सालभर की उपलब्धियां व सरकार की नीति संबंधित कार्यक्रमों का ज़िक्र आता है। इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद ये नज़र आया कि सरकार की पिछले साल की जो 30 स्कीमें थी, उनका इसमें कोई ज़िक्र नहीं है, सिर्फ कुछेक स्कीमें हैं। हमारे पक्ष के जो नेता है, उन्होंने बड़े विस्तार इस इसके बारे में चर्चा की है कि जितनी भी परियोजनाएं पिछले साल की थी, उनमें कई स्कीमें ऐसी भी है जिनकी अभी तक नोटिफिकेशन्ज नहीं हुई है।

07-02-2019/1505 /NS/DC /1

श्री नन्द लाल -----जारी

ये स्कीमें कागजों पर नहीं उतरी हैं लेकिन यहां पर हो गई हैं। एक साल हो गया लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। यह भी बहुत निंदनीय और गलत बात है। आप जो यहां पर बजट सत्र के दौरान कमिट करते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे और एक साल में क्या हुआ,यह सब जग ज़ाहिर है। दूसरा, पिछले साल जब सरकार बनी तो कर्जे पर बहुत बातें हुई कि सरकार कर्ज ले करके चल रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि कोई भी सरकार स्टेट लाईक हिमाचल जिसके बड़े कम रिसोर्सिज हैं और अपने रिसोर्सिज़ न होने की वज़ह से the State has to depend on the Centre Government. केंद्र सरकार जो हमें देती है जैसे सबसिडी, उपदान या ग्रांट यह भी कोई खैरात नहीं है। यह जो हमारे शेयर की किटी बनती है और अगर हम अपने प्रदेश के विकास के लिए इसको लेते हैं तो इसके लिए अपनी पीठ या उनकी पीठ थपथपाने की जरुरत नहीं होती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इस साल ही देखिए कि लोन की यहां पर जो बात हो रही थी तो एक साल में यह लोन 4 हजार करोड़ से भी ज्यादा का है और इतना लोन आप ले चुके हैं तथा अगले पांच सालों में कितना लोन होगा you can imagine it. मैंने जैसे कहा कि यह हमारा legitimate right है और यह हमें मिलना चाहिए। इस दस्तावेज़ में एग्रीकल्चर के बारे में बड़े विस्तार से लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर इतना बड़ा सैक्टर है जिसका National Economy में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। यहां पर आपने जो स्कीमें बताई हैं, उन स्कीमों के अंडर "प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान" स्कीम है और इसमें आपने 9 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दी है। 9 हज़ार लोगों में से मात्र 3 हज़ार लोगों ने इसका फायदा उठाया है। 6 हजार लोग हैं, what are they doing after training? इस स्कीम का फायदा मात्र 3 हजार लोग ले रहे हैं और 6 हजार लोग जिन्होंने ट्रेनिंग की आपने इनको सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग दी है और वे क्या कर रहे हैं? It is a big loss to the Government. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी स्कीम का लोगों को कितना फायदा हुआ है और कितनी popularity हुई है?

इसके अतिरिक्त आपने सोलर फैंसिंग पर जो सबसिडी दी है या कहीं पर कांटेदार तार से फैंसिंग की गई है।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

अच्छी बात है कि सोलर फैंसिंग हुई है। जंगली जानवर, आबारा पशु और बंदरों आदि को रोकने के लिए यह बहुत अच्छी स्कीम बनाई गई है और पिछली सरकार के समय यह स्कीम आई थी तथा इसमें सबसिडी भी है। मगर इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें कितने लाभार्थी हैं? फिर हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार को यह देखना है कि instead of अपनी पीठ थपथपाने के बजाए कि हमने इसकी सबसिडी को बढ़ा दिया या कुछ और कर दिया। बेनीफिशरीज़ बढ़ाने के लिए इसका जो सिस्टम है या प्रोसैस है यह cumbersome होगा या कोई और दिक्कत होगी, उसको सिंपलीफाई करना चाहिए ताकि इस स्कीम का फायदा उठाया जा सके। इस स्कीम का नाम "खेत संरक्षण योजना" है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं हार्टिकल्चर की विस्तार से बात करता हूं। हार्टिकल्चर सेब की socio economic development में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। हार्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो जब तक हम मार्किटिंग और स्टोरेज़ की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम इसमें ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं। इनका फायदा उठाने के लिए मेरा पुनः सुझाव है कि कोल्ड स्टोर जगह-जगह बनने चाहिए और सुविधाजनक होने चाहिए ताकि ज्यादा-से-ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। इसी तरह से जो हमारी मार्किटिंग है, आज सुबह ही माननीय मंत्री जी ज़िक्र कर रहे थे कि the entire thing is left to APMC; ए0पी0एम0सी0 देंगे इतने लोग इसमें जाली पाए गए और एफ0आई0आर0 करेंगे। सरकार को देखना होगा कि इस तरह के डिफॉल्टर हैं और लाइसैंस तो ए0पी0एम0सी0 ईश्यू कर रही है। सरकार को यह देखना है कि ठीक आदमी को लाइसैंस मिला है या नहीं। अगर कोई गलती हो रही है तो सरकार को चैक करना है। मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि इसको ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार को गहराई में जाने की जरुरत है।

इसी तरह से पॉलीहाउसिज़, ग्रीन हाउसिज़ और फलोरीकल्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक आप number of beneficiaries नहीं बढ़ा पाएंगे तो आपको इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा। आप सबसिडी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन आपको सिस्टम को सिंपलीफाई करने की जरूरत है।

07.02.2019/1510/RKS/HK-1

श्री नन्द लाल... जारी

होर्टिकल्चर मिशन के अंदर 1132 करोड़ रुपये आए थे लेकिन अभी तक मामला upheld है। पिछली सरकार ने होर्टिकल्चर मिशन में बड़ी मेहनत से केंद्र सरकार से पैसे लिए थे लेकिन एक वर्ष के अंदर उस पैसे का कोई यूटिलाइज नहीं किया गया। लाइवस्टॉक में 407 करोड़ रुपये खर्च किए गए यह अच्छी बात है । छोटी नस्ल की गायें खरीदी जा रही है, उनकी फीड के लिए सब्सिडी दी जा रही है लेकिन आज सबसे मेजर इश्यू हमारी आवारा गाय हैं जिनके लिए आपने 'helpless selfless गाय' लिखा है। हम पिछले एक वर्ष में उन हैल्पलैस गायों के लिए कितने गौसदन बना पाए? इस दिशा में क्या कदम उठाए गए that is important. अगर आप रामपुर जाएंगे तो वहां पर जो नीरथ जगह है वह पूरा बाजार आवारा गायों से भरा पड़ा है। ऐसी बहुत-सी जगह हैं लेकिन हम गायों के लिए गौसदन का इंतजाम नहीं कर पाए। 'गौ सेवा आयोग का गठन किया गया', हिमाचल प्रदेश गौवंश संबर्धन बोर्ड बनाया गया लेकिन फिल्ड में हैल्पलैस गायों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई।

इस दस्तावेज़ में मनरेगा का जिक्र किया गया है। जैसा माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि इसमें आपने अपनी बड़ी तारीफ की कि नम्बर ऑफ डेज 100 से 120 कर दिए। इसमें आपने सॉयल कंजर्वेशन और रोड एक्टिविटी को जोड़ दिया है। हमें यह देखना है और धन्यवाद भी करना है of UPA Government of 2006. उन्होंने रोजगार देने के लिए यह एक स्कीम बनाई थी। यह एक खाली स्कीम नहीं है बल्कि यह एक एक्ट है। लेकिन दुःख इस बात का है कि हम इस एक्ट को ठीक तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। एक्ट में यह भी लिखा है कि जॉब कार्ड मिलने के बाद 15 दिन के अंदर काम पर नहीं बुलाया जाए तो 50 percent of the allowances will be paid by the Government to that candidate. आप वर्किंग के लिए तीन किलोमीटर के बाहर जाते हैं

तो आपको 10 प्रतिशत अधिक अलाउंसिज देने होंगे। इस तरह के कई प्रोविजन हैं मगर दु:ख की बात है कि हम इस मनरेगा को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। If we see the total number of beneficiaries of this year जो इसमें निकले हैं वे केवल 33,757 परिवार हैं। ऐसा क्यों है? हमें इसे अच्छी तरह लागू करने के लिए ब्लॉक लैवल में स्टाफ इत्यादि की जरूरत है और यह व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी जिसके लिए हमें विचार करने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि जब वर्ष 2014 में केंद्र में सरकार बनी थी तो मनरेगा स्कीम को बुरी तरह नकारा किया गया था। लेकिन आज हम उसी स्कीम को आगे बढ़ा रहे हैं और इस के लिए सोच की जरूरत है and implementation level of these schemes has to be increased.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनमंच की बात बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। जनमंच के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इसमें Government functioning का एक सिस्टम है। एक hierarchical structure होता है। Hierarchy के अंदर I am answerable to my senior, he is answerable to his senior, this is the way how it works. मगर जब यह सिस्टम डिफंक्ट हो जाता है और जब आपने देखा कि यह सिस्टम डिफंक्ट होने जा रहा है तो आप डायरैक्टली इंट्रैक्ट करने के लिए जनमंच का आयोजन करने लगे। कोई शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट देना है या कोई और सर्टिफिकेट देना है तो इसके लिए जनमंच किया जा रहा है। लोग जब दफ्तरों में जाते हैं तो वहां तहसीलदार कहता है कि हमारा डीलिंग हैंड नहीं है या अधीक्षक नहीं है और वे आज व्यवस्था में लगे हुए हैं। कई बार वे कहते हैं कि एस.डी.एम. साहब या तहसीलदार साहब जनमंच में गए हैं, वहां मंत्री जी आ रहे हैं और उन्हें सीटिंग अरेंजमैंट या खाने की व्यवस्था व्यवस्था करनी है। जब लोगों ने देखा कि इसमें कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है तो लोगों की हाजरी कम होने लगी। आपने पंचायत के अंदर हर व्यक्ति के लिए 50 रुपये के हिसाब से खाने की व्यवस्था भी की है लेकिन फिर भी हाजरी पूरी नहीं हुई तो आपने फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर दिया। इसके आगे भी अगर कुछ न हो पाए then, I don't know what is going to happen. यह अच्छी बात है कि जनमंच में लोगों की

समस्या का निवारण होना चाहिए मगर यह सही तरीके से होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप जनमंच को अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे।

07.02.2019/1515/बी0एस0/एच0के0-1

इसी तरह इसमें मिड-डे-मील का इसमें जिक्र है which is replication by the State Government. मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे वर्ष 2006 में इसे चला था and it is replicated in the State only. परंतु उस वक्त भारत से बाहर के लोगों ने भी इसकी तारीफ की है। So, I want to correct this document on this. इसमें भी ज्यादा आपको को पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। यह सब पुरानी स्कीमें चल रही हैं। आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। (घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय हम वैसे भी बोलते ही कम है, थोड़ा और समय बोलने के लिए चाहेंगे। इसके लिए आपका धन्यवाद।
अब थोड़ा डिजास्टर मेनेजमैंट की बात करना चाहता हूं। अभी जो बर्फबारी हुई उसके संबंध में बड़ी- बड़ी मिटिंग्स की गई। जिला और डीविजन स्तर पर बैठकों का दौर हुआ। परंतु जो सड़के खराब हुई और रास्ते जो बंद हुए उनकी कलियरेंस में कितना समय लग रहा है। आज हमारे क्षेत्र में जो बिजली की लाइन है वह बहुत बुरी हालत में है। लाइनमैन वहां पर नहीं हैं। लाइनों के पोल खराब हो चुके हैं और तरह की भी खराबी लाइन में आ रही है। इसका मुख्य कारण हमारे स्टाफ की कमी है। हम देखते हैं कि अनस्किल्डेबल लोग पोल पर चढ़ कर काम कर रहे हैं। उनकी जान भी खतरे में है। सरकार को चाहिए कि जो हमारा लगातार कार्य करने का तरीका है उस पर जोर दें। यह जो आपदा होती है यह कोई बता कर नहीं आती है। उसकी हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। इन कार्यो की तैयारी के लिए हमें लोगों की भर्ती भी करनी होगी।

इसी प्रकार से हमारे सड़कों की हालत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी कह रहे थे कि हमारे यहां बहुत से सड़कों का निमार्ण हुआ है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह बताना चाहूंगा कि पूरे पिछले एक साल के अंदर कोई भी नए रोड की बात नहीं की गई है। जो रोड बने है उन्हीं पर कार्य चला हुआ है और उन कार्यो में भी कमी आ गई है।

धीमी गति से कार्य हो रहा है। जैसे काशापाट की सड़क है और मनखड़ी की सड़क है वह इतनी महत्वपूर्ण है परंतु अभी भी वहां लोग पैदल जा रहे हैं। उस सड़क पर भी बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है। हम हर बार सदन में यह बात बोलते हैं कि इस कार्य में तेजी लाई जाए परंतु नहीं हो रहा है। मैं सीधे यह कहना चाहता हूं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या फिर सरकार दूसरे क्षेत्रों में सड़कों का कार्य कर रही है हमारे नहीं कर रही है। उस पर भी सरकार ध्यान दें। अभी बर्फबारी में हमारी नगर निगम की बस फसती है वहां से बर्फ तो हटा दी गई परंतु बस 7 दिनों तक फसी रही। ज्यादातर रोड पर क्या हो रहा है कि आधे रास्ते तक बसें जा रही है और आगे ड्राइवर का कहना होता है कि आगे बस नहीं जाएगी। इस बात का माननीय मुख्य मंत्री जी संज्ञान लें। क्यांकि माननीय मुख्य मंत्री जी लोक निमार्ण विभाग भी देख रहे हैं। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, चीनी और दालोंकी बड़ी तारीफ हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के वक्त वर्ष 2006 में सबसीडि स्कीम चलाई गई । माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे। उस स्कीम के अंदर तीन दालें, दो तरह के तेल और चावल आटे का प्रावधान किया था। वह स्कीम 100 करोड़ से शुरू हुई and we should be thankful that we are continuing with that system today. तब यह सोच बनी आज भी इसे बढ़ा कर शायद 20 करोड़ दिया गया है। इसमें जो पहल कांग्रेस पार्टी ने की थी उसे नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद राजीव गांधी अन्नपूर्णा योजना चली। उस योजना में we were second in the Country. जो इस योजना को चला पाए। जिसके अंतर्गत आज गेहूं और चावल 2 और 3 रुपये किलो प्रदान किया जाता है। उस वक्त भी ऐसा होता था।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नन्द लाल : आपने अच्छी चीनी लाई यह अच्छी बात है। इसी तरह मैं स्वास्थ्य पर बात करना चाहूंगा । हमारे यहां 2 पी.एच.सीज. हैं उनके लिए लैंड उपलब्ध है बजट

उपलब्ध है। परंतु एक वर्ष से सरकार उस पर कोई कार्य नहीं कर पाई है। इस बात का मुझे खेद है। रामपुर अस्पताल व महात्मा गांधी मेडिकल सर्विसिस कॉम्पलेक्स खनेरी अस्पताल इतना जरूरी है कि जिसमें पूरा किन्नौर, आउटर सराज, कोटगढ़ का एरिया और रामपुर का एरिया आता है वहां पर अभी तक अल्ट्रासाउंड की मशीन तक उपलब्ध नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। इन अस्पतालों में स्टाफ का भी यही हाल है। यहां पर जैसे फीगर दी गई है कि 359 डाक्टर्ज इनरोल हुए हैं

07.02.2019/1520/DT/YK-1

359 डॉक्टर्ज एनरऔर नर्सिज़ घरों में बैठी हैं, आप उनको रेक्रूट कीजिए और भर्ती पूरी कीजिए। अध्यक्ष महोदय,ट्रांसंफर पर पूरा जोर है। जैसे ही सरकार बनी जितने भी स्पैशलिस्ट थे उनको पहले भेजा गया । इसी तरह से दो पी.एच.सी की बात कर रहा हूं। एक तो लालशा है जिसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। शिक्षा पर तो बहुत चर्चा हो चुकी है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, हमको पढ़ने का हक है। जब पढ़ने का हक है तो स्कूल भी खोले जाते हैं आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे यहां के जो एरिया है। It's a hilly terrain area. जो नॉर्म्ज़ हैं स्कूल खोलने के लिए डिस्टैंस रखा गया है और नम्बर ऑफ स्टूडैंटस कम हो गए हैं। You can relax it any time. अगर आप इसको रिलेक्स नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे अनपढ़ रहे जाएगें। तो इसलिए स्कूल खोले गए। माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी उस समय यह कोशिश की है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य वाईंड अप करें। मुख्यमंत्री जी को उत्तर देना है।

Shri Nand Lal: Hon'ble Speaker, Sir, I will take two minutes more. पूरी कोशिश की है कि स्कूल जगह-जगह खोले गए हैं। कई बारी by relaxing these norms also. आज वो स्कूल बंद करने के कगार में हैं। हमारे यहां 21 कॉलेज जो खोले गए है 2017 हुआ क्या उसमें 16 कॉलेज तो ये मान गए कि ये हम चलाएंगे। 5 कॉलेज जो कि वो मेरी विधान सभा क्षेत्र में है जो कि ज्यूरी कॉलेज हैं। वह जो कवर कर रहा है एरिया 6 पचांयतें है across the river पन्द्रह-बीस की इधर मछनू से लेकर वहां तक करीब-करीब 21 पचांयतों के बच्चे वहां पढ़ने को जाते हैं। कॉलेज खोला उसमें रेगूलर लैक्चरर की पोस्टिंग हुई,

रेगूलर स्टाफ की पोस्टिंग हुए। रामपुर कॉलेज के जो प्रींसिपल थे उनको आदेश दिए you elect as a Principal इस कॉलेज को चलाना है और वहां पर 13 बच्चों की एडमिशनज हो गई। हमने रिक्वेस्ट किया कि यहां पर कोमर्स का टीचर भेजा जाए अगर यहां पर रेगूलर टीचर वहां से नहीं आ सकता तो रामुपर कॉलेज से जाए। ताकि कोमर्स के जो सैक्टर में पड़ने वाले बच्चे कोमर्स पड़ सकें। क्योंकि आजकल बच्चों को कोमर्स पढ़ने का क्रेज है बच्चों को नहीं भेजा गया और वह कोमर्स के बच्चे ultimately they have to go to Rampur. जो मैं आपको बता रहा हूं वहां पर13 बच्चे हैं। 13 में से 10 लड़कियां majority Scheduled Caste और 3 बच्चे हैंडिकैपड है।इस हालत में भी हमारी रिक्वैटस करने बाद अगर आप उस कॉलेज को बंद करना चाहते है तो यह बहुत शर्म की बात होगी और हमें इस बात का खेद है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री है वह यह कह रहे थे कि हमने 16 के करने हैं और 5 के नहीं करने हैं। तो मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जो आपसे रिक्वैस्ट है कि इस कॉलेज को जिंदा रखा जाए। और इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन गरीबों का और उन लड़कियों का और महिलाओं का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और रामपुर कॉलेज में पांच हजार प्लस स्ट्रैंथ है, तब भी प्रैशर कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो ननखड़ी के कॉलेज हैं उसका जो काम चल रहा है बिल्डिंग बन जाएगी वो भी शिफ्ट हो जाएंगे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य वाईंड अप करें। मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूं।

Shri Nand Lal: Hon'ble Speaker, Sir, I will take two minutes only. मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह जनमंच के अंदर लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आपने यह देख लिया है। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस चीज को भी रोकना बहुत जरूरी है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं बैकबॉन हैं, जैसे one of the Members हैं। ये बैकबॉन हैं, इनको इस तरह प्रताड़ित करना पब्लिक के बीच प्रताड़ित करना सही नहीं है। You cannot insult the people the way you are doing it. अगर आप यह करते हैं, As a Minister, as responsible person it is highly incorrect. इसमें एक लाईन है cordial relationship with employees लिखा है ऐसा इस डोक्यूमैंट में cordial relationship with employees मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि इस कोर्डियल

के अलावा आप 3% ऐडिशनल डी.ए दे रहें हैं. और 4% इंटरिम रिलिफ दे रहे हैं। ऐडिशनल डी.ए. के लिए you are late. It's an obligated payment जो आपको देनी ही है, what is so special. आप अपनी पीठ क्यूं थपथपा रहे हैं इसके लिए इंटरिम रिलिफ 4% दिया it's a recoverable. उसमें क्या है ये तो देना ही देना है। ये आपका रिलिफ है क्योंकि आपको जो फाईल अप हो रही है उसकी लाईबिल्टी कम होती जा रही है गर्वमैंट लेवल पर तो इसमें भी कोई बड़ी थपथपाने की कोई बड़ी बात नहीं हैं।

07/02/2019/1525/RG/YK/1

कंज्युमर प्राईस इंडैक्स को देखते हुए हर कर्मचारी को एक साल में दो बार डी0ए0 दिया जाता है। तो इस प्रकार वह दिया जाता है, इसलिए इसमें कोई पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। बल्कि हमारा यह कहना है कि इनका ध्यान रखना चाहिए।
माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बातें तो कुछ और भी थीं, परन्तु आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अभी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर भी देना है। दो सदस्य विपक्ष की ओर से और एक सदस्य पक्ष की ओर से बोलने वाले हैं। अगर वे पांच-पांच मिनट में अपनी बात रख सकते हैं तो मैं बोलने की अनुमति दूंगा। अगर ज्यादा समय लेना है तो थोड़ा प्रतिबन्ध रहेगा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर भी देना है। अब श्री नरेन्द्र ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया पांच मिनट में समाप्त करें, मैं छठे मिनट के लिए अनुमति नहीं दूंगा।

श्री नरेन्द्र ठाकुर(हमीरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव हमारे वरिष्ठ सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह ने रखा था, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अपना भाषण शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज इस चर्चा का अन्तिम दिन है और सदन का समय भी बढ़ाया जा सकता है।

अध्यक्ष : नहीं, इसके बाद नौ दिन चर्चा चलनी है, आपने बजट पर बोल लेना।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : पांच मिनट में बोलना तो बहुत मुश्किल है।

अध्यक्ष : पांच मिनट मिलेंगे, वकीलों के लिए तो यह बहुत आसान है।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, लगभग एक साल, दो महीने पहले हमारे प्रदेश में एक नौजवान मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। शुरू-शुरू में तो ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा था कि क्या पता हमारे नौजवान मुख्य मंत्री सरकार चला पाएंगे या नहीं। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं और इनका धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने एक साल में जिस ढंग से यह सरकार चलाई है, आज विपक्ष वाले इस सरकार के खिलाफ बोलने में बिल्कुल असमर्थ हैं। एक साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग, हर क्लास, हर कैटागिरी माननीय मुख्य मंत्री जी की योजनाओं से खुश है, चाहे वह विकास की बात हो, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि की बात है, हर वर्ग को फायदा मिला है। एक कहावत है, "Well begun is half done," उस कहावत को पूरा करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक साल में यह उपलब्धि हासिल की है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष वाले नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। कल यहां इस पर काफी चर्चा की गई कि आजकल कैंसर के रोगी दिन-प्रति-दिन बहुत बढ़ रहे हैं। आज हम जो भी फूड ग्रेन्स, सब्जी या फल खाते हैं, उनमें अत्यधिक फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड का उपयोग किया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री की एक सोच है कि हमारे प्रदेश के लोगों को एक हैल्दी ऑर्गेनिक फूड खाने को मिले। इसके लिए हिमाचल प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग की शुरूआत की गई है। मैं तो हैरान हूं कि यह नेचुरल फार्मिंग की इतनी बढ़िया खेती है लेकिन इसको भी विपक्ष वाले पचा नहीं पा रहे हैं। इस साल शुरूआत में ही 9,000 फारमर्ज को इसका प्रशिक्षण दिया गया और 3,000 फारमर्ज ने इसके माध्यम से खेती करना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये कह रहे थे कि 9,000 को ट्रेनिंग दी गई और सिर्फ 3,000 ने खेती शुरू की, तो जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, अगले साल वे भी शुरू करेंगे। अभी यह तो शुरूआत है। जब सिक्किम राज्य में पूर्णतया आर्गेनिक खेती की जा सकती है तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की खेती क्यों नहीं की जा सकती? इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और इनको बधाई भी देता हूं कि यदि हिमाचल प्रदेश में पूर्णतया नेचुरल फार्मिंग शुरू की जाए तो इससे बढ़िया और क्या होगा जिससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जनमंच हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू किया है। लेकिन इसके लिए ये लोग शोर मचा रहे हैं कि यह कार्यक्रम ठीक नहीं है। हमारे यहां एक बहुत बड़े राजनीतिकार चाणक्य जी हुए, उन्होंने यह कहा है कि जिस रियासत में असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा शोर मचाएं, हो-हल्ला करें, तो समझ लेना चाहिए कि उस रियासत का राजा बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध है।

7/02/2019/एम0एस0/1530/वाई0के0/1

और यही कहावत इस "जनमंच" प्रोग्राम में आप के ऊपर भी लागू होती है कि हमारी सोच क्या है और माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच क्या है। "जनमंच" का उद्देश्य यह है कि आम शिकायतकर्त्ता जो गांव में बैठा है, जो जिलाधीश के पास जाने में असमर्थ है, जिसको एक्सियन के पास जाने का समय नहीं मिलता है और अगर वह जाता भी है तो वहां उसको मिलने का समय नहीं मिलता है। तो जब जनमंच का कार्यक्रम उसके गांव में हो रहा है, वह अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आ रहा है और उसी समय उसकी समस्या पर कार्रवाई हो रही है तो इसमें बुरी क्या बात है? क्या आप लोग यह चाहते हैं कि आम आदमी की समस्या का मौके पर निवारण न हो? यदि ऐसा है तो आप हां कर दीजिए। इस तरह से एक साल में जो लगभग 100 जनमंच प्रोग्राम हुए हैं उनमें हजारों कम्पलेंट्स का मौके पर हल किया गया या हल करने के निर्देश दिए गए। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो पैसे वाला और चालाक आदमी होता है वह तो अपने काम करवा लेता है लेकिन गरीब आदमी जिसका कोई नहीं होता है,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप कीजिए।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया मंच आम आदमी के लिए कोई हो ही नहीं सकता है।

एक बात और कहना चाहता हूं। यहां पर कानून-व्यवस्था के बारे में चर्चा हो रही थी। मैं कहता हूं कि जिस समूथ ढंग से यह एक साल प्रदेश में गुजरा है शायद ही ऐसा पहले गुजरा हो। ...(घण्टी)...माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

यह बात एक साल दो महीने पहले की है कि यहां पर दो-तीन ऐसे काण्ड हुए, जिससे सारे शिमला शहर के लोग बाहर आ गए। होशियार काण्ड मण्डी में हुआ तो मण्डी के सारे लोग बाहर आ गए। अब सारे लोग क्यों बाहर आ गए? वे इसलिए बाहर आ गए क्योंकि दोषियों को बचाया गया और निर्दोष लोगों को जेल के अन्दर डाला गया। इसलिए लोगों को उस केस की जांच में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने एकदम से गुड़िया हैल्प लाइन जारी कर दी और उसके द्वारा 1398 कम्पलेंट्स एक साल के अन्दर-अन्दर आई हैं। जिनके ऊपर केस बनते थे, उनमें एफ0आई0आर0 लॉज हुई और जिनके ऊपर केस नहीं बनते थे, उनका निपटारा किया गया है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब आप अभिभाषण का समर्थन करें। मैं अब अगले वक्ता को चर्चा हेतु बुला रहा हूं।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः तो इस तरह का एक होशियार सिंह काण्ड मण्डी में हुआ था। समय की कमी है अन्यथा बोलने को बहुत कुछ था। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का जो एक साल का कार्यकाल रहा है, वह बहुत शानदार रहा है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः नरेन्द्र ठाकुर जी, आपका भी धन्यवाद। अब चर्चा में श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (कुल्लू)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी द्वारा प्रदेश विधान सभा में दिए गए अभिभाषण पर अपने विचार रख रहा हूं।

यहां बात कही गई कि युग परिवर्तन हुआ और युवा नेतृत्व आया। हम जानते हैं कि मुख्य मंत्री जी बहुत सरल हैं लेकिन मेरा यह मानना है कि मुख्य मंत्री जी का जो सरल स्वभाव है इसको अफसरशाही सरलता से न लें। जिस प्रकार से टीम वर्क की उम्मीद थी कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, हालांकि कुछ मंत्रीगण बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं। मेरा यह कहना है कि जो आपका टीम वर्क है उस टीम वर्क के साथ आपका इस वक्त ध्यान गोल दागने पर होना चाहिए था लेकिन आपका ध्यान चीयर लीडर्स पर ज्यादा जा रहा है। चीयर लीडर्स कहने का मेरा मतलब यह है कि ऐसी अफसरशाही जो पिछले वक्त में जब हमारी सरकार थी तो हमारी चीयर करती थी और

आज आप हैं तो आपकी चीयर करती हैं। मैं चाहूंगा कि कृपा करके यह पहला हाफ है और नई ऊर्जा है ...(व्यवधान)... मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी जो आप फैसले ले रहे हैं उन्हें धरातल पर लाइए। उनके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। नेशनल हाइवेज की बात सर्वेक्षण पर, रज्जु मार्ग की बात सर्वेक्षण पर और टूरिज्म के प्रोजैक्ट्स भी सर्वेक्षण पर हैं। इन्हें धरातल पर लाना होगा। यहां बार-बार ऐसी बातें हो रही हैं। आज बागवानी के बारे में मंत्री महोदय कह रहे थे कि बागवानी के क्षेत्र में बड़ा-भारी क्लेम दिया गया।

7.2.2019/1535/जेके/डीसी/1

मंत्री महोदय, आपके लाहौल-स्पिति में अभी हाल ही की बर्फबारी में जो नुकसान हुआ, हैरानी की बात तो यह है कि अब उन लोगों को 100-100 और 500-500 रुपये के चैक मिल रहे हैं। क्या यह बीमा योजना है? अभी भी उन्होंने कहा कि 11 करोड़ रुपये बांटे है और मैंने तुरन्त कैल्कुलेट किया तो एक किसान को 1500 रुपये मिले जबकि किसान 1500 रुपये के लिए कभी क्लेम नहीं करता । मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें धरातल पर उतरना पड़ेगा। आपने यहां पर पशुधन की बात की, गौ-रक्षा, गौ-सेवक की बड़ी बातें हो रही हैं। मुख्य मंत्री जी, आपको गुमराह किया गया। कुल्लू में सैंकड़ों पशु बह गए। मीडिया में बात को रोका गया। श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी उस बात के खुद गवाह हैं। किसने उस गऊशाला को खड्ड में बनाया था? उसके ऊपर कितना पैसा व्यय हुआ था? वहां पर जिलाधीश महोदय उस गौ-हत्या से बचने के लिए आज ब्यास आरती कर रहे हैं और वह ब्यास आरती भी उस जगह पर कर रहे हैं जिसके 50 मीटर के दायरे में कूड़ें का संयन्त्र लगा है और उस कूड़े के निष्पादन का कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। कहां ध्यान भटकाने की बातें हो रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपके एफर्ट्स की प्रेज़ करता हूं । आप ऐसी अफसरशाही से बचिए। आपको जिले की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। आपने यहां पर जनमंच कार्यक्रम की बात कही। नग्गर में जनमंच हुआ। उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायतें आती हैं लेकिन मुझे वहां पर नहीं बुलाया गया। विधायकों को यदि आप जनमंच में नहीं बुलाएंगे और बोलने का मौका नहीं देंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। हम भी जनता के चुने हुए

प्रतिनिधि हैं। कृपया करके इन बातों का भी ख्याल रखें। आपने ग्रामीण विकास को बड़ा सुदृढ़ करने की बात की है। पिछले दिनों लगातार प्रयास हुए हैं कि किस तरह से इन संस्थाओं को कमजोर किया जाए। कुल्लू में जो हमारे पंचायत समिति के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तब लाया गया जब मैं विधान सभा के दौरे पर था। समय भी निश्चित किया गया। लेकिन किसी तरह हमने वहां पर विश्वास जीता है । मुख्य मंत्री महोदय, आज वहां पर जिस प्रकार से जिलाधीश, बी0डी0ओ0 और सरकारी ऑफिसर्ज़ काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को हम पैसा दे रहे हैं, उसे रोका जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक पंचायत में ऐसा पंचायत सचिव है, हमने 20,000 रुपये महिला मण्डल को दिया और एक पंचायत में उससे 45 कुर्सियां, एक अलमारी और 5 टाटें और एक टेबल मिल रहा है। लेकिन वह पंचायत सचिव खादी बोर्ड को ऑर्डर दे कर, आगे वह पैसा जाता है और उससे सिर्फ 9 कुर्सियां और एक अलमारी मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है और इन प्रावधानों को सरल क्यों नहीं बनाया जा रहा है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से मैं भी सुन रहा हूं, अब मुझे कुछ समय दीजिए।

अध्यक्षः प्लीज, मजबूरी है, आपके ही लीडर से बात हुई है। अच्छा एक कहावत सुना देता हूं। पहले समय में चिट्ठी लिखा करते थे और चिट्ठी के मज़बून को बादमें लिखते थे कि थोड़ा लिखे को ज्यादा समझा जाए। आज थोड़ा बोल रहे हैं, उसको मुख्य मंत्री जी ने ज्यादा समझ लिया।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा ही बोलूंगा, आप चिन्ता मत कीजिए। बहुत ही संक्षेप में सारी बातें होंगी। हमारे वहां पर भूभू टनल है। भूभू टनल का वहां पर प्रीलिमिनरी सर्वे किया गया है। कई महीनों से केन्द्र के पास पड़ा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा नेशनल-हाइवे वहां पर बन्द पड़ा है उसके ऊपर मुझे आज जो ज़वाब आया, वह भी कोई संतोषजनक नहीं था। आप गडकरी जी को मिलिए, उस पर

कुछ कार्रवाई कीजिए। आज मैं देख रहा हूं कि पर्यटन के दावे, मेरे पक्ष के साथियों ने यहां पर बहुत मेज़ें थपथपाई जब बताया गया कि हिमाचल इस बात के लिए अव्वल दर्ज़े में आया है, दूसरे दर्ज़े पर आया। लेकिन आज पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल दूसरे से 20वें स्थान पर गया, अब आप क्या करेंगे? यह इंडिया टूडे का सर्वे है। आप ज़वाब दीजिए। आप मेजें ऊपर से थपथपाएंगे या नीचे से थप-थपाएंगे? मेरा यह प्वाइंट है,

07-02-2019/1540/SS-DC/1

आज हिमाचल में जिस प्रकार से सहकारी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, आपने जगह-जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखे हैं और वे इन सहकारी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। यहां पर बताया गया कि आई0सी0डी0पी0 प्रोजैक्ट की वजह से सहकारी संस्थाओं को मजबूती मिल रही है। कुल्लू में आई0सी0डी0पी0 का प्रोजैक्ट पूरा हो चुका है और पैसा लैप्स होकर केन्द्र को चला गया क्योंकि सहकारी संस्थाओं को धारा-118 के तहत परमिशन लेनी पड़ रही है अगर उसने वर्कशैड भी बनाना है, वह उसके वश में नहीं है। कृपा करके आप इसका सरलीकरण कीजिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप कोशिश कर रहे हैं। आप हाइड्रो सैक्टर में ध्यान दीजिए। हिमाचल के हाइड्रो सैक्टर को मजबूती पूर्व मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी के वक्त में दी गई और बोनाफाइड हिमाचलीज़ को बहुत सारी परियोजनाएं सैंक्शन की गई थीं। लेकिन वे आज मात्र इसी वजह से ठण्डे बस्ते में पड़ी हैं कि हमारी पॉलिसी में नियामक आयोग द्वारा कुछेक त्रुटियां रखी गई हैं। मैं चाहूंगा, मंत्री जी यहां पर बैठे हैं कि कृपा करके इस सैक्टर को बाहर लाईये। इसके लिए कोई समयबद्ध योजना लेकर आईये।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्यटन के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी योजना की ज़रूरत है जोकि धरातल पर नज़र आए। भुंतर हवाई अड्डे पर बार-बार सर्वे हो रहे हैं। हमारा यह हवाई अड्डा सर्वे तक ही सीमित क्यों रहा

है? मंडी का भी हवाई अड्डा बने। जगह-जगह हवाई अड्डे बनें। कम-से-कम हिमाचल में एक तो बड़ा हवाई अड्डा होना चाहिए।

अंत में, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एक विशेष विचारधारा की बेड़ियों से बाहर निकल कर अफसरशाही पर प्रभावी नियंत्रण करके हिमाचल के विकास के लिए ऐसे प्रभावी कदम उठाएं जिससे हिमाचल शिखर पर पहुंचे। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नीरस था इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्षः अगर आप यह बात पहले बोल देते तो सारा भाषण समाप्त हो गया होता। श्री सतपाल रायजादा जी, 3:45 बजे अपराह्न माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर देना है, आप उससे पहले अपनी बात समाप्त करें।

श्री सतपाल सिंह रायजादाः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं दो-तीन बिन्दुओं पर बोलूंगा क्योंकि समय कम है।

मैं सबसे पहले स्वास्थ्य पर बात करना चाहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी बातें हुईं। मेरे ऊना की बात है। हर बार वहां पर जाना पड़ता है, वहां पर जाकर भी अगर डॉक्टरों को बोलते हैं तब भी वहां पर काम नहीं होता है। यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बोला कि 300 के आस-पास डॉक्टरों की एप्वाइंटमैंट हुई है। लेकिन महोदय 70 परसैंट डॉक्टर पड़ोसी राज्यों में अपनी सेवाएं देने चले गए हैं। आज चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राईमरी हॉस्पिटल हो, सारे-के-सारे हॉस्पिटल और हैल्थ सैंटर खाली पड़े हैं। आंकड़ों का जो खेल खेला जा रहा है वह बिल्कुल खोखला है। स्वास्थ्य का हाल मेरे हिसाब से पूरे हिमाचल प्रदेश में चरमराया हुआ है। मैं मंत्री महोदय को बोलूंगा कि आप खास करके ऊना ज़रूर आईये। अगर आप ऊना आयेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊना का हॉस्पिटल पी0जी0आई0 को रैफर करने वाला हॉस्पिटल बन गया है।

इसके साथ-साथ मैं स्कूलों और कॉलेज की बात करूंगा कि वहां पर स्टाफ की कमी है। लेकिन आप देखिये कि आज 31 प्रोफैसर्ज़ को डायरैक्टोरेट में लगा रखा है। मुझे नहीं पता कि वहां पर उनका क्या काम है। लेकिन हॉस्पिटल और कॉलेजों में लैक्चरार और टीचरों की कमी है।

महोदय, तीसरा बिन्दु मैं बोलूंगा कि इलैक्ट्रिकल और आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट में टेक्निकल स्टाफ की कमी है।

7.2.2019/1545/केएस/एजी/1

काम ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है और ठेकेदार दो-दो, तीन-तीन लोगों से काम करवाते हैं और 10-10 लोगों का पैसा ले रहे हैं। इससे सरकारी खजाने को चूना लग रहा है और लोग परेशान हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं खनन के बारे में बोलना चाहूंगा। सरकार चाहे कांग्रेस की थी या अब भाजपा की है। खनन पहले भी वैसे ही होता था और आज उससे दोगुना स्पीड में हो रहा है। सिर्फ अधिकारी बदल गए हैं। अधिकारी जो पहले होते थे, तब भी वे उसके ऊपर रोक नहीं लगा पाए और जो अब अधिकारी हैं, ये भी रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। जो खनन करते थे, वे भी वही लोग हैं। कोई बदलाव नहीं है। मैं कांग्रेस का हूं और खनन के मामले में मैं कांग्रेस की बात भी कर रहा हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सभी को इसके ऊपर सांझा प्रयास करना पड़ेगा। हमारे बड़े भाई ध्वाला जी बोल रहे थे कि काम बहुत हो रहे हैं, बच्चा अभी गोद में है, एकदम से चलना शुरू नहीं होता, अभी तो एक साल ही हुआ है। हमें तब शक होता है जब बच्चा पांच साल भी बड़ा नहीं होता, चलना शुरू नहीं करता। पांच-पांच साल हो गए हैं। जो एम.पीज़. द्वारा गोद में लिए हुए हैं उनको पोलियो हो गया है। वे चलने लायक नहीं रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ है। हमें शक है कि जो आपकी स्कीमें हैं, उनको भी पोलियो न हो जाए। हम समय-समय पर आपको चेताते रहेंगे। धन्यवाद और मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं।

अध्यक्षः महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर चर्चा की समाप्ति पर माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य आदरणीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने इस माननीय सदन में रखा और माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी ने उसका अनुसमर्थन किया, मैं उस पर सारी चर्चा के बाद उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब की बार यह बजट सत्र भले ही किसी कारण से छोटा करना पड़ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी माननीय सदस्यों का पार्टिसिपेशन, माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिला है और जो आज से पहले बजट सत्र होते रहे, वह उससे कम नहीं रहा है । मैं देख रहा हूं कि 18 माननीय सदस्य पक्ष के तथा 14 प्रतिपक्ष के यानि कुल मिलाकर 32 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया।

7.2.2019/1550/av/hk/1

आज से पहले भी बजट सत्र के दौरान सदन में माननीय सदस्यों की राज्यपाल महोदय के बजट अभिभाषण पर चर्चा करने की पार्टिसिपेशन लगभग यही रहती है। यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात बड़े प्रभावी ढंग से कही है जिसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। चर्चा के दौरान यहां पर कुछ सुझाव भी दिए गए और कमियां भी जाहिर की गईं। लेकिन मेरा यह मानना है कि मनुष्य जीवनभर सीखता है और कभी भी सम्पूर्ण नहीं बनता। जीवन में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कुछ बातें हटकर भी कही हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आखिरकार अपनी बात कहते-कहते अपना कवि होने का परिचय भी दिया। इन्होंने यहां अपनी कविता सुनाई और यह सुनकर मुझे संतोष हुआ कि हमारी मोहब्बत का असर हुआ है। जब कोई व्यक्ति शायरी सुनाने पर उतर आए तो समझ लेना कि असर हुआ है। आज मेरा आपसे एक निवेदन यह भी रहेगा कि बाहर मौसम बहुत खराब है, बाहर मत जाइए। हम आपको खराब मौसम में जाने की सलाह नहीं दे सकते, आप यहां पर आन्नद से बैठे रहें। आज मैं भी आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... मोहब्बत तो बहुत पुरानी है मगर हमने जाहिर नहीं होने दी।

भरोसा जीतना है तो ये खंजर फेंकने होंगे।

किसी हथियार से अमनो-आयाम कायम नहीं होता॥

इसलिए उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग भविष्य में अमन की राह पर चलेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर यही मान लें कि सच में कुछ नहीं हुआ तो ये सब क्यों हो रहा है? ये परेशानी, बेचैनी और हैरानी किस बात की है? अगर कुछ नहीं होता तो यह बेचैनी जो आपकी तरफ से जाहिर हुई है यह कई बार हमें सचमुच में बड़ा संतोष देती है कि हमने जो किया है, सही किया है यानी तीर ठिकाने पर लगा है। हमारा लक्ष्य यह नहीं होता कि आप हमारे काम से परेशान हों, हमारा लक्ष्य यह होता है कि हम बेहतर करें, अच्छा करें जिसके कारण आपको यह अनुभव हों कि काश हमने भी यह किया होता तो अच्छा होता। हमने भी बेहतर और कुछ हटकर करने की कोशिश की होती तो अच्छा होता। आप नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र हमें जब मिलते हैं तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि हम कहते थे कि कुछ करो, नया करो, हटकर करो। हम यह नहीं कहते कि आदमी खराब करने की मन्शा से ही काम करता है। जब कोई व्यक्ति या सरकार सत्ता में होती है तो सबकी यही कोशिश होती है कि सबकुछ अच्छा हो। लेकिन बावजूद उसके अच्छा नहीं हो पाया। आज अगर अच्छा हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से उस बात का यह परिणाम होगा कि जनता उसकी प्रशंसा करेगी। प्रदेश की जनता जो प्रशंसा कर रही है, हम उसको सुन भी रहे हैं। हमारी यहां आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हम वैचारिक रूप से अलग-अलग हैं जिसके कारण परेशानी निश्चित रूप से होती है और वह हुई है जो कि दिख भी रही है।

07/02/2019/1555/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

उसके बाद वह आपकी जुबान से यहां पर व्यक्त हुई है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार अच्छा करने की कोशिशें कर रही है। एक बात को लेकर हम हैरान है कि एक साल बीत गया, एक साल बीत गया। एक ही साल बीता है, चार साल अभी बाकी

है, ये भी देखना चाहिए। आप एक साल को ही क्यों गिन रहे हैं? बाकी बचे 4 साल भी तो गिनने चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के अनुसार आप सब जानते हैं कि सरकार की ओर से अभिभाषण बनकर तैयार होता है और महामहिम राज्यपाल महोदय उसको यहां सदन में पढ़ते हैं। एक स्थापित परम्परा है, जिसको आज से नहीं वर्षों से हम देख रहे हैं और उसका हमें आदर व सम्मान करना चाहिए। उसके बावजूद भी कहा गया कि बहुत दुःखी और निराश होकर महामहिम राज्यपाल महोदय को अभिभाषण पढ़ना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घण्टे के अभिभाषण में एक साल के कार्यकाल का ज़िक्र किया गया। लेकिन और अच्छा करने की अभी तक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और हम वह करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम उसको करें। लेकिन एक साल का कार्यकाल काम करते-करते बीता है, आराम करते-करते नहीं। इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो ज़िक्र हुआ है, वह काम का हुआ है, सिर्फ काम का ही ज़िक्र हुआ है।

आज यहां आपका प्रश्न भी लगा था, लेकिन जब प्रश्न का जवाब देने के लिए हम खड़े हुए तो आप बाहर चले गए। हम चाहते थे कि आप यहां पर रहे। नेशनल हाइवे के मुद्दे को आप सभी माननीय सदस्यों (विपक्ष) ने किसी-न-किसी रूप में छूने की कोशिश की। स्वभाविक रूप से यह आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि काम जल्दी हों। लेकिन जल्दी के लिए भी तो व़क्त चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में ये सारे नेशनल हाइवेज़ के प्रोजेक्ट की सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई थी? क्या यह भी सत्य नहीं है कि आपके (विपक्ष) व़क्त में कहा गया कि आप इनकी डी0पी0आर्ज का प्रोसैस शुरू कर दो? क्या यह भी सत्य नहीं कि है कि जब आपकी ओर से यह कहा गया कि डी0पी0आर्ज0 पर जो खर्च होगा, हम उसको करने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या यह भी सत्य नहीं है कि उसके बाद केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन

गडकरी जी ने केन्द्र से कहा कि डी0पी0आर्ज0 का खर्चा हम देगें? उन्होंने इसकी सैंक्शन भी दी। क्या यह भी सत्य है कि आपका कार्यकाल बीत गया और आप 69 नेशनल हाइवेज, जिनकी सैद्धांतिक नोटिफिकेशन हो चुकी थी, उनमें से आप मात्र 8 नेशनल हाइवेज़ की डी0पी0आर्ज0 ऑउटसोर्स करने का प्रोसैस शुरू कर पाए? और---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः यह भी सत्य है कि 65 हजार करोड़ रुपया नहीं मिला है।---(व्यवधान)---

अध्यक्षः प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद हमने इन डी0पी0आर्ज0 को आउटसोर्स करने का प्रोसैस तुरन्त शुरू किया और आज हमारी 50 डी0पी0आर्ज0 की आउटसोर्सिंग का प्रोसैस कंप्लीट हो गया है। हमने कोशिश की है, हम मंत्री जी से मिले और हमने प्रधानमंत्री जी से भी इस बात के लिए आग्रह किया। मैं यह कह सकता हूं कि जो बात कही गई है, हमें उस पर भरोसा है। कुछ बातों पर भरोसा भी करना चाहिए और हमें भरोसा है कि नेशनल हाइवे जो सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत हुए हैं, आने वाले समय में इसका नम्बर अलॉट होने के साथ-साथ इसको विधिवत् स्वीकृति भी मिल जाएगी और डी0पी0आर्ज का प्रोसैस आगे बढ़ेगा। अभी तो ये अंतरिम बजट है, उसके बाद माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बजट आएगा और वह चुनाव के बाद आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी हैरानी होती है। ---(व्यवधान)--- ये आप दिल बहला रहे हैं कि 3 प्रदेशों में आपकी सरकार आ गई। ठीक है,

07-02-2019/1600 /NS/YK /1

आपको राहत तो बहुत मिली लेकिन काम नहीं आएगी। क्योंकि देश को मोदी जी चाहिए। यह बात पक्की है और इस बात को आप (विपक्ष) मान कर चलिए। ---(व्यवधान)--- मैं इन बातों को यहां पर कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक दिन मैं टी0वी0 पर देख रहा था कि पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम हुआ और पूरे देश भर से विपक्ष में जितने भी बड़े-बड़े

लोग हैं, उनको इकट्ठा करके एक मंच पर खड़ा कर दिया गया। इसमें सच्चाई यह है कि थोक के भाव में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। ---(व्यवधान)--- आपने ज़िक्र किया है तो थोड़ा देश का भी ज़िक्र होना चाहिए। अगर आपने मोदी जी की बात की तो मुझे भी थोड़ा कहना पड़ेगा। यह वहां की बात नहीं है, कई बार तो हम यहां के हालात भी देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, थोक के भाव। ये परिस्थितियां बहुत अलग तरह की हैं और मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जनमंच की बात आई। जनमंच हमारी सरकार का एक कार्यक्रम है। मेरे लिए यह काम है। ---(व्यवधान)--- जुवां से कई बार कोई बात फिसल जाती है, उसको उस रूप में ही लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जब नई जिम्मेवारी मिली तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नया आदमी है। मैं सोचने लगा कि इतना नया भी नहीं हूं, आदमी तो पुराना हूं। मुझे विधान सभा के अंदर 20 साल हो गये हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नया है तो मैं कहना चाहता हूं कि जिम्मेवारी के हिसाब से नया हूं और पुराना भी जल्दी नहीं होना चाहता हूं। मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस जिम्मेवारी के साथ पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में जाना चाहिए। लोग मुझे सुनें, मैं लोगों को मिलूं और लोग मुझे मिलें और मैं उनकी बात सुनूं, उनकी बात को समझूं तथा मैं प्रदेश को समझूं और प्रदेश की समस्याओं को समझूं और लोग भी हमें समझें इसलिए मैंने हिमाचल प्रदेश में सभी विधान सभा क्षेत्रों के प्रवास के दौरान यह कोशिश की। मैं पिछली सरकार के कार्यकाल को भी देख रहा था तो आमतौर पर एक साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री का प्रवास 25 या 30 विधान सभा क्षेत्रों का होता है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने एक साल के कार्यकाल में 65 विधान सभा क्षेत्रों का दौरा किया। मैंने लोगों की समस्याओं को समझा और जाना तथा जिन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है उनको हल करने की कोशिश की। जब मैं प्रवास पर गया तो मुझे लगा कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास आते हैं। प्रदेश की आबादी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा गांव में रहता है। क्या यह संभव नहीं हो सकता कि गांव का आदमी गांव में रहे और सरकार जा करके गांव में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे? इस बात के लिए हमने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। इस दृष्टि से हमने इस कार्यक्रम की शुरूआत की, जिसका नाम 'जनमंच' रखा गया है। जनमंच के ज़िक्र से सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि लोग इस कार्यक्रम में आने लगे और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर होने लगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं जनमंच की बात कहूं तो

मुझे इस बात का संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में जनमंच आज तक की सरकारों के सफलतम कार्यक्रमों में से एक सफल कार्यक्रम है, जिसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों में विश्वास जागा है तथा जनमंच के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश से जितनी समस्यायें अभी तक आई हैं उनका समाधान करने में हम काफी हद तक सफल हुए हैं। अगर मैं इस आंकड़े का ज़िक्र करूं तो यह 24,424 है। इन समस्याओं का समाधान करने में हम सफल हुए हैं। अब आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं,

07.02.2019/1605/RKS/YK-1

हम सब लोग इन समस्याओं से वाकिफ़ है इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर गांव के आदमी को छोटी-छोटी बातों के लिए जैसे नकल-ततीमा निकालने के लिए पटवारी या कानूनगो के पास जाना पड़ता है लेकिन वहां पर पटवारी या कानूनगो नहीं मिलता है या कहा जाता है कि यह कार्य आज नहीं कल होगा। पैंशन का फार्म जमा करने के लिए जाएगा तो बाबू नहीं मिलेगा । पानी का कनैक्शन, बिजली का कनैक्शन, रास्ता बंद हो गया, सड़क टूट गई, पानी बंद हो गया, इन सारी चीजों को लेकर आदमी अपनी शिकायत लेकर जाता है ।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

कभी उन्हें नकल-ततीमा चाहिए या फिर राशन कार्ड बनाना हो तो इस तरह की रोजमर्रा की बहुत-सी समस्याएं हैं। इसलिए हमने सोचा कि गांव का आदमी गांव में रहे और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी सरकार का मंत्री अधिकारियों के साथ गांव में जाए और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर करे। मुझे इस बात की खुशी है कि यदि किसी को मैडिकल सर्टिफिकेट चाहिए हो तो उसे डॉक्टर की टीम मौके पर बैठकर मैडिकल सर्टिफिकेट उसके हाथ में देती है। लोगों को नकल-ततीमा मौके पर दिया जा रहा है। किसी का पानी, बिजली का कनैक्शन लगना है तो उसके लिए मौके पर आदेश दिए जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के गांव के लोगों का footfall शहर में, दफ्तरों में कम हो और उनकी समस्याओं का समाधान गांव में ही हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कोशिश की है। गांव में ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सके इसलिए जनमंच के माध्यम से हमने यह कार्य शुरू किया है। लगभग 26,700 शिकायतों का निवारण इस जनमंच के माध्यम से किया गया है। अभी तक 65 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में 106 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 30, 335 मांग पत्र व शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें से 26, 699 मांग पत्र एवं शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल जनता की समस्याओं का निपटारा किया गया है बल्कि 277 स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए जिसमें 45 हजार लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ। यह मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में खुद देखा है कि स्वास्थ्य कैंप में जो डॉक्टर्ज की टीम आई थी वह सुबह से शाम तक लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करती रही जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फायदा हुआ है। इसके अतिरिक्त 5, 269 इंतकाल निपटाए गए और 799 योजनाओं का निरीक्षण भी किया गया। 28,225 प्रमाण पत्र जारी किए गए, 21,800 लाभार्थियों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कागज पूर्ण करवाए गए। जिस कागज के चक्कर में आदमी की चक्करी बन जाती थी उसके लिए मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। 569 ग्राम पंचायतों और 121 अन्य स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में हमने सफाई अभियान की व्यवस्था भी की है ताकि गंदगी भी साफ की जाए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4.23 लाख डिजिटल राशन कार्ड जारी किए गए जोकि बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1.46 लाख लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। 36,162 गर्भवती माताओं का पंजीकरण किया गया तथा 351 शौचालयों के निर्माण की मंजूरी दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जनमंच के संदर्भ में यह कहना है कि आखिरकार जनमंच क्यों होना चाहिए? अभी माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी

कह रहे थे। यह हमारे रिस्तेदार भी हैं लेकिन बातें बहुत करते हैं। मैं भी सराजी आदमी हूं यानी पिछड़े इलाके का आदमी हूं। जो पिछड़ा हुआ आदमी होता था उसे एक जमाने में सराजी कहा जाता था। मैं यह कहना चाहता हूं जब

07.02.2019/1610/बी0एस0/डी0सी-1

इस कार्यक्रम के संबंध में आपके क्षेत्र में जाते हैं तो आपको बोलने के लिए भी पूर्ण अवसर दिया जाता है। आपको बुलया भी जाता और भाषण देने का अवसर भी दिया जाता है। एक-आधे कार्यक्रम की बात हो सकती है जिसमें किसी को बोलने का मौका न मिला हो अन्यथा हमने सब जगह बोलने का पूरा मौका दिया है। आप जनमंच में भी आ सकते हैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनमंच के कार्यक्रम के माध्यम से गांव के लोगों में एक विश्वास जगा है। यहां कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि यह तो पहले भी चलता था । चलता था, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। परंतु वह "प्रशासन जनता के द्वारा" कार्यक्रम चलता था।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : वही यह कार्यक्रम है आपने इसका नाम बदल कर जनमंच कर दिया।

मुख्य मंत्री : जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चलाया जा रहा है। हमने किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं पूछा कि आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं। एक माइक सामने लगा होता है वहां पर मंत्री बैठे होते हैं और सामने अधिकारी बैठे होते हैं। जिस आदमी की समस्या होती है उसको कहा जाता है कि माइक पर अपनी समस्या का जिक्र करें। उसे समस्या के बारे में जो बोलना होता है उस बारे में सब-के-सब मंत्री और अधिकारी सुनते हैं। उसके बाद उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। यहां बात कही गई कि आप अधिकारियों को धमकातें है। परंतु मैं यहां कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार में एक डी.सी. के आर्डर भाषण करती बार मंच से ही कर दिए गए थे। ऐसा भी तो हुआ है । जो कार्य करने वाले अधिकारी होंगे उनको शाबाशी भी मिलेगी। लेकिन जिनकी काम करने

की नियत ही नही होगी। उनको पूछा भी जाएगा और उनको पूछना भी पड़ेगा। आखिर हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और उसका हल भी होना चाहिए उसे हम करते भी हैं।

अब दूसरी बात आती है कि आपने हैलिकॉप्टर को साईकिल बना दिया। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हैलिकॉप्टर प्रदेश की सेवा के लिए लिया गया है।

इस बात का जिक्र मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह की बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है । मुझे इस बात की प्रशंन्नता है। ...(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप किसी योजना और प्रोजैक्ट की बात करिए। आप जनमंच की ही बात न करें। आपने कहा था कि कर्जा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, इस पर बात करिए। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : मैं उसी पर आ रहा हूं। जनमंच सरकार का कार्यक्रम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बातें आप लोगों ने कही हैं उसी का उत्तर में दे रहा हूं। जिन बातों का जिक्र यहां से हुआ है उसका उत्तर भी मुझे देना है। इस पर ऐसे मत बोलिए । आपने पिछले कल भी कह दिया कि मंत्री जी ने यह बात कही, क्या आप इस बात को तय करेंगे कि हमें बोलना है या नहीं बोलना है? यह तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। यदि आपने यहां पर प्रश्न खड़े नहीं किए होते तो हम नहीं बोलते। यह प्रश्न आपके द्वारा ही खड़े किए गए हैं। अब इनका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हैलिकाप्टर के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। वर्ष 2016 में हैलिकॉप्टर पर खर्च हुआ 8.31 करोड़ रुपये वर्ष 2017 में हैलिकॉप्टर पर खर्चा हुआ उड़ान का 8.78 करोड़ रुपये और वर्ष 2018 में हमने खर्च किया 7.89 करोड़ रुपये और

यहां पर शोर मचाया जा रहा है । मुझे एक बात को लेकर बड़ी हैरानी हो रही है। माननीय सदस्य जो ट्राइब्ल इलाके से हैं, ठण्डे इलाके से है, आज तो कम से कम ठण्डा रहिए। हम कहते है कि हैलिकॉप्टर ये तो ट्राइब्ल के लिए लिया गया, कही नहीं। ये जो हैलिकॉप्टर लिया गया है ये सरकार का है। ---(व्यवधान)---अब कम से कम इस बात को लेकर आपके जो अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी हम भी बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए ट्राइब्ल सब प्लान से नहीं चलता है। हैलिकॉप्टर आपकी जानकारी के लिए---(व्यवधान)---मैं एक-एक बात का जवाब देना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि ---(व्यवधान)---अच्छा अगर आप उसके बारे में जिक्र कर ही रहे हैं तो मैं वही थोड़ी सी बात कह लेता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि हैली टैक्सी, हमारी अभी भी मन्शा है और वह हम कर रहे हैं। हैली टैक्सी होकर रहेगी यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। लेकिन हमने कहा कि वह अभी शुरू नहीं हो पा रही है उसमें विलम्भ हो रहा है, देर हो रही है। ये खाली पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। हैलिकॉप्टर आप जब जाते तब इस्तेमाल कर लेगें, लेकिन जब नहीं जाते हैं तब देना चाहिए। लेकिन हमारे अधिकारियों ने कहा कि हमें इसमें तय करना पड़ेगा कि अगर आपको इसमें जाना है तो हमें इसे तीन दिन बंद करना पड़ेगा। तीन दिन देना है तो हमें बुकिंग के लिए पहले ही तय करना पड़ेगा कि किस-किस तारीख को जायेगा और मैंने कहा भी है कि हफ्ते के तीन दिन हैलिकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैंने नहीं किया। हमने इस हेलिकॉप्टर की शुरूआत 4 जून, 2018 से की और लगभग 400 पर्यटकों ने इसमें आने-जाने की सुविधा का आनन्द लिया। बाद में जब बरसात का मौसम आया तो हेलिकॉप्टर के इंजन में खराबी आ गई और मैजर रिपेयर के लिए इसको ग्राउंड करना पड़ा। इसको ठीक करने के लिए रशिया से इंजीनियर्ज की टीम को आने में 2 महीने का व़क्त लग गया और तब तक सर्दी का मौसम आ गया। आज से पहले 1955 में ऐसी स्थिति हुई थी जब सितम्बर के महीने में लाहौल-स्पीति में 5 फुट बर्फ पड़ी थी और अबकी बार फिर पड़ी है। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि हेलिकॉप्टर को हम टूरिज्म को नहीं

दे सकते हैं। हमें इसका ट्राइब्ल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और आज की तारीख में ट्राइब्ल के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप थोड़ा सा इंतजार करें, जितनी चिन्ता आपको है, उससे कम हमको भी नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा कनेक्टिविटी की आती है। इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और संभव हुआ तो इसी महीने में उड़ान-॥ के अंतर्गत चण्ड़ीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू और शिमला से धर्मशाला के लिए हमारी उड़ान शुरू होने जा रही है। इसके लिए हमने मंत्रालय में भी बात की है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। ---(व्यवधान)--- उड़ान-। चली हुई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है। जो खर्च करने की जो बात थी, उसके बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर व अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए उपदान पर हेलिकॉप्टर सेवाएं देने की एक योजना थी जिसको हिमाचल प्रदेश में लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा 10 मार्गों पर उड़ान करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। 2016 से लेकर मार्च, 2018 तक भारत सरकार से कोई भी राशि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त नहीं की गई। लेकिन हमारे प्रयासों से गत वर्ष 7.38 करोड़ रुपये सितम्बर, 2018 तक प्राप्त हुए हैं

07/02/2019/1620/RG/DC/1

जो पहली बार भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। जितना हमने हैलीकॉप्टर पर खर्च किया, उतना पैसा प्रदेश की ओर से नहीं बल्कि हमने केन्द्र सरकार से वह पैसा लिया, यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं और भाईसाहब, यह ट्रायबल सब-प्लान का पैसा नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं। ---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

मुख्य मंत्री : कुछ बातों का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार तो पाचं सालों के लिए है जिसका अभी एक साल बीता है और आप कह रहे थे कि आपने यह नहीं किया, वह नहीं किया। हमारे पास तो करने के लिए समय है और चार साल

बाकी हैं। लेकिन मैं आपके समय का थोड़ा सा जिक्र करूं, क्या आप सुनेंगे? मेरी बात आप सुन लीजिए। जिक्र तो होगा, यह क्या बात हुई? जब जिक्र मुहब्बत का हुआ है तो दोनों तरफ से होना चाहिए। जब आपकी सरकार थी, यह वर्ष 2015-16 का बजट है और बजट भाषण का यह 123वां पैरा है, "Helicopter services from Chandigarh to Shimla and other tourists places will be started soon". यह आपने कहा था। ---(interruption)---. लेकिन समय निकल गया, इधर से उधर चला गया। आप यहां से उधर उस हैलीकॉप्टर में चले गए। लेकिन आप लोग हमें कह रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सारी बातों का जिक्र करूं, वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में कहा गया कि "State Commissioner, Public Grievances is to be appointed very soon", but it was not implemented. This is mentioned in the Para-10 of the Budget Speech of 2013-14. ---(Interruption)---.

श्री मुकेश अग्निहोत्री : तो आप क्या कहते हैं कि इस बजट में जो लिखा है वह पूरा नहीं करना है।

मुख्य मंत्री : नहीं-नहीं, हम अपनी बात तो पूरी करेंगे, आप तो हमसे ही हिसाब मांग रहे हैं। मैं इनका बीच-बीच में जिक्र करता रहूंगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। मैंने संभालकर ये पेज रखे हुए हैं, ये ठीक हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : वे तीस योजनाएं कहां गईं? राम राज्य कहा गया?

मुख्य मंत्री : राम राज्य यही स्थापित है और राम राज्य इसी को कहते हैं जो आप आजकल देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने तीस योजनाओं की बात की। हां, हमने तीस योजनाएं कही हैं। ऐसा है कि यह भाषण लम्बा हो जाता और आप कहते कि यह बहुत लम्बा भाषण कर दिया। इसलिए हमने आपकी सुविधा के मुताबिक थोड़ा ख्याल रखा है। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जो हमने नए इनिशियेटिव लिए हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। यदि मैं सच कहूं तो बजट पास हुए अभी सिर्फ नौ महीने हुए हैं और नौ महीने में आप उम्मीद करते हैं कि बजट में हमने जितनी भी योजनाओं की घोषणा की है, वे योजनाएं आपको जमीन पर उस रूप में मिलें। लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की

खुशी है कि जितनी योजनाओं का हमने जिक्र किया है, उनमें से अधिकांश योजनाएं शुरू हो रही हैं, कुछ जगह पर दिक्कत आई है, कुछ चीजों को लेकर दिक्कत आई है। कई बार जब मुसाफिर सफर पर चलता है तो मालूम नहीं पड़ता कि मंजिल तक पहुंचने में कहां कौन सी बाधा या दिक्कत आ जाएगी। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है। आप भी कई बार सफर पर चलते-चलते ठोकर खाए होंगे, कई जगह रुके होंगे और उम्मीद के हिसाब से आपको जहां पहुंचना था, वहां समय पर नहीं पहुंच पाए होंगे। ऐसी परिस्थिति कई बार आती है। लेकिन उसके बावजूद हमने योजनाओं की शुरूआत की है।

माननीय अध्यक्ष जी, गृहिणी सुविधा योजना का जिक्र आया, हमने उसमें पैरे में लिख दिया और देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश में धूंआमुक्त चूल्हा हर घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वह एक अच्छी पहल थी

7/02/2019/MS/1625/DC/1

और उसकी आवश्यकता पूरा देश महसूस कर रहा था। उस योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश ने भी बहुत लाभ लिया। हमें लगा कि हिमाचल प्रदेश में उसे और ज्यादा मजबूत करने की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है तो हमने हिमाचल प्रदेश में उस "उज्ज्वला योजना" को फरदर सप्लीमैंट करने के लिए "गृहिणी सुविधा योजना" की शुरुआत की और इस योजना के अंतर्गत मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः मुकेश अग्निहोत्री जी, कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलने दीजिए। ऐसा नहीं होता है। ...(व्यवधान)...माननीय मुख्य मंत्री जी, एक मिनट के लिए बैठिए। ...(व्यवधान)...मुकेश अग्निहोत्री जी आप बिना व्यवधान के 45 मिनट बोले और अब आप मुख्य मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...मुकेश अग्निहोत्री जी, क्या आप इस बात को डिसाइड करेंगे? आप अपनी जगह पर बैठ जाइए...(व्यवधान)...
(पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

कृपया दोनों पक्षों के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।...(व्यवधान)...बैठिए, बैठिए।

(विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

माननीय मुख्य मंत्री जी, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं यह कहना चाहता हूं कि

7.2.2019/1630/जेके/डीसी/1

सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर समय की परिधि में रहते हुए दिया गया। उन्हीं की सभी बातों का उत्तर देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हैं। ऐसे समय पर बार-बार माननीय मुख्य मंत्री जी को इन्टरप्ट करना शोभा नहीं देता और सदन की परिपाटी के विपरीत है। माननीय मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर आगे जारी रखें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे आप इस तरफ हो, चाहे उस तरफ हो, कम-से-कम उसके प्रति सम्मान और विश्वास बहुत आवश्यक है। मैं देख रहा था कि जितनी भी इस माननीय सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई, सभी माननीय सदस्यों ने इस ओर से शांतिपूर्वक ढंग से सुना है। कहीं किसी को इन्टरप्ट नहीं किया। यह राजनीति सिर्फ राजनीति है। हर जगह राजनीति से लाभ ही नहीं होता बल्कि कई बार नुकसान भी होता है। मैं इस बात को देख रहा हूं कि वहां की परिस्थिति ऐसी है कि नेतृत्व किसके हाथ में है, वह भी थोक के भाव हो गया है। जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि वह जा करके कलकत्ता में देखने को मिला। थोक के भाव प्रधान मंत्री मंच पर हो गए। आजकल प्रदेश में भी हम इसी को देख रहे हैं कि थोक के भाव नेता हमारे विपक्ष में हो गए इसलिए कौन इनको दिशा देगा, कौन इनका मार्गदर्शन करेगा? यह इनका अपना संकट है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन कम-से-कम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही है, चर्चा का उत्तर दिया जा रहा है और तथ्यों पर दिया जा रहा है, उनके माध्यम से कुछ बातें इस

प्रकार से उठाई गई जिनका ज़वाब देना लाज़मी है, उनको कम-से-कम सुन के जाना चाहिए। ये किसी भी बात पर सहमत नहीं हैं। अपनी बात अंत में कहते लेकिन बात को सुन करके जाना चाहिए। यदि उनको अपनी बात कहने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार है तो यह अधिकार हमारे पास भी उतना ही है, उनसे कम नहीं है इसलिए उनको इस बात को समझना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जो यहां पर परिस्थितियां हुई उनकी मैं निन्दा करता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैं अपनी बात को आगे जारी रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि पैसा कितना आया? हमारे सभी साथियों ने, सभी मंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया कि 9 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा केन्द्र से प्रोजैक्ट के माध्यम से हिमाचल को मिल रहा है लेकिन इनकी बात यह है कि पैसा कितना आया? इनका पांच साल का कार्यकाल बीत गया और अपने कार्यकाल में इन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हमारे पास अपने वित्तीय संसाधन नहीं हैं। अगर प्रदेश का विकास करना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए केन्द्र से मदद का रास्ता कैसे निकलेगा? उस वक्त भी हजारो, करोड़ों रुपये आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने इनको बिना मांगे हिमाचल के विकास को दे दिए क्योंकि हिमाचल से उनका अपना लगाव था और अपनापन था। हम यहां इसी सदन में कहते रहे कि एक शब्द धन्यवाद का तो कह दो, लेकिन इनके मुंह से नहीं निकला। हम ऐसे नहीं हो सकते हैं। जब इनकी सरकार थी उस वक्त भी हमने इस प्रकार से नहीं किया। अगर केन्द्र से मदद आई है तो हमने उसका धन्यवाद किया है। उस वक्त के मुख्य मंत्री जी ने भी यहां से धन्यवाद किया है लेकिन अब ये परम्परा ही समाप्त हो गई। जिस बात का वे जिक्र कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि केन्द्र से कितना पैसा आया, मैंने स्पष्ट कहा कि पैसा किसी की जेब में नहीं जाएगा। पैसा अगर केन्द्र से आएगा तो प्रदेश के विकास में लगेगा। गरीब लोगों की मदद के लिए वह पैसा लगेगा। वह दौर खत्म हो गया, वह ज़माना निकल गया जब पैसा आता था और पैसा आने के बाद फिर ये सारी चीजें शुरू हो जाती थी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र में जितने भी हमारे प्रोजैक्ट्स हैं, जो यहां से विभाग की ओर से भेजे गए, मैं सभी मंत्रियों का

धन्यवाद करता हूं, उनको और अपने अधिकारियों को बधाई देता हूं जिसके लिए उन्होंने मेहनत की है।

07-02-2019/1635/SS-HK/1

आखिरकार वे प्रोजैक्ट हमने केन्द्र में रखे, अपना पक्ष बार-बार रखा है कि हमको पैसे की आवश्यकता है। धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोजैक्टस बहुत ज़रूरी हैं। मैं स्वयं बार-बार प्रधान मंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों से मिलने जाता रहा हूं और बात करता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका सार्थक परिणाम निकला। आज 10300 करोड़ रुपये केन्द्र से एक्सटर्नली ऐडिड प्रोजैक्टस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत हुए हैं। मैं कह सकता हूं कि आज तक के इतिहास का यह सबसे बड़ा अमाऊंट है जोकि हमको केन्द्र सरकार से एक्सटर्नली ऐडिड प्रोजैक्टस के माध्यम से स्वीकृत होकर आ रहा है। इसको हमने एक साल के कार्यकाल में स्वीकृति दिलाने में सफलता हासिल की है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी ने शोर डालना है तो डालते रहें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कानून-व्यवस्था के बारे में कहा गया। मैं कहना चाहूंगा कि हम कानून-व्यवस्था की परिस्थिति पर इतना भी न बोलें कि पूरे प्रदेश और देश भर में इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर दें कि कानून-व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में इतनी खराब हो गई है कि जिस हिमाचल प्रदेश को देश दुनिया में देवभूमि के नाम से जाना जाता है वहां पर लोग आने में सोचने के लिए विवश हो जाएं। यह परिस्थिति अपने हाथों से इस तरह से नहीं बनानी चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश देश भर के उन प्रान्तों में से एक है जहां सबसे बेहतरीन कानून-व्यवस्था है। अगर हम आंकड़ों की तफ़सील में जाएं तो आंकड़े हमारे सामने पड़े हैं। वर्ष 2018 में 19594 अभियोग पंजीकृत हुए। जबकि 2017 में थोड़ा इससे कम 17804 अभियोग पंजीकृत हुए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं कि इसमें 32.8 प्रतिशत की वृद्धि ड्रग्स के इश्यु को लेकर हुई है। इसका कारण क्या है? पहले ड्रग्स का धंधा चलता था, उसमें बड़े लोग भी शामिल होते थे। अगर मामला कहीं दर्ज़ होने की नौबत आती थी तो उसको दफ़न कर दिया जाता था। कोई पकड़ा जाता था तो छोड़ दिया जाता था, कहा जाता था कि छोड़ दीजिए। लेकिन हमने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं है चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो,

हमने कहा कि इस सारी चीज़ को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। हमने कहा कि ड्रग्स के लिए हिमाचल प्रदेश में गुंजाइश नहीं हो सकती है। इसके लिए हमने अभियान भी चलाया और अभियान के साथ-साथ अगर हमको लगा कि कानून को सख्त करने की आवश्यकता थी तो उसके लिए भी हमने कदम उठाया। हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के मामले को लेकर जिस प्रकार से हमने शिकंजा कसा, उसका परिणाम यह हुआ कि लोग जो पकड़े गए, उनमें केस दर्ज हुए। ड्रग्स की तस्करी कोई करता था तो मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुईं। जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए। इसके कारण केसिज़ का नम्बर बढ़ा है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था खराब हो गई है। इसका पैरामीटर यह है कि जब मामले दर्ज हुए तो स्वाभाविक रूप से हमने सख्ती की होगी। इसमें और सख्ती करने की आवश्यकता है।

अगर हम हत्या की बात करें तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 2018 में 98 अभियोग हत्या के मामले में दर्ज हुए। इसमें अधिकतर मामले सुलझाये जा चुके हैं जिसकी प्रतिशतता 90 प्रतिशत है। पहले बहुत सारे मामले ऐसे होते थे कि हत्या हो जाती थी तो वे ट्रेस नहीं होते थे। लेकिन हमने बहुत सख्ती की और मैं सारे पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं कि इंवैस्टगेशन का प्रोसैस बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया और ऐसे मामले जो अनट्रेसड रहते थे उनको ट्रेस करने में सफलता हासिल की है।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम इससे आगे बढ़कर बलात्कार के मामलों की बात कहें तो 2018 में बलात्कार के 345 अभियोग पंजीकृत हुए। जबकि 2017 में इस शीर्षक में 250 अभियोग पंजीकृत हुए थे।

7.2.2019/1640/केएस/एचके/1

प्रदेश पुलिस महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के प्रति संवेदनशील है तथा अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रयत्नशील है। गुड़िया हैल्प लाइन, एस.एम.एस., व्हाट्स एप एवं ऑन लाइन शिकायत पोर्टल की सुविधाओं तथा सामुदायिक पुलिस योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरुकता अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं में जागरुकता बढ़ी है तथा वे निर्भय हो कर अपनी शिकायतें दर्ज करवा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले क्या होता था कि महिला के खिलाफ मामला आता था उसको रफा-दफा करने की कोशिश होती थी और आज के दौर में हमने कोशिश की है कि किसी भी महिला के साथ अगर किसी भी प्रकार की बात होती है तो उस पर मामला दर्ज होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अवैध खनन के बारे में कहना चाहूंगा। मैं अपने लिखित उत्तर में से बहुत सा पोर्शन छोड़ रहा हूं, इसको मैं रिकॉर्ड के लिए सदन के पटल पर भी रख दूंगा लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि खनन एक बहुत बड़ा विषय था जो पिछली सरकार के समय खुला चलता था। खनन माफिया एक ऐसा माफिया था जो सरकार को चला रहा था। उन खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने की बात हम उस वक्त भी करते थे लेकिन नहीं हुआ। आखिरकार ऐसे माफियाओं के कारण ही सरकार खुद उस खनन में दफ़न हो गई। इसलिए हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश में खनन माफियाओं के साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगें । वर्ष 2018 में पुलिस विभाग द्वारा अवैध खनन के 6,789 चालान किए गए हैं तथा दोषियों से 3 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि जुर्माने के तौर पर प्राप्त की गई है । इसके अतिरिक्त अवैध खनन के 36 अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं जबकि वर्ष 2017 में पुलिस विभाग द्वारा अवैध खनन के 5,378 चालान किए गए थे तथा दोषियों से 2 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि जुर्माने के तौर पर प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त अवैध खनन के 32 अभियोग पंजीकृत किए गए थे । अधिक संख्या में खनन के परमिट देने के बावजूद भी सख्त कार्रवाई कर खनन माफिया के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाई की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था से सम्बन्धित कुछ विषयों पर हमने अपनी बात कही। मैं अभी भी कह सकता हूं कि छोटी सी घटना होती है तो अनावश्यक रूप से उसको बड़ा कर दिया जाता है। हम मानते हैं कि घटना घटित नहीं होनी चाहिए, वह छोटी हो या बड़ी । वह चाहे बलात्कार की घटना है या मर्डर की घटना है, नहीं होनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी घटित हो रही है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इनको कैसे

रोका जाए क्योंकि आज पूरे देश व दुनिया में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं कि जो अपराध करने वाला आदमी गलत मनोस्थिति का होता है वह अपने काम को अन्ज़ाम देने के लिए कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से कोशिश करता है लेकिन उसके बावजूद जरूरी यह है कि अगर कोई गलत करता है, इस प्रकार का अपराध करता है, वह अपराधी न छूट सके। इस बात को हमने सुनिश्चित किया है कि हिमाचल प्रदेश में कोई अपराधी, वह चाहे छोटा है या बड़ा, अपराधी जो भी है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई हो, यह हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर लोक भवन के बारे में कहा गया। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक योजना शुरू की है। हमको यह लगता है, हम खुद गांव के रहने वाले हैं, गांव में जा कर लोगों के लिए कोई सार्वजनिक स्थान ऐसा नहीं होता जहां किसी बड़े कार्यक्रम को ले कर बैठने की व्यवस्था हो। सर्दी, बारिश या गर्मी का मौसम हो तो गरीब आदमियों को कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि प्रत्येक विधान सभा में हमें ऐसे स्थान तय करने चाहिए और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त हमारी ही सरकार थी, हमने हिमाचल प्रदेश में सभी विधान सभा क्षेत्रों में अम्बेदकर भवन की शुरूआत की थी और जहां अनुसूचित जाति के बड़े गांव हैं, उन गांव में वे भवन बनाए गए थे। आज भी मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जाता हूं तो अगर मौसम खराब हो जाता है तो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम उन्हीं में किए जाते हैं। मुझे लगा कि इसकी और जगह भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि यह भवन तो एक विधान सभा क्षेत्र में एक जगह ही होगा लेकिन और जगह भी कार्यक्रम करने हैं तो उसके लिए लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि हम एक शुरूआत और करते हैं इसलिए हमने मुख्य मंत्री लोक भवन की शुरूआत की । यहां शोर डाला गया कि एक भी भवन नहीं बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस योजना के दिशा-निर्देशों पर मंत्री परिषद के अनुमोदन के उपरांत 30 जून, 2018 को विभाग द्वारा योजना की अधिसूचना जारी की गई थी औ

इसी तरह से दिनांक 1 जुलाई, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक 6 माह की इस अवधि में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश में 68 विधान सभा क्षेत्र में से 41 विधान सभा क्षेत्र के लिए लोक भवन की स्वीकृति प्रदान की गई और 25 लाख रुपये प्रथम किस्त के रूप में जारी भी कर दिए गए हैं। उसके बावजूद मुझे मालूम नहीं कि ये लोग अपने विधान क्षेत्र में रहते भी हैं या नहीं रहते। ये लोग रहते कहां हैं? यह राशि अधिकांश विधान सभा क्षेत्र के लिए जारी कर दी गई है। हमने पिछली बजट स्पीच में यह भी कहा है कि एक जगह 30 लाख रुपये की लागत से सरकार देगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि यह बहुत कामयाब है तथा इसकी आवश्यकता और महसूस की जा रही है तो ऐसी परिस्थिति में सम्बंधित विधायक तय कर सकता है। उसके लिए स्थान का चयन भी विधायक ही कर सकता है जिसके लिए 15 लाख रुपये सरकार देगी तथा 15 लाख रुपये की राशि सम्बंधित विधायक अपनी विधायक निधि में से देगा। इस तरह से दूसरा लोक भवन भी बनाया जा सकता है। उसके बावजूद भी जो जमीन पर मिल रहा है या दिख रहा है उसके बारे में भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त यहां पर सड़कों के बारे में चर्चा की गई। लेकिन मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत पश्चात यानी वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्तुत होने से पहले हमने सौ करोड़ रुपये सड़कों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत किए थे। उसके बाद हमने जब वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट रखा तो यह सोचा गया कि सड़कों का रख-रखाव बहुत आवश्यक है और इसमें बहुत कम पैसा होता है। इसमें 30-35 करोड़ रुपये की राशि रखी जाती थी जो कि बहुत कम होती है। इसलिए हमने कहा कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए हमने पिछले पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सड़कों के रख-रखाव हेतु सौ करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

हमारे प्रदेश में मौसम के कारण काफी दिक्कतें रहती हैं। यहां पर सर्दी में जब बर्फ पड़ती है तो सड़कें टूट जाती हैं। सर्दी के बाद सड़कें ठीक करते हैं और उसके पश्चात बरसात की वजह से सड़कें फिर टूट जाती हैं जिसके कारण हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सड़कों के रख-रखाव का प्रश्न है प्रदेश में कुल 36276 किलोमीटर सड़कें हैं जिसमें से 26543 किलोमीटर पक्की सड़कें बन चुकी हैं जिनकी पीरियोडिकल रीन्युअल हर 5 वर्ष के बाद आवश्यक है। जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष लगभग 5300 किलोमीटर सड़क की 5 सालाना रीन्युअल स्टेट फंड से करवाना अति आवश्यक है। अधिक धन उपलब्ध करवाने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग द्वारा जहां पहले औसतन 1800 किलोमीटर सड़कों की पीरियोडिकल रीन्युअल की जाती थी चालू वित्त वर्ष 2018-19 में 15 जनवरी, 2019 तक 2282 किलोमीटर सड़कों की पीरियोडिकल रीन्युअल की गई जो आज तक का एक रिकॉर्ड है। हम इस बात से भी सहमत हैं कि उसमें और व्यवस्था करने की आवश्यकता है क्योंकि जब सड़कें ठीक होंगी तो स्वाभाविक रूप से बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी यह महसूस करता है कि इस प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। अगर सड़कें ठीक नहीं होती हैं तो उसके दिमाग में एकदम से यह इम्प्रैशन बन जाता है कि प्रदेश में बाकी काम भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसलिए आने वाले समय के लिए भी हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम सड़कों के रख-रखाव पर ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान दें।

यहां पर गोसदन के बारे में भी बात हुई। हालांकि इसके बारे में जो आज प्रश्न लगा था उसके उत्तर में यह कहा गया कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। लेकिन हम इस सारे मामले को लेकर गम्भीर हैं और हम उस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश में बेसहारा गोवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए गो अभ्यारणों व जिला स्तरीय बड़े गो सदनों की स्थापना की जा रही है। इसके अंतर्गत जिला ऊना के थानाकलां में 1.70 करोड़ रुपये, जिला सोलन के हांडा-कुंडी में 2.97 करोड़ रुपये, जिला सिरमौर के कोटला-बड़ोग में 1.52 करोड़ रुपये तथा जिला कांगड़ा के इन्दौरा में 3.55 करोड़ रुपये की लागत से इनके निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने गौसदनों और गौशालाओं की वित्तीय सहायता के लिए भी मंदिर न्यासों की कुल आय का 15 प्रतिशत भाग देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके संदर्भ में मैंने अधिकारियों से बात की है कि जो पैसा हमने मंदिर ट्रस्टों से लेना है वह जल्दी-से-जल्दी लिया जाए ताकि 'गऊ संवर्धन आयोग' जो हमने आयोग के रूप में इस कार्य की मॉनिटरिंग करने लिए स्थापित किया है, वह ठीक प्रकार से संचालित हो सकें। ताकि आने वाले समय में कोई भी गाय सड़कों व चौक-चौराहे पर न दिखे और उनके लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए। ऐसी हमारी कोशिश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यहां किसानों के बारे में बात कही गई। क्या हमारा हिमाचल प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? अगर आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे देश को लाभ मिला है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी उस योजना से 22 लाख लोग लाभान्वित होंगे। क्या ऐसी परिस्थिति है कि जहां एक गरीब आदमी को अपने इलाज के लिए 5 लाख रुपये मिलेगा और हम महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका ज़िक्र न करें। मुझे लगता है कि इस प्रकार से सोच में बहुत संकीर्णता आई है। अगर मैं कृषि के क्षेत्र की बात करूं तो हमने पिछली बार हिमाचल प्रदेश में एक नया प्रयास किया है और 25 करोड़ रुपये से प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाया है। वह सफलतापूवर्क आगे बढ़ रहा है। इसके साथ-साथ प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना भी हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने इसका बहुत ज़िक्र किया कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। मुझे नहीं मालूम कि वे कहां से ये सारी चीजें लेकर आई है। गत वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 234831 किसानों को फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया गया तथा 68863 किसान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए। जिन्हें 12.74 करोड़ रुपये का मुआव़जा दिया गया। मैं माननीय सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं। यहां पर कहा गया कि सरकार ने सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया। श्री

मुकेश अग्निहोत्री जी ने विशेषतौर पर इस बात का ज़िक्र किया था। सदन में चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था कि हिमालयन रेजीमेंट के बारे में अभिभाषण में कोई बात नहीं आई है। मैं इस संदर्भ में यह जानकारी देना चाहूंगा कि दिनांक 14-12-2018 को सदन में यह प्रस्ताव पारित किया गया और दिनांक 8-01-2019 को मैंने यह मामला माननीय प्रधानमंत्री जी से उठाया। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से प्रदेश के अधिक युवाओं को भर्ती करने का मामला उठाया था। भारत सरकार के दिशानिर्देशों पर प्रदेश सरकार द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से सेना भर्ती हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के फलस्वरूप मण्डी, पालमपुर में जहां भर्तियां पूरी कर ली गई है। वहां भर्तियों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। यदि में कुछ आंकड़ों के रूप में कहूं तो वर्ष 2016-17 में मण्डी में 287 कुल भर्तियां हुई थी, 2017-18 में 273 और हमारी सरकार आने के बाद वर्ष 2018-19 में भर्तियों का आंकड़ा 273 से बढ़कर 589 पर पहुंच गया है। इसी तरह से पालमपुर में जो भर्तियां हुई उनमें वर्ष 2016-17 में 388, 2017-18 में 752 और अब यह आंकड़ा 752 से भी आगे बढ़कर 1074 पर पहुंचा है। यह एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश है।

07-02-2019/1655 /NS/AG /1

यहां पर इंडस्ट्रियल सैक्टर की बात आई है। मेरे साथी (विपक्ष) कहने लगे कि आपने उद्योग के क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग के क्षेत्र में विस्तार से नहीं जाउंगा। हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल और पॉवर पॉलिसी है, इनको और भी सरल किया जाए। यहां पर जो उद्योगपति निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए हिमाचल प्रदेश आकर्षण का केंद्र बने और इस दृष्टि से हमने कोशिश की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोकसभा के चुनाव के पश्चात बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की जाए और इस मीट में पूरे देश भर से और देश के बाहर से जो भी इन्वेस्टर्ज़ हिमाचल प्रदेश में किसी भी सैक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वे यहां पर आएं। आमतौर पर आज से पहले यह होता था कि इन्वेस्टमैंट

के लिए इस प्रकार की कोशिशें कम होती थी और एक ही सैक्टर में यानी इंडस्ट्री के क्षेत्र में होती थी। हमने इसका बहुत ही holistic view लिया है। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है और टूरिज्म में ईको टूरिज्म, हैल्थ टूरिज्म और स्पोर्टस एक्टिविटीज़ का अलग से स्कोप है। इन सबमें जो भी आदमी अलग-अलग दिशाओं में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको हम हिमाचल प्रदेश में बुलाना चाहते हैं कि वे आएं और काम करें तथा हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से होर्टिकल्चर एक सैक्टर है और इस सैक्टर में आज से पहले इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं करते थे। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास बहुत बड़ी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में फूड प्रोसैसिंग का बहुत बड़ा स्कोप है और इसके साथ-साथ यहां पर कोल्ड स्टोर्ज़ का बहुत बड़ा स्कोप है। हम इस सैक्टर में काम करना चाहते हैं। पिछले कल इस माननीय सदन में सीमेंट प्लांट की बात आई थी। हिमाचल प्रदेश में अगर किसी इंडस्ट्री या सीमेंट प्लांट लगाने की गुंजाइश है तो इस सैक्टर में हमें आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में सीमेंट प्लांट पहले भी लगे हैं। लेकिन विपक्ष वाले मित्र कह रहे हैं कि पर्यावरण खराब होगा। आज हमारे विपक्ष के मित्रों को पर्यावरण की चिंता होने लगी है। मैं कहना चाहता हूं कि आज की इस टैक्नोलोजी में बहुत बड़ा परिवर्तन है। नई टेक्नोलोजी के साथ बड़े-बड़े उद्योग लग रहे हैं और इनमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर पर्यावरण को नुकसान न हो। हम हिमाचल प्रदेश में उन्हीं उद्योगों को लगाएंगे जो पर्यावरण प्रेमी हों और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। अगर हम सीमेंट प्लांट की बात करते हैं तो हम सुनिश्चित करेंगे कि हम कौन-सी तकनीक को इस्तेमाल करेंगे, किस तकनीक से वहां पर पर्यावरण को कम-से-कम नुकसान हो सकता है और उसी को हम अनुमति दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमने हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए फार्मा सैक्टर के बारे में सोच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दौर ऐसा भी है जब माननीय अटल जी ने यहां के लिए एक इंडस्ट्रियल पैकेज़ दिया था तब पूरे देश और दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में प्रवेश हुई थी। हमें इस बात की खुशी है कि पूरे एशिया में नम्बर वन फार्मा इंडस्ट्री का सैक्टर हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थापित है। हमें इसी बात पर संतोष नहीं करना है बल्कि आने वाले समय में हमें आगे और

बढ़ना है तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में और उद्योग आएं तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर "मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना" की बात आई है। इस योजना के अंतर्गत हमने कहा कि यह किसी भी सरकार के लिए संभव ही नहीं है कि हम हरेक बेरोज़गार नौज़वान को यह कहें कि तुम आओ, हम तुम्हें नौकरी देंगे। यह बात न तो हमने चुनाव से पहले कही है और न ही चुनाव के बाद कही है। हमने कहा है कि आओ, हम तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा नौज़वान नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बने। इसलिए हमने एक नई योजना के साथ शुरूआत की है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस योजना को ले करके हमारे पास बहुत सारे सुझाव आए हैं और हम आगे इसे और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नौज़वान आगे आ रहे हैं। इसमें 25 प्रतिशत सबसिडी बेटे को और अगर कोई बेटी इंडस्ट्री लगाना चाहती है तो उसको 30 प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान रखा गया है।

07.02.2019/1700/RKS/DC-1

मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसका परिणाम और भी अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक छोटा-सा प्रदेश है लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत-सी योजनाओं की शुरूआत की है लेकिन यह लोग कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। हमने 'अटल आदर्श विद्या केंद्र' के नाम से एक योजना शुरू की है जिसकी शुरूआत माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हुई है। 'अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती' योजना की शुरूआत माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ जिस स्कूल से मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, जहां से मैंने मैट्रिक की थी, वहां से की है। लेकिन उसके बावजूद भी यह बोला जा रहा है कि यह योजनाएं शुरू ही नहीं हुई है।

जिस तरीके से विपक्ष के लोग इन बातों को कह रहे हैं उससे लगता है कि यह लोग इस प्रदेश में रहते भी हैं या नहीं।

अध्यक्षः अब इस सदन की बैठक आधे घंटे के लिए (5:30 बजे तक) बढ़ाई जाती है।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने नए इनिशिएटिव लिए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'आयुष्मान भारत' की शुरूआत पूरे देश के लिए की है लेकिन हमें ऐसा लगा कि जो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग इस योजना के तहत छूट रहा था उस वर्ग को स्वास्थ्य की सेवाएं देने के लिए या उसे कवर करने के लिए हमने इस हैल्थ योजना को क्लब किया और इसे एक और रूप देकर इसका नाम हिमकेयर रखा। हिमकेयर एक ऐसी योजना है जिसमें पहली बार एक हजार रुपये के प्रीमियम के साथ 5 लाख रुपये का हैल्थ कवरेज हिमाचल में रहने वाले लोगों को मिलेगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 6 मैडिकल कॉलेज चल रहे हैं और यह लोग सभी जगह शोर मचा रहे हैं कि यह सब हमने किया। कागज में होना एक अलग बात है लेकिन किसी चीज़ को जमीन पर खड़ा करना दूसरी बात है। इनका सारा काम कागज पर होता था। यदि कोई नोटिफिकेशन हो गई तो ये उस काम से फारिग हो गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जिला मण्डी में एक मैडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने में भी सफल हुए हैं। इसी तरह मैडिकल कॉलेज, नाहन भी अच्छी तरह से चल रहा है और वहां पर भवन का कार्य बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह चम्बा और हमीरपुर में भी मैडिकल की क्लासिज चल रही है। वहां पर भवन के निर्माण के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है और हम कोशिश करेंगे कि दोनों जगह इसी महीने शिलान्यास करके काम की शुरूआत की जाए। हिमाचल की धरती में AIIMS को जमीन पर खड़ा करने का काम किया गया है तथा इसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके इसका शिलान्यास आदरणीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया गया तथा इसका विधिवत् रूप से भूमि पूजन भी हुआ है। हम इस बात से सहमत है कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाओं को और भी बेहतरीन करने के लिए

जो प्रयास करने की आवश्यकता है वह लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिर भी ऐसा कहना कि कुछ नहीं हुआ है यह गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तिफाक नहीं रखता हूं। इसके साथ-साथ महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिन बातों का जिक्र अपने अभिभाषण के दौरान किया है अब इसके अतिरिक्त हमारा पूर्ण बजट भी यहां पर आएगा। बहुत सारे विषय जो माननीय सदस्यों ने उस तरफ से उठाए हैं वे अधिकांश विषय जब बजट प्रस्तुत होगा और बजट पर चर्चा शुरू होगी उनमें से कुछ उस वक्त के विषय हैं। मैं समझता हूं कि सभी विधायकों के पास एक मौका होता है जब वे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते हैं तो इन चीजों पर बारीकी से ध्यान नहीं दिया जाता है कि कौन सी बात उन्हें बजट पर करनी है और कौन सी बात उन्हें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलनी है। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम जवाब देने के लिए खड़े हैं और मुझे मालूम है कि आने वाले समय में जब बजट प्रस्तुत होगा विपक्ष भी उस समय ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि उनकी यह व्यवस्था है कि वे जितना शोर डालेंगे उतना उनको बड़ा लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शोर करने वाले बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जिनकी आज माननीय सदन में शक्ल दिख रही है। इसलिए मैं उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा शोर डालने की आवश्यकता नहीं है। जो जायज और व्यवहारिक बात होगी उस बात को हम अवश्य सुनेंगे। अगर किसी बात पर हमें लगेगा कि इस पर हमें अमल करना है और यह लागू करने लायक है हम उसे लागू करने के लिए भी तैयार है । जरूरी नहीं कि अच्छा सुझाव सत्ता पक्ष से ही आए, अच्छा सुझाव विपक्ष की ओर से भी आ सकता है। मेरे पास बहुत सारी सूची थी परंतु में इन सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा हूं कि जब आने वाले समय में 9 तारीख को बजट पेश होगा उसके लिए कुछ बातें छोड़ देता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के बजट अभिभाषण को देख रहा था इन्होंने इतनी ज्यादा घोषणाएं की हुई है जो मात्र

कागजों पर ही सीमित रह कर रह गई हैं। एक बजट वर्ष 2017-18 का है जिसमें पैरा संख्या 138 है । इसमें इन्होंने कहा है कि 25 हजार इंडक्शन चुल्हे महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे और इस योजना का नाम "गृह ऊर्जा दक्षता" योजना रखा गया था। अब तक न हमें वह दक्षता मिली और न कोई इस तरह की योजना मिली और न की कोई ऊर्जा मिली। यह सब इनके बजट पर कहा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में हम इनकी ऐसी योजनाओं का जिक्र करेंगे। यदि हमारी सरकार का कार्यकाल पांच वर्ष का पूरा होने वाला होता और हमने जो बातें कहीं हैं वे पूरी न हुई होती तो भी ये लोग विरोध करते। हमारा एक वर्ष का कार्यकाल और उसमें भी बजट में सिर्फ 9 महीने का कार्यकाल बीता है । परंतु विपक्ष यही सुना रहा है कि यह कार्य नहीं हुआ वह कार्य नहीं हुआ। यह बात अच्छी है कि आप हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी कार्य हम करें वह जल्दी करें। हम कोशिश करेंगे कि यह सब कार्य जल्दी हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा इसमें की है। सबने अपनी - अपनी बात को कहा है। अच्छा होता अगर विपक्ष के हमरे साथी भी यहां पर उपस्थित होते। कुछ बातों को हम सुन लेते कुछ बातों को सांझा कर लेते। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना है किसी और दिन हम उन्हें इन बातों को सुनाने का प्रयत्न करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रेदेश में जब हम सत्ता में आए थे उस वक्त आदरणीण प्रधान मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आ करके शफ्त समारोह के चश्मदीद गवाह बने और हमें अपनी शुभकामनाएं भी दीं। मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रह गई। एक साल का सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तो मैंने फिर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी के समक्ष फिर इस बात के लिए आग्रह किया कि आप एक वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में आए थे।

07.02.2019/1710/DT/HK-1

एक साल का कार्यकाल हमारा पूरा हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप फिर से हिमाचल प्रदेश में आएं और हम सब हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए अपनी शुभकामनांए अपना

आशीर्वाद दें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बात को माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारा वह निवेदन स्वीकार किया धर्मशला में आए और वहां आ करके हमको अपना संदेश भी दिया आपनी शुभ कामानएं भी दीं । सरकार की जिन योजनाओं का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं उनमें से कुछ का जिक्र करना हम यहां पर छोड़ रहे हैं। लेकिन हामरे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने एक-एक योजना पर खुले मंच से अपनी बात कही है। हिमाचल प्रदेश को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। आज हिमाचल प्रदेश को ऐसे प्रधान मंत्री की आवश्यकता है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों की पीड़ा को समझते हैं और नजदीकी से समझते हैं। अब छोटी सी बात को अगर में कहूं कि अभी बरसात का मौसम बीता बरसात के मौसम के दौरान हमारे प्रदेश में बाढ़ के कारण नुकसान हुआ एक तरफ बर्फबारी के कारण बहुत बड़ा संकट आया। जब देश के प्रधान मंत्री का फोन आता हमें कितनी खुशी होती है जब वे स्वयं यह कहते हैं कि जो मदद चाहिए वह प्रदान की जाएगी। 22 लोगों को कुल्लू की नदी के बीच में से जहां उनका जीवन खत्म होता दिख रहा था उनको बीच नदी से जिंदा निकाल करके जान बचाने में सफलता हासिल की है। इस कार्य के लिए हैलिकॉप्टर आर्मी के भेजे गए और उन्होंने एक-एक आदमी को जिंदा बचाने में सफल हुए। इसी तरह लाहौल स्पीति में भी 5 फुट बर्फ में लोग फंस गए। लोग गाड़ियों में रह गए लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि इन्हें जिंदा निकालना है। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की उस मदद के लिए 7 हैलिकॉप्टर दिल्ली से भेजे और लाहौल-स्पीति में फंसे हुए 252 लोगों को एयर लिफ्ट करवाया और डालपुर के मैदान में उन्हे उतारा गया। इस तरह से उनके जीवन की रक्षा की गई। सैकड़ों बच्चो चम्बा के हौली और भरमौर में फस गए थे । स्कूल के टुर्नामेंट में भाग लेने के लिए गए थे। रास्ते टूट गए और रास्ता टूटने के कारण वे कठिनाई में आ गए। हमें चिंता थी कि इन बच्चों को कैसे सुरक्षित परिवार के पास पहुंचाया जाए? हमने फिर माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने किसी देरी को किए बिना दो हैलिकॉप्टर भेजे। बच्चों को उठा करके उनके गांव मैं छोड़ करके आए। पिछले कल मै विधान सभा चुनाव क्षेत्र में गया था। वहां जा करके जो हमारा सबसे

कठिन इलाका है जिस इलाके को बड़ा भंगाल कहते हैं वहां पर भी लोग फस गए थे। राशन खत्म हो गया, ऐसी परिस्थिति में अगर लोगों को राशन पहुचाना और लोगों को जिंदा वहां से निकालना , दो बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि वहां भी जा करके हैलिकॉप्टर के द्वारा राशन पहुंचाया गया। राशन पहुंचाने के बाद जो वहां पर बर्फ पर फंसे हुए लोग थे। उनको जिंदा बचाने में भी हम सफल हुए। ऐसे इस प्रकार के प्रयत्न हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि पहले भी संकट आए होंगे और सरकार ने प्रयत्न किए होंगे। लेकिन जितनी संजिदगी के साथ वर्तमान सरकार ने प्रयास किए हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष को सोचने पर विवश होगा और आगे भी इन्हें सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि जो कार्य वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य कर रही है काश हमने भी पूर्व में ऐसे कार्य किए होते। विपक्ष का काम करने का तरीका अलग तरह का था। वे पांच वर्ष तक आराम करते थे और जब पांच साल पूरे होते थे और विदाई का समय आ जाता । और उनकी विदाई भी उसी रूप में हुई है। मैं उस बारे में ज्यादा नहीं जाना चाहता। लोकतांतरिक व्यवस्था में सम्मान करता हूं। हमें हिमाचल प्रदेश की सरकार को जनता ने जो एक अवसर दिया है मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम पूर्ण स्मर्पण के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कार्य कर रहे है। जो हमारा एक वर्ष का समय व्यवस्था बनाने में जो लगना था वह लग चुका है । परंतु आने वाले समय में जो 30 योजनाएं हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की हैं उन योजनाओं को जमीन पर खड़ा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में एक विकास की दृष्टि से आगे बढ़ता हुआ प्रदेश उस तरह से गिनती में नजर आए इस तरह हमने कार्य करने की कोशिश की है।

07/02/2019/1715/RG/HK/1

यह लगना चाहिए और दिखना भी चाहिए, उसके लिए आप सब माननीय सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि के नाते अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता का उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण यहां प्रस्तुत किया है, इसमें सरकार की एक साल की योजनाओं का जिक्र किया गया है और जो योजनाएं बनने के बाद जमीन पर चलनी शुरू हुई हैं, उनका भी जिक्र हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के मित्रों को वह रास नहीं आ रहा है इसलिए उनकी परेशानी जायज़ है और परेशानी की वजह से वे यहां अंदर बैठने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वे जो भी सोचें, वह हमारी चिन्ता का विषय नहीं है, हमारी चिन्ता का विषय हिमाचल प्रदेश के गरीब आदमी की मदद करना, गरीब आदमी के लिए विकास को उनके घरद्वार तक पहुंचाना है और उसको हम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करने के साथ-साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए, मैं सदन से इस बात के लिए आग्रह करुंगा कि इसको हम ध्वनिमत से पारित करें ताकि हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए?

'इस सदन में एकत्रित सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदय का दिनांक 4 फरवरी, 2019 को उन्हें संबोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।'

प्रस्ताव स्वीकार

इससे पूर्व कि मैं सदन की कार्यवाही को 8 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्नन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करूं, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि अभी-अभी दस मिनट पहले आई.जी.एम.सी. से मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि मुझे स्वाईन फ्लु पौजिटिव आया है। तो मैं यह सूचना इसलिए दे रहा हूं कि जो मेरे संसर्ग में आए, वह कृपया प्रिवेंटिव मैडिसिन ले ले

और इनफैक्शन फ्री होने के लिए जितने दिन के विश्राम की मुझे सलाह दी जाएगी, उतने दिन के बाद मैं फिर आपको सत्र में मिलूंगा अन्यथा मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक : 7 फरवरी, 2019 **सचिव।**